



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 24, 1971/श्रावण 2, 1893

No. 30]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24, 1971/SRAVANA 2, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गए विधिक आदेश और अधिसूचनाएँ

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

New Delhi, the 15th July 1971

S.O. 2750.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627, dated 8th March, 1960, the Director-General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 15th August 1971 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in KHAMMAM Telephone Exchange, Andhra Circle.

[No. 5-41/71-PHB(2).]

संचार विभाग

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1971

स्थायी आदेश 2750.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार

डाक-तार महानिदेशक ने खम्मम टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 15-8-71 से प्रमापित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-41/71-पी० एच० बी० (2)]

New Delhi, the 17th July 1971

S.O. 2751.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627, dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 15th August 1971, as the date on which the Measured Rate System will be introduced in JIND Telephone Exchange, Punjab Circle.

[No. 5-42/71-PHB(2).]

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1971

स्थायी आदेश 2751.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने जिन्द टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 15-8-71 से प्रमापित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-42/71-पी० एच० बी० (2)]

S.O. 2752.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules 1951, as introduced by S.O. No. 627, dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs hereby specifies the 16th August 1971 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in CHHINDWARA Telephone Exchange, M.P. Circle.

[No. 5-33/71-PHB(7).]

T. N. MONDAL,

Assistant Director General (PHB).

स्थायी आदेश 2752.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने छिन्दवाड़ा टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-8-71 से प्रमापित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-33/71-पी० एच० बी० (7)]

टी० एन० मंडल,

सहायक महानिदेशक (पी० एच० बी०)।

(P. & T. Board)

New Delhi, the 17th July, 1971

S.O. 2753.—In exercise of the powers conferred by clause (W) of Rule 2 of Indian Telegraph Rules, 1951, the Director-General, Posts and Telegraphs declares that with effect from 1st September, 1971,

(i) The local area of following exchanges shall cover an area within a radial distance of 5 (five) Kms. from the respective telephone exchange.

1. Asansol.
2. Berhampur.
3. Burdwan.
4. Bolpur.
5. Coochbehar.

6. Darjeeling.
7. Jalpaiguri.
8. Kalimpong.
9. Krishnagar.
10. Port Blair.
11. Raniganj and
12. Siliguri.

(ii) The local area of Durgapur Industries shall cover an area within a radial distance of 5 Kms. from the Durgapur Industries Telephone exchange. The demarcating boundary in the south, however, shall be restricted to the river Damodar and in the west by an imaginary line passing through a point at mile 114½ on G.T. Road and at right angles to it.

(iii) The local area of Durgapur Steel shall cover an area within a radial distance of 5 Kms. from the Durgapur Steel telephone exchange. The demarcating boundary in the east, however, shall be restricted to an imaginary line passing through a point at mile 114½ on G.T. Road and at right angles to it.

(iv) The local area of Malda shall cover an area within a radial distance of 5 Kms. from the Malda Telephone exchange. The demarcating boundary in the west and the south, however, shall be restricted to the river Mahananda.

[No. 3-18/70-PHB.]

K. R. NAYAR,

Director of Phones (E).

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1971

एस० ओ० 2753.—1951 के भारतीय तार नियमावली के नियम 2 के खण्ड (डब्ल्यू) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक-तार महानिदेशक घोषित करते हैं कि 1-9-1971 से :-

(i) निम्नलिखित टेलीफोन एक्सचेंजों का स्थानीय क्षेत्र सम्बन्धित एक्सचेंज से 5 (पांच) किलोमीटर के भीतर की श्रृंखला दूरी वाला क्षेत्र होगा।

- | | | |
|-------------|---------------|------------------|
| 1. आसनोल | 5. कूचबिहार | 9. कृष्णागर |
| 2. बरहामपुर | 6. दार्जिलिंग | 10. पोर्ट ब्लेयर |
| 3. बर्दवान | 7. जलपाइगुड़ी | 11. रानीगंज तथा |
| 4. बोलपुर | 8. कालिगपोंग | 12. सिलीगुड़ी |

(ii) दुर्गापुर उद्योग का स्थानीय क्षेत्र दुर्गापुर उद्योग टेलीफोन एक्सचेंज से 5 कि० मी० के भीतर की श्रृंखला दूरी का क्षेत्र होगा। किन्तु दक्षिण में उसकी सीमा दामोदर नदी तक तथा पश्चिम में उस काल्पनिक लाइन तक सीमित होगी जो कि जी० टी० रोड पर 114-1/2 मील के पत्थर से समकोण बनाती हुई गुजरे।

(iii) दुर्गापुर इस्पात का स्थानीय क्षेत्र दुर्गापुर इस्पात टेलीफोन एक्सचेंज से 5 कि० मी० के भीतर की श्रृंखला दूरी वाला क्षेत्र होगा। किन्तु पूर्व में उसकी सीमा उस काल्पनिक लाइन तक सीमित होगी जो कि जी० टी० रोड पर 114 1/2 मील के पत्थर से समकोण बनाती हुई गुजरे।

(iv) मालदा का स्थानीय क्षेत्र मालदा टेलीफोन एक्सचेंज से 5 कि० मी० के भीतर की श्रृंखला दूरी वाला क्षेत्र होगा। किन्तु पश्चिम व दक्षिण में उसकी सीमा महानन्दा नदी तक सीमित होगी।

[सं० 3-18/70-पी०एच०बी०]

के० आर० नायर, निदेशक फोन (ई)।

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 1st July 1971

S.O. 2754.—In pursuance of the rule 8 of the Export of Safety Class (Inspection) Rules 1969, the Central Government hereby makes the following amendments to the Notification of the Government of India, in the late Ministry of Foreign Trade & Supply No. S.O. 1857 dated the 17th May 1969, namely:—

In the said notification, in the Table—

(i) for item 1 of the entry under column (2) against serial No. 2. Export Inspection Agency, Bombay, the following shall be substituted, namely—

“1. Shri V.R. Bhide, M/s. Kangan Pvt. Ltd., 208, Lady Jamshedji Road, Bombay-28.
.. .. . Chairman.”

(ii) after item 3 of the entry under column (2) against serial No. 3. Export Inspection Agency, Delhi, and the entry relating thereto the following serial number and entry shall be inserted namely—

“4. Development Officer (Glass) .. Ex-officio Directorate General of Technical Development, (Ministry of Industrial Development), Udyog Bhavan, New Delhi-11.”

(iii) for item 4 of the entry under column (2) against serial number 3. Export Inspection Agency, Delhi and the entry relating thereto the following serial number and entry shall be inserted, namely—

“5. Deputy Director .. Ex-officio Export Inspection Council, 6B/9, Northern Extension Area, Rajinder Nagar, New Delhi-60 Convener.”

(iv) for item 5 of the entry under column (2) against serial No. 4. Export Inspection Agency, Madras & Cochin the following shall be substituted, namely:—

“5. Branch Manager, .. Ex-officio The State Trading Corporation of India Ltd., 123, Mount Road, Madras-6.

(v) for item 6 of the entry under column (2) against serial No. 4. Export Inspection Agency, Madras and Cochin, the following shall be substituted, namely:—

“6 Joint Director, Export Inspection Council, Manohar Building, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam, Cochin-11. Convener.”

[No. 60(58)/Exp. Insp/68.]

M. K. B. BHATNAGAR, Dy. Director,
(Export Promotion).

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जुलाई 1971

एस० आ० 2754.—निरापद कांच का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार और पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1857 तारीख 7 मई, 1969 में एत द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में—

(i) क्रम संख्या 2 निर्यात निरीक्षण, अधिकरण, मुम्बई के सामने स्तम्भ (2) के नीचे की प्रविष्टि की मद 1 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“1. श्री वी० आर० भिडे,

मैसर्स कंगन, प्राइवेट लिमिटेड

208, लेडी जमशेदजी रोड,

मुम्बई-28

...

...

...

अध्यक्ष।”

(ii) क्रम संख्या 3 निर्यात निरीक्षण अभिकरण दिल्ली के सामने स्तम्भ (2) के नीचे की प्रविष्टि की मद 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“4. विकास अधिकारी काच तकनीकी विकास महानिदेशालय, (शैक्षणिक विकास मंत्रालय) उद्योग भवन, नई दिल्ली-11” पदेन

(iii) क्रम संख्या 3 निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली के सामने स्तम्भ (2) के नीचे की प्रविष्टि की मद 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“5. उन निदेशक पदेन
निर्यात निरीक्षण परिषद्,
6 बी/9, नार्दन एक्स्टेंशन एरिया,
राजेन्द्र नगर,
नई दिल्ली-60 सयोजक”

(iv) क्रम संख्या 4 निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मद्रास और कोचीन के सामने स्तम्भ (2) के नीचे की प्रविष्टि की मद 5 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“5. शाखा प्रबन्धक, पदेन
दी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड,
123, माउन्ट रोड,
मद्रास-6”

(v) क्रम संख्या 4 निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मद्रास और कोचीन के सामने स्तम्भ (2) के नीचे की प्रविष्टि की मद 6 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“6. संयुक्त निदेश,
निर्यात निरीक्षण परिषद्,
मनोहर विलि बिल्डिंग,
महात्मा गांधी रोड,
एरनाकुलम,
कोचीन-11 सयोजक”

[स० 60(58)/68-नि०नि०]

एम० के० बी० भटनागर,

उप निदेशक, (निर्यात प्रवृत्ति) ।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

ORDER

New Delhi, the 6th July 1971

S.O. 2755.—IDRA/5/71.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rule 8 of the Central Advisory Council (Procedural) Rules 1952, the Central Government hereby appoints Dr. A. M. Khusro to be member of the Central Advisory Council of Industries till the 4th March, 1972, in place of Prof. P. N. Dhar, and directs that the following amendment shall be made in the order of

the Government of India in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 971, dated the 5th March, 1970 as amended *vide* No. S.O. 1367, dated the 9th April, 1970, namely :—

In the said Order, for the entry No. 19 relating to Prof. P. N. Dhar, the following entry shall be substituted:—

“19. Dr. A. M. Khusro Director, Institute of Economic Growth University Enclave, Delhi-7.”

[No. 1(3)/Lic.Pol./69.]

R. C. SETHI, Dy. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1971

का० आ० 2755/आई० डी० आर० ए०/5/71.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951का 65) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवम् केन्द्रीय सलाहकार परिषद् कार्यविधि) नियम, 1952 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा डा० ए० एम० खुसरो को प्रो० पी० एन० धर के स्थान पर 4 मार्च, 1972 तक के लिए केन्द्रीय सलाहकार परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है और यह निदेश देती है कि भारत सरकार के औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 971 दिनांक 5 मार्च, 1970 में, जिसे आदेश सं० का० आ० 136 दिनांक 9 अप्रैल, 1970 के द्वारा संशोधित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, प्रो० पी० एन० धर से सम्बन्धित प्रविष्टि सं० 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी।

“19. डा० ए० एम० खुसरो,
निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान,
यूनिवर्सिटी इन्वलेय, दिल्ली - 7.

[सं० 1 (3)/एल० पी०/69]

आर० सी० सेठी, उप-सचिव।

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 7th July 1971

S.O. 2756 IDRA/6/8/71.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with rules 5 and 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints till the 5th November, 1971, Shri M. Subramanian, Assistant Development Officer (Fertiliser), Directorate General of Technical Development, New Delhi, in place of Shri N. R. Srinivasan, Development Officer (Fert.) Directorate General of Technical Development, New Delhi, as a member of the Development Council established by Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industrial Development, Internal Trade & Company Affairs

(Deptt. of Industrial Development) No. IDRA/6/4/69 dated the 6th November, 1969, for the scheduled industries engaged in the manufacture or production of Inorganic Chemicals and directs that the following amendment shall be made in the said Order, namely:—

In the said Order, for entry No. 27 relating to Shri N. R. Srinivasan, Development Officer (Fertiliser), Directorate General of Technical Development, New Delhi, the following entry shall be substituted, namely:—

“27. Shri M. Subramanian, Assistant Development Officer, (Fertilisers), Directorate General of Technical Development, New Delhi.”

2. Shri M. Subramanian, Assistant Development Officer (Fertilisers) Directorate General of Technical Development, New Delhi, is hereby appointed to carry on the functions of the Secretary to the said Development Council.

[No. 13(15)/69-LC.]

D. C. VAISH, Under Secy.

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1971

का० आ० 2756/आई० डी० सार० ए०/6/8/71.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्स विकास परिषद् (कार्यविधि) नियम, 1952 के नियम 5 और 8 के साथ पढ़ते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एम० सुब्रह्मण्यन, सहायक विकास अधिकारी (उर्वरक) तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली को श्री एन० आर० श्रीनिवासन, विकास अधिकारी (उर्वरक) तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली के स्थान पर 5 नवम्बर, 1972 तक की अवधि के लिये भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० आई० डी० आर० ए०/6/4/69 दिनांक 6 नवम्बर, 1969 के आदेश द्वारा स्थापित अकार्वनिक रसायन के निर्माण अथवा उत्पादन रत अनुसूचित उद्योगों की विकास परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है और यह निदेश देती है कि उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, श्री एन० आर० श्रीनिवासन, विकास अधिकारी (उर्वरक) तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली, से संबंधित प्रविष्टि संख्या 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखा जाएगी, अर्थात् :—

“27. श्री एम० सुब्रह्मण्यन, सहायक विकास अधिकारी (उर्वरक), तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली।”

2. एतद्वारा श्री एम० सुब्रह्मण्यन, सहायक अधिकारी (उर्वरक), तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली, को उक्त विकास परिषद् के सचिव के कार्यों को करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

[सं० 13 (15)/69-एल०सी०]

डी० सी० वैश, अधर सचिव।

ORDER

New Delhi, the 14th July 1971

S.O. 2757/IDRA.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central

Government hereby appoints, for a period of two years with effect from the date of this Order, the following persons to be members of the Development Council for the scheduled industries engaged in the manufacture or production of Food Processing Industries in place of members appointed under the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) Order No. S.O. 680/IDRA, dated the 8th February, 1968, as amended from time to time, whose term of office has expired by efflux of time or otherwise:—

DEVELOPMENT COUNCIL FOR FOOD PROCESSING INDUSTRIES

Chairman

1. Shri R. Ramaswamy, President, Protein Foods Association of India, 28/6, Chemiers Road, Adyar, Madras.

Members

2. Shri P. Mohanlal, M/s. Parle Products Private Limited, Belvandi House, 254-B, Dr. Annie Besant Road, Bombay-25.
3. Shri A. Bose, M/s. Lily Biscuit Company Private Limited, 3. Rama Kanta Sen Lane, Ultadanga, Calcutta-4.
4. Shri Jayant Vithaldas, M/s. Wallace Flour Mills Company Limited, 9, Wallace Street, Fort, Bombay-1.
5. Shri P. R. Ramakrishnan, Chairman, M/s. Jeypore Sugar Company Limited, Rayagada, Koreput District (Orissa State).
6. Lala Bansidhar, M/s. Daurala Sugar Works, Daurala, Meerut (Uttar Pradesh).
7. Dr. V. Kurien, M/s. Kaira District Cooperative Milk Producers Union Limited, Anand (Gujarat).
8. Shri N. J. Chacko, M/s. Kerala Food Packers, P.O. Box No. 66, Alleppey (Kerala).
9. Shri M. A. Wadud, M/s. Tata Oil Mills Company Limited, Bombay House, Bruce Street, Fort, Bombay-1.
10. Shri Ranjit Rai, M/s. Sun Sip Limited, Bernighat, Meghalaya.
11. Shri Ritendra Mohan Datta, President, District Congress Committee, P.O. Dubri, Assam.
12. Shri A. V. Mody, M/s. Unichem Laboratories Limited, C-32, Industrial Area, Meerut Road, Ghaziabad (Uttar Pradesh).
13. Shri V. B. Oberoi, M/s. Klissan Products Limited, Old Madras Road, Bangalore-16 (Mysore).
14. Shri Shamsuddin Ahmed, R.L.B. Advocate, P.O. Silchar, Cachar, Assam.
15. Shri J. R. L. Pountney, Managing Director, M/s. Hindustan Milkfood Manufacturers Limited, Nabha (Punjab).
16. Shri Sujir Ganesh Nayak, Quilon, Kerala.
17. Sardar Daljit Singh, M/s. Pure Drinks (Private) Limited, Connaught Place, New Delhi.
18. Shri H. N. Kapadia, M/s. Poysa Industrial Company Limited, Tiecicon, Dr. E. Moses Road, Bombay-11 B.C.
19. Dr. H. A. B. Parpia, Director, Central Food Technological Research Institute, Chelluvamba Mansion, Mysore.
20. Dr. C. Gopalan, National Nutrition Laboratory, Hyderabad.
21. Dr. P. K. Kymal, Director, Ministry of Agriculture (Department of Food), New Delhi.
22. Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Agriculture, Nagpur.
23. Dr. K. Bagchi, Secretary, Central Committee for Food Standards, Ministry of Health and Family Planning, New Delhi.
24. A representative of the Indian Standards Institution.
25. A representative of the Development Commissioner (Small Scale Industries).
26. Shri N. K. Seth Director, Ministry of Industrial Development, New Delhi.
27. Shri S. Ramaswamy, Officer on Special Duty (Food), Directorate General of Technical Development, New Delhi.

Shri S. Ramaswamay, Officer on Special Duty, Directorate General of Technical Development, New Delhi is hereby appointed to carry on the functions of Secretary to the said Development Council.

[No. 1(39)/69-LI&PF.]

K. M. RAJPAL, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1971

का० प्र० 2757 आई० डी० आर० ए०.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवम् विकास परिषद् (कार्यविधि) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पढ़ते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस आदेश की तिथि से दो वर्षों तक की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को भूतपूर्व औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 680/आई० डी० आर० ए०/दिनांक 8 फरवरी, 1968, के अधीन नियुक्त किये गये सदस्यों के स्थान पर जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, जिनका कार्यकाल समय के व्यतीत होने अथवा अन्यथा द्वारा समाप्त हो गया है, खाद्य परिष्करण उद्योग के निर्माण अथवा उत्पादनरत अनुसूचित उद्योगों की विकास परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है :—

खाद्य परिष्करण उद्योग की विकास परिषद्

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (1) श्री आर० रामास्वामी,
अध्यक्ष,
प्रोटीन फूड्स एसोसियेशन आफ इण्डिया,
28/6, चेमर्स रोड, अड्यार, मद्रास । | अध्यक्ष |
| (2) श्री पी० मोहनलाल,
मे० पार्ले प्रोडक्ट्स प्रा० लि०,
बेलबंडी हाउस, 254-बी, डा० एनीबेसन्ट रोड,
बम्बई-25 । | सदस्य |
| (3) श्री ए० बोस,
मे० लिली बिस्कुट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड,
3, रमाकान्तसेन लेन,
उल्टाडांगा, कलकत्ता-4 । | सदस्य |
| (4) श्री जयंत विठ्ठलदास,
मे० बालिश फलवर मिल्स कम्पनी लि०,
9, बालिश स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-1 । | सदस्य |
| (5) श्री पी० आर० रामकृष्णन्,
अध्यक्ष,
मे० जयपुर सुगर कम्पनी लि०,
रायगाड़ा, कोरेपुर जिला,
झड़ीसा (राज्य) । | सदस्य |

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (6) लाला बंशीधर,
मे० धौराला सुगर वर्क्स,
दौराला, मेरठ (उत्तर प्रदेश) | सदस्य |
| (7) डा० बी० कुरियन,
मे० कैरा डिस्ट्रिक्ट कोओपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स,
यूनियन लिमिटेड, आनन्द (गुजरात) । | सदस्य |
| (8) श्री एन० जे० चाके,
मे० केरल फूड पैकर्स,
पो० आ० बा० सं०-66,
एलेप्पी (केरल) । | सदस्य |
| (9) श्री एम० ए० बद्द,
मे० तारा आयल मिल्स कम्पनी लि०,
बम्बई हाउस, क्रुस स्ट्रीट,
फोर्ट, बम्बई-1 । | सदस्य |
| (10) श्री रणजीत राय,
मे० सनसिप लि०, बोनो घाट,
मेघालय । | सदस्य |
| (11) श्री रितेन्द्र मोहन दत्ता,
अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी,
पो० आ० दुबरी, आसाम । | सदस्य |
| (12) श्री ए० बी० मोदी,
मे० पूनीकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड,
सी-32, इण्डस्ट्रीयल एरिया,
मेरठ रोड, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) । | सदस्य |
| (13) श्री बी० बी० ओवेराय,
मे० किसान प्राइवट्स लिमिटेड,
ओल्ड मद्रास रोड,
बंगलौर-16, (मैसूर) । | सदस्य |
| (14) श्री शम्सुद्दीन अहमद, आर० एल० बी०,
एडवोकेट, पो० आ० सिलचर,
कछार (आसाम) । | सदस्य |
| (15) श्री जे० आर० एल० पौन्टनी,
प्रबंधन-निदेशक,
मे० हिन्दुस्तान मिल्कफूड मैनुफैक्चरर्स लि०,
नाभा (पंजाब) । | सदस्य |
| (16) श्री सुरजीर गणेशनायक,
क्विलोन, केरल । | सदस्य |

- (17) सरदार दलजीत सिंह, सदस्य
मे० ग्योर ट्रिन्वस (प्राइवेट) लिमिटेड
कनाट प्लेस,
नई दिल्ली ।
- (18) श्री एन० एन० कापड़िया, सदस्य
मे० पोयशा इण्डस्ट्रियल कं० लिमिटेड,
टिड्सिकन, डा० इ० मोसेज रोड,
बम्बई-11, बी० सी० ।
- (19) डा० एच० ए० बी० परपिया, सदस्य
निदेशक,
केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान,
चेल्लुवाम्बा मैसान,
मैसूर ।
- (20) डा० सी गोपालन्, सदस्य
मे० राष्ट्रीय पोषण प्रयोगशाला,
हैदराबाद ।
- (21) डा० पी० के० किमल,
निदेशक,
कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग),
नई दिल्ली ।
- (22) कृषि सम्बन्धी निपटान सलाहकार,
कृषि मंत्रालय, नागपुर ।
- (23) डा० के० बाजोही,
सचिव,
खाद्य मानक की केन्द्रीय समिति,
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
- (24) भारतीय मानक संस्था का एक प्रतिनिधि ।
- (25) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का एक प्रतिनिधि ।
- (26) श्री एन० के० सेठ,
निदेशक, औद्योगिक विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
- (27) श्री एस० रामास्वामी,
विशेष कार्य अधिकारी (खाद्य),
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

श्री एम० रामस्वामी, विशेष कार्य अधिकारी, तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली, को उक्त विकास परिषद् के सचिव के कार्यों को करने के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है ।

[सं० । (39)/69-एल०आई०एण्ड०बी० एम०]

के० एम० राजपाल, अवर सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 30th June 1971

S.O. 2758.—In pursuance of section 106 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby publishes the Order, pronounced on the 21st May, 1971 by the High Court of Judicature at Bombay, Nagpur Bench, Nagpur, in Election Petition No. 2 of 1971.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY, NAGPUR BENCH,
NAGPUR

ELECTION PETITION No. 2 OF 1971

Krishna Kumar, son of Madhaorao Bhajikhaya, occupation service, resident of Ward No. 9, Yeotmal, Taluq and District Yeotmal and another.—*Petitioners.*

Versus

1. Shri Deosthale, Collector, Yeotmal, Returning Officer for Yeotmal Parliamentary Constituency, representing the Chief Election Commissioner of India and 5 others—*Respondents.*

In the matter of Election Petition

Under Section 81 of the Representation of the People Act, 1951.

M/s. S. N. Kherdekar and V. P. Kukday, Advocate for the Petitioners.

(Coram: Chandurkar, J.)

Friday, May 21, 1971

Oral Judgment

This is an election petition filed by the two petitioners challenging the election of respondent No. 2 Sadashiorao Bapuji Thakare, who was elected as a member of the Lok Sabha from the Yeotmal Parliamentary Constituency. Admittedly the respondent No. 2 was declared to have been elected by the Returning Officer on March 10, 1971, Under section 81 of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as the Act), an election petition has to be presented within 45 days from but not earlier than the date of election of the returned candidate.

Under Section 67-A of the Act, the date of election is the date on which a candidate is declared by the Returning Officer under the provisions of section 53 to be elected to a House of Parliament. In the instant case, it is not disputed that the date of election as contemplated by section 67-A and under section 81 of the Act is March 10, 1971. The election petition should, therefore, have been filed within a period of 45 days from March 10, 1971. The petition was, however, filed on April, 26, 1971, and admittedly it has therefore, been filed beyond the period of 45 days prescribed by section 81 of the Act. Such an election petition is liable to be rejected in view of the provisions of section 86 of the Act, which provides that the High Court shall dismiss an election petition which does not comply with the provisions of section 81 or section 82 or section 117.

Both the petitioners are present in person and are represented by Mr S. N. Kherdekar and Mr. V. P. Kukday, Advocates. Both the petitioners have filed an application under their signatures and counter-signed by their counsel Mr. Kukday stating that the petition came to be filed on the 47th day and is barred by limitation and was, therefore, liable to be rejected as being barred by limitation. They have also stated in the application that the requirement that necessary copies of the petition should be filed has also not been complied with and that the petition

was also formally defective as persons who had withdrawn their nominations could not be made parties for want of intimation. They have, therefore, prayed for permission to withdraw the petition.

No question of any withdrawal of the petition arises in this case. The petition is really barred by limitation having been filed after the period of 45 days prescribed by section 81 and it is conceded that it is barred by limitation. The petition must, therefore, be rejected as barred by limitation. None of the opposite parties have been noticed in the instant case as this is the first date of hearing and the objection with regard to limitation raised by the office is conceded to be correct by the petitioners. The petitioners, therefore, entitled to refund of their security deposit.

The result is that the petition is rejected as barred by limitation and the security deposited shall be refunded to the petitioners.

By the Court,

(Sd.) M. B. DIWATE,
Jnd Addl. Special Officer

[No. 82/MT/2(Nagpur)/71.]

By Order,
A. N. SEN, Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 5th July 1971

S.O. 2759.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (g) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) the Central Government hereby appoints Shri B. G. Fernandes Town and Country Planner, Town and Country Planning Organisation, as a member of the Delhi Development Authority in place of Shri C. S. Gupte and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. 12-173/57-LSG, dated the 30th December, 1957, namely:—

In the said notification, in item 10-A, for the entry "Shri C. S. Gupte" the following entry shall be substituted, namely:—

"Shri B. G. Fernandes".

[No. 5-2-69-UDI]

L.M. SUKHWANI, Under Secy.

New Delhi, the 9th July 1971

S.O. 2760.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Rehabilitation (Department of Works and Housing) S.O. No. 1533, dated the 28th May, 1963, namely:—

In the said notification, in item (2), after the words 'Municipal Corporation of Calcutta' the words 'and Howrah Municipality' shall be inserted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of August, 1971.

[No. F. 12033(2)/71-Pol(II).]

P. N. KHANNAH,
Dy. Director of Estates & *ex-officio* Under Secy.

निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्रालय

(सम्पदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 9 जुलाई 1971

का० अ० 2760.—राष्ट्रपति, मूल नियमों के नियम 45 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय (निर्माण तथा आवास विभाग) की तारीख 28 मई, 1963 की अधिसूचना संख्या का० अ० 1533 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्—

1. उक्त अधिसूचना में सद (2) में 'कलकत्ता नगर निगम' शब्दों के पश्चात् "और हावड़ा नगरपालिका" शब्द अन्तः स्थापित किये जायेंगे।

2. यह अधिसूचना 1971 के अगस्त के पहले दिन प्रवृत्त होगी :

[सं० एक० 12033(2)/71 नीति(2)]

प्राण नाथ खन्ना,

सम्पदा उप निदेशक तथा पदेन

अवर सचिव।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 6th July 1971

S.O. 2761.—In pursuance of the sub-section (5) of section 5 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947), the Central Government hereby publishes the following estimates of receipts and expenditure from the general welfare account of the Coal Mines Labour Welfare Housing and General Welfare Fund during the year 1970-71 together with a statement of accounts for the year 1969-70 and a report on the activities financed during that year from the general welfare account of the said Fund, namely:—

PART I

ESTIMATES OF RECEIPTS AND EXPENDITURE DURING 1970-71

General Welfare Account

Receipts
Rs. 2,42,33,900/-

Expenditure
Rs. 2,94,48,600/-

PART II

STATEMENT OF ACCOUNT FOR 1969-70

General Welfare Account

	Receipts Rs.	Expenditure Rs.
Opening balance on 1st April, 1969	1,64,75,222	
Expenditure on General Welfare Account during the year	..	3,27,80,564
Receipts during the year	2,40,14,830	..
Closing balance on 31st March 1970	..	77,09,488
	404,90,052	4,04,90,052

(Provisional figures).

PART III

1. *Medical Facilities:*

(a) *Hospitals.*—The two Central Hospitals at Dhanbad and Asansol and 12 Regional Hospitals situated in the different parts of various coalfields continued to function during the year under report. The bed strength of the Central Hospital, Dhanbad, is 300 and that of the Central Hospital at Asansol 350. The proposal to raise the bed strength of the two Central Hospitals to 400 beds each was kept in abeyance due to paucity of funds. The construction work of the 100 bedded Central Hospital at Manendragarh with an attached 50 bedded T.B. Wing was completed. The hospital was opened on the 19th September, 1970.

(b) *Dispensaries.*—One Static Dispensary at Mugma in Jharia Coalfield, two Mobile Medical units one each at Assam and Pench Valley Coalfields and 30 Ayurvedic Dispensaries at various coalfields rendered service during the period under report. For the manufacture of the genuine medicines required for the use at the Ayurvedic Dispensaries, an Ayurvedic Pharmacy set up at Patherdih in Jharia Coalfield continued to function during the year under report.

(c) *Family Welfare, Maternity and Child Welfare Centre.*—Family Welfare Centre attached to each of the Regional Hospitals continued to function during the year under report. Besides, 8 such centres already established in the various coalfields were also functioning as independent units, each under the charge of a qualified Lady Health Visitor. In addition, 53 Maternity and Child Welfare Centres were being run by the Asansol, Jharia and Hazaribagh Mines Board of Health for which the Coal Mines Labour Welfare Organisation (hereinafter referred to as the Organisation) continued to pay grant-in-aid towards their maintenance. For the benefit of the colliery workers in the Chanda Coalfield, the block attached to the Government Hospital Chanda, continued to function during the year under report.

(d) *Financial assistance for improving Dispensary Services.*—With a view to encourage the colliery managements for improving the standard of dispensary services at the collieries for the benefit of the colliery workers and their dependents, the scheme for the payment of grant-in-aid was continued and a sum of Rs. 13,56,013.00 was paid during the year. Further, in order to give incentive to colliery managements to establish new dispensaries or to improve the existing dispensary services for the benefit of the workers employed by them, the Organisation had introduced a scheme of financial assistance in the form of payment of interest free loans equivalent to actual cost of construction or improvement of existing building for the dispensaries including purchase of equipment subject to the maximum of 16 times of the annual grant-in-aid. Under this scheme a sum of Rs. 1,63,000.00 was paid to the colliery managements.

(e) *Anti T.B. Measures.*—Besides the 262 beds provided by the Fund (12 at Katras, 100 each at Dhanbad and Asansol and 50 at Searsole) 61 beds were reserved in various T.B. Sanatoria for the treatment of colliery workers and their dependents suffering from T.B. Construction of a T.B. Clinic with 30 beds at Ramagundam was completed. The scheme of domiciliary T.B. Treatment continued to function during the year under report and payment of diet and subsistence allowances to the T.B. patients who were undergoing treatment under this scheme were also continued to be made according to schedule.

(f) *Family Planning Services.*—Free advice on family planning continued to be given and contraceptive supplied free of cost at the fund's Hospitals and at the clinics opened for the purpose at some rural and urban areas. The scheme for the payment of grant-in-aid to the colliery owners for the family planning work continued to be in force. 5 Static Family Planning Units and 3 Mobile Family Planning Units remained in operation. In addition, the Maternity and Child Welfare Centres numbering 53 run by the Jharia, Asansol and Hazaribagh Mines Board of Health in different parts of respective coalfields for which the Organisation has been paying grant-in-aid also provided facilities for family planning services for the benefit of the colliery workers and their dependents in those areas.

(g) *Rehabilitation.*—A Rehabilitation-cum-Physiotherapy Centre attached to each of the Central Hospitals at Dhanbad and Asansol, continued to function. The work on construction of the Rehabilitation-cum-Convalescent Home at Sidhabari was completed. The construction work for establishment of a Rehabilitation Centre at Chhindwara and the construction of residential and non-residential buildings were in progress.

(h) *Other activities.*—Other important activities of the Organisation on the medical and public health sides were giving facilities for the treatment of Cancer, Leprosy and Mental Cases, running of Blood Bank at both the Central Hospitals at

Dhanbad and Asansol, maintenance of Ambulance Vans, free supply of spectacles and dentures, establishment of Malaria Control Operations and Anti-malaria Measures.

2. Educational and Recreation Facilities :

(a) Some relevant Statistics highlighting the activities on this account are given below—

(i) Multipurpose Institute	—62	
(ii) Welfare Centre for Women	64	
(iii) Adult Education Centres	66	
(iv) Feeder Adult Education Centres	163	
(v) Scholarship to the children of colliery workers	500	General and 22 technical scholarships are awarded every year in addition to renewal of scholarships awarded during the previous years.
(vi) Boarding Houses for children	3	Besides, 30 seats were reserved at the Lahiri MPHS at Chirimiri.
(vii) Holiday Home	3	

(b) *Games and Sports*.—During the year, for organising games and sports a sum of Rs. 1,85,466.00 was sanctioned. The more important events are listed below:—

(i) *The 9th All India Coalfield Sports*.—The 9th All India Coal Field sports were held at Gandhi Stadium, Kustore Colliery on the 7th and 8th March, 1970 with great enthusiasm and splendour. The West Bengal Coalfield Team retained the Coalfield Championship and the Jharia Coalfield Team was the runners-up. Moira Colliery won the individual Championship. Teams from West Bengal, Jharia, Hazaribagh, Orissa, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Maharashtra Coalfields participated in the Sports.

(ii) *All-India Coalfields Football Tournament*.—The Central meet of the tournament was held at the Central Sounda Colliery in Hazaribagh Coalfield between the West Bengal and Jharia Coalfields Teams on 18th February 1970 in which the Jharia Coalfields won the tournament. Teams from West Bengal, Jharia, Hazaribagh, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Orissa Coalfield participated in the tournament.

(c) *Bharat Darshan Special Train*.—With a view to contributing to better National Integration and enhancement of the feeling of the fellowship and team work amongst the workers employed in the Coal Mining Industry, the Organisation run Special Trains taking the workers to the various projects undertaken by the Government of India and also places of religious, historical and cultural importance.

The 12th Bharat Darshan Yatra Train with 500 colliery workers left for the North India on the 6th September, 1969 and after visiting several places, like Varanasi, Lucknow, Hardwar, Bhakra-Nangal, Delhi, Agra, Bombay and Allahabad returned to Dhanbad on the 22nd September 1969.

3. Water Supply:

(a) A brief review of the progress made in respect of the various water supply schemes in the different coalfields during the year under report is furnished below:—

Name of Coalfield	Name of Colliery	Particulars	Value of the Scheme
			Rs.
Bihar Coalfield	(i) Muralidih 21/22/Pits Colliery.	Scrutinised and technically sanctioned.	89,890.00
	(ii) Mondal's Belbera Colliery	Technically sanctioned.	1,49,918.00
	(iii) Jamadoba Colliery	Technically Sanctioned.	9,32,168.25
	(iv) Sijua Bhelatand Colliery.	Scrutinised and technically sanctioned.	7,82,700.00
	(v) Malkera Colliery	Do.	3,43,606.00

1	2	3	4
West Bengal Coal-field	(i) Kunustoria Colliery .	Scrutinised and technically sanctioned.	1,44,686.00
	(ii) Bankola 1/2 Pits Colliery	Do.	1,76,549.00
	(iii) Bankola 3/4 Pits Colliery.	Do.	1,44,327.00
	(iv) Bankola Centenary.	Do.	75,841.00
	(v) Krishnanagar Colliery. .	Technically sanctioned.	97,928.00
	(vi) Parasia Colliery.	Do.	2,63,938.00
	(vii) Saltora Colliery. .	Do.	1,97,170.00
Madhya Pradesh Coalfield.	Burhar Colliery. . .	Prepared and technically sanctioned.	1,57,992.00
Orissa Coalfield	Hingir Rampur Colliery. .	Designed and technically sanctioned.	1,55,966.00

An amount of Rs. 48,50,496 was paid as financial assistance during the year for implementation for water supply schemes in different coalfields.

(b) *Sinking of wells*.—14 wells, under the scheme of 50 per cent subsidy, were sunk bringing the total number of wells so far completed to 234. A sum of Rs. 39,925.00 was paid as subsidy to the mine owners for sinking of wells in different coalfields during the year under report.

4. Co-operative Movement Organisation:

The total number of primary Co-operative stores and Credit Societies of colliery workers remained at 587. A drive was launched to collect the outstanding dues advanced as loans to the Central Co-operative Stores with utmost speed. A sum of Rs. 16,92,163.00 was collected during the year from various Central Co-operative Stores. Most of the Central Co-operative Stores which had sustained losses in the preceding years showed profit during the year under report.

[No. 14/45/70-MIL.]

C. R. NAIR, Under Secy.

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1971

का० आ० 2761—कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 5 उपधारा (5) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 1969-70 वर्ष के लेखाओं के विवरण और कोयला खान श्रम कल्याण आवास और साधारण कल्याण निधि के साधारण लेखा में से उस वर्ष के दौरान वित्त घोषित क्रिया कलापों की रिपोर्ट के साथ वर्ष 1970-71 के दौरान उक्त निधि के साधारण कल्याण लेखा में की की प्राप्तियों और उसमें के व्यय के निम्नलिखित प्राक्कलन एतद्द्वारा प्रकाशित करती है, अर्थात्:—

भाग 1

1970-71 के दौरान प्राप्तियों और व्यय के प्राक्कलन
साधारण कल्याण लेखा

प्राप्तियां

व्यय

रु०

रु०

2,42,33,900

2,94,48,600

भाग 2

1969-70 के लेखाओं का विवरण

साधारण कल्याण लेखा

प्राप्तियां	व्यय
रु०	रु०
1 अप्रैल, 1969 को	1,64,75,222/-
अथशेष	
वर्ष के दौरान साधारण	
कल्याण सेवा में	3,27,80,564
का व्यय	
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	2,40,14,830/-
31 मार्च, 1970 को इतिशेष	77,09,488
कुल	4,04,90,052 4,04,90,052

(अन्तिम आंकड़े)

भाग—3

1 चिकित्सा प्रसुविधाएं

(क) अस्पताल—धनबाद और आसनसोल के दोनों अस्पताल और विभिन्न कोयला क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न भागों में स्थित बारह प्रादेशिक अस्पताल रिपोर्ट वाले वर्ष के दौरान कार्य करते हैं। केन्द्रीय अस्पताल धनबाद में 300 बिस्तरों की और केन्द्रीय अस्पताल आसनसोल में 350 बिस्तरों की व्यवस्था है। दोनों अस्पतालों में से प्रत्येक में बिस्तरों की संख्या 400 तक बढ़ाए जाते। क प्रस्ताव को धन की कमी के कारण प्रास्थगित रखा गया। मनेन्द्रगढ़ में 100 बिस्तरों वाले केन्द्रीय अस्पताल का उससे संलग्न 50 बिस्तरों वाले टी० बी० स्कंध सहित सनिर्माण कार्य पूरा किया गया। अस्पताल का उद्घाटन 19 सितम्बर, 1970 को किया गया।

(ख) औषधालय —रिपोर्ट की अवधि के दौरान झरिया कोयला क्षेत्र में मुगमा में एक स्थेतक औषधालय की, असम और पंच घाटी के कोयला क्षेत्रों में अलग-अलग दो चलते फिरते चिकित्सीय यूनिटों की और विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 30 आयुर्वेदिक औषधालयों की सेवा चालू की गई। आयुर्वेदिक औषधालयों में उपयोग के लिए अपेक्षित असली औषधियों के विनिर्माण के लिए झरिया कोयला क्षेत्र में पथेरडिह में स्थापित आयुर्वेदिक फार्मसी रिपोर्ट, वाले वर्ष के दौरान कार्य करती रही है।

(ग) कुटुम्ब कल्याण, प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र—प्रादेशिक अस्पतालों में से प्रत्येक से सम्बद्ध कुटुम्ब कल्याण केन्द्र रिपोर्ट वाले वर्ष के दौरान कार्य करते रहे। इसके अतिरिक्त विभिन्न कोयला क्षेत्रों में पहले ही से स्थापित आठ ऐसे केन्द्र, जो अलग-अलग अर्हित महिला स्वास्थ्य

परिवर्षक के भार साधन में है, स्वतंत्र इकाइयों के रूप कार्य करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 53 प्रसूति और शिशुकल्याण केन्द्रों को आसनसोल, झरिया और हजारीबाग खान स्वास्थ्य बोर्ड चला रहा है और उनको बनाए रखने के लिए कोयला खान श्रम कल्याण संगठन (जिसे इसमें इसके पश्चात् संगठन कहा गया है) सहायता अनुदान देता आ रहा है। चांदा कोलियारी क्षेत्र में कोलियरी कर्मकारों की प्रसुविधा के लिए सरकारी अस्पताल, चांदा से सम्बद्ध ब्लाक, रिपोर्ट वाले वर्ष के दौरान कार्य करता रहा है।

(घ) औषधालय सेवाओं में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता—कोलियरी कर्मकारों और उन के आश्रितों की प्रसुविधा के लिए कोलियरियों में चिकित्सीय सेवाओं के स्तर में सुधार करने के लिए कोलियरी प्रबन्धतंत्र को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सहायता अनुदान देने की योजना चालू रखी गई और वर्ष के दौरान 13,56,013 रुपये की राशि सन्दत्त की गई। इस के अतिरिक्त, कोलियरी प्रबन्धतंत्रों द्वारा नियोजित कर्मकारों की प्रसुविधा के लिए नए औषधालय स्थापित करने या विद्यमान औषधालयों में सेवाओं में सुधार करने के लिए इन प्रबन्धतंत्रों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से संगठन ने औषधालयों के सन्निर्माण की या उसके विद्यमान भवन में सुधार करने की वास्तविक लागत, जिस में उपस्कर की खरीद भी सम्मिलित है, के बराबर बिना व्याज के उधार के सन्दाय के रूप में, जो अधिक से अधिक वार्षिक सहायता अनुदान के सोलह गुना तक हो सकती है, वित्तीय सहायता की एक स्कीम प्रारम्भ की थी। इस स्कीम के अधीन कोलियरी प्रबन्धतंत्रों को 1,63,000 रुपये की राशि सन्दत्त की गई थी।

(ङ) टी० बी० विरोधी उपाय—निधि के अन्तर्गत 262 बिस्तरों (कटरास में 12, धनबाद और आसनसोल म सौ-सौ और सीरसोल में 50) की व्यवस्था करने के अतिरिक्त 61 बिस्तर विभिन्न टी० बी० सेनिटोरियमों में टी० बी० से पीड़ित कोलियरी कर्मकारों और उन के आश्रितों के उपचार के लिए प्रारक्षित रख गये थे। रामगुंडम में 30 बिस्तरों के टी० बी० क्लीनिक का सन्निर्माण पूरा किया गया। रिपोर्ट वाले वर्ष के दौरान टी० बी० गृह उपचार स्कीम कार्य करती रही है तथा टी० बी० के उन मरीजों को, जो इस स्कीम के अधीन उपचार पा रहे थे, खुराक और निर्वाह भत्ते का सन्दाय भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता रहा है।

(च) परिवार नियोजन सेवाएं—परिवार नियोजन पर निशुल्क सलाह दी जाती रही और निधि के अस्पतालों तथा कुछ एक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रयोजन के लिए खोले गये क्लीनिकों पर निःशुल्क गर्भ-निरोधक दिए जाते रहे हैं। परिवार नियोजन कार्य के लिए कोलियरी स्वामियों को सहायता अनुदान के सन्दाय की बाबत स्कीम प्रवृत्त रही है। पांच स्थितिक परिवार नियोजन यूनिट और तीन चलती फिरती परिवार नियोजन यूनिट प्रवर्तन में रही है। इसके अतिरिक्त झरिया, आसनसोल और हजारीबाग खान स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा अपने अपने कोयला क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न भागों में चलाए जा रहे 53 प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्रों, जिन के लिए संगठन सहायता अनुदान देता रहा है, ने भी वहां इन क्षेत्रों में कोलियरी कर्मकारों और उन के आश्रितों की प्रसुविधा के लिए परिवार नियोजन की सेवाएं उपलब्ध की हैं।

(छ) पुनर्वासि—धनबाद और आसनसोल के प्रत्येक केन्द्रीय अस्पताल से सम्बद्ध पुनर्वासि एवं-भौतिक चिकित्सा केन्द्र कार्य करते रहे। सिघवाड़ी में पुनर्वासि-एवं-रोगनिवृ-

तालथ का उन्निर्माण कार्य पूरा किया गया । छिदवाड़ा में पुनर्वास केन्द्र की स्थापना का सन्निर्माण कार्य और निवास-सम्बन्धी और अनिवास सम्बन्धी भवनों का सन्निर्माण कार्य चल रहा था ।

(ग) ग्रन्थ कार्यकलाप—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में संगठन के अन्य मुख्य कार्यकलापों के अन्तर्गत कैंसर, कुष्ठ और मानसिक रोग के उपचार के लिए सुविधाएं देना धनबाद और आसनसोल के दोनों केन्द्रीय अस्पतालों में रक्तदान केन्द्र चलाना और इसके अन्तर्गत एम्ब्यूलेस वेन को बनाए रखना, चश्मे, और कृत्रिम दांतों का निशुल्क प्रदाय, मलेरिया नियंत्रण प्रचालनों की स्थापना और मलेरिया रोधक उपाय थे ।

2. शैक्षिक और ग्रामोद-प्रमोद सम्बन्धी सुविधाएं:

(क) इस सम्बन्ध में कार्यकलापों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ मुसंगत आंकड़े नीचे दिए जाते हैं—

(i) बहुउद्देशीय संस्थान	62
(ii) स्त्रियों के लिए कल्याण केन्द्र	64
(iii) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	66
(iv) प्रदायक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	163
(v) कोलियरी कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	गत वर्ष दी गई छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त 500 साधारण और 22 तकनीकी छात्रवृत्तियां प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाती हैं ।
(vi) बच्चों के लिए छात्रावास	3 तथा इसके अलावा 30 सीटें चिरिमिरि के ब० उ० ड० मा० लाहिरी में आरक्षित रखी गई थी ।
(vii) अवकाश गृह	. 3

(ख) खेल और खेलकूद—खेल और खेल कूद का आयोजन करने के लिए वर्ष के दौरान 1,85,466 रुपये मंजूर किए गए थे ।

मुख्य मुख्य आयोजन इस प्रकार हैं :—

- (i) नवी अखिल भारतीय कोयला क्षेत्र खेल कूद—नवी अखिल भारतीय कोयला क्षेत्र खेल कूदों का आयोजन गांधी स्टेडियम कसतौर कोलियरी में 7 और 8 मार्च, 1970 को बड़े उत्साह और भव्यता के साथ किया गया । पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्र टीम के कोयला-क्षेत्र चैम्पियनशिप फिर से प्राप्त की और झरिया कोयला क्षेत्र टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया । व्यक्तिगत चैम्पियनशिप मोहरा कोलियरी ने जीती । खेल कूदों में पश्चिम बंगाल, झरिया, हजारीबाग, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कोयला की क्षेत्र टीमों ने भाग लिया ।

- (ii) **प्रखिल भारतीय कोयला क्षेत्र फुटबाल प्रतियोगिता**—प्रतियोगिता का सम्मिलन पश्चिम बंगाल और झरिया कोयला क्षेत्र टीमों के बीच 18 फरवरी, 1970 को हजारीबाग कोयला क्षेत्र में केन्द्रीय साउन्डा कोलियरी के स्थान पर हुआ जिसमें झरिया कोयला क्षेत्र विजयी रहा। इस प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल, झरिया, हजारीबाग, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा कोयला क्षेत्र की टीमों ने भाग लिया।

(ग) **भारत वर्शम विशेष रेलगाड़ी**—राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान देने और कोयला खान उद्योग में नियोजित कर्मचारियों में भाई-बारे और टीम के रूप में कार्य करने की भावना को तीव्र बनाने की दृष्टि से कर्मचारियों को, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रयोजनाओं और धार्मिक, ऐतिहासिक, और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर ले जाने के लिए संगठन ने विशेष रेलगाड़ी की व्यवस्था की।

500 कोलियरी कर्मचारियों को लेकर बारहवीं भारत दर्शन यात्रा गाड़ी 6 सितम्बर, 1969 को उत्तरी भारत के लिए रवाना हुई और वाराणसी, लखनऊ, हरद्वार, भाखड़ानगल, दिल्ली, आगरा, बम्बई और इलाहाबाद जैसे कई स्थानों की यात्रा करने के पश्चात् 22 सितम्बर, 1969 को धनबाद वापस लौटी।

3. जल प्रदाय

(क) भिन्न भिन्न कोयला क्षेत्रों की विभिन्न जल प्रदाय स्कीमों के सम्बन्ध में रिपोर्ट वाले वर्ष के दौरान हुई प्रगति का संक्षिप्त पुनर्विलोकन नीचे दिया जाता है :—

कोयला क्षेत्र का नाम	कोलियरी का नाम	विशिष्टियां	स्कीम का मूल्य
रूपये			
बिहार कोयला क्षेत्र	(i) मुरालिध 21/22 गत कोलियरी	संवीक्षित और तकनीकी रूप से मंजूर-शुदा	89,890.00
	(ii) मण्डल की बेलबेरा कोलियरी	तकनीकी रूप से मंजूर-शुदा	1,49,918.00
	(iii) जामदोबा कोलियरी	तकनीकी रूप से मंजूर-शुदा	9,32,168.25
	(iv) सिजुवा मेलातण्ड कोलियरी	संवीक्षित और तकनीकी रूप से मंजूर-शुदा	7,83,700.00
	(v) मालकेरा कोलियरी	—यथोक्त—	3,43,606.00

कोयला क्षेत्र का नाम	कोलियरी का नाम	विशिष्टियां	स्कीम का मूल्य
			रूपये
पश्चिम बंगाल क्षेत्र	(i) कनुस्तोरिया कोलियरी	संबीक्षित और तकनीकी रूप से मंजूर शुदा	1,44,686.00
	(ii) बांकोला 1/2 गत कोलियरी	—यथोक्त—	1,76,549.00
	(iii) बांकोला 3/4 गत कोलियरी	—यथोक्त—	1,44,327.00
	(iv) बांकोला सेन्टीनरी	—यथोक्त—	75,841.00
	(v) कृष्णनगर कोलियरी	तकनीकी रूप से मंजूर शुदा	97,928.00
	(vi) पराशिया	—यथोक्त—	2,63,938.00
	(vii) सालेतीरा कोलियरी	—यथोक्त—	1,97,170.00
मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र	बरार कोलियरी	तैयार और तकनीकी रूप से मंजूर शुदा	1,57,992.00
उड़ीसा कोयला क्षेत्र	हिंगीर रामपुर कोलियरी	डिजाइन की गई और तकनीकी रूप से मंजूर शुदा	1,55,966.00

भिन्न भिन्न कोयला क्षेत्रों में जल प्रदाय की स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष के दौरान 48,50,496 रु० की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी गई ।

(ख) कुएं लगाना—पचास प्रतिशत सहायकी स्कीम के अन्तर्गत चौदह कुएं गलाए गए जिससे अब तक पूरे किए गए कुओं की कुल संख्या 234 हो गई है । रिपोर्ट वाले वर्ष के दौरान विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कुएं गलाने के लिए 39,925.00 रु० की राशि सहायकी के रूप में खान स्वामियों को दी गई ।

4. सहकारिता आन्दोलन संगठन—प्राथमिक सहकारी भंडारों और कोलियरी कर्मकारों को उधार देने वाली समितियों की कुल संख्या 567 रही । केन्द्रीय सहकारी भण्डारों को उधार के रूप में दी गई राशि की बकाया रकम को, वसूल करने के लिए बड़े जोरों से एक अभियान शुरू किया गया और वर्ष के दौरान 16,92,163.00 रु० की राशि विभिन्न केन्द्रीय भण्डारों से वसूल की गई । जिन केन्द्रीय सहकारी भण्डारों को पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान घाटा हुआ था उन में से अधिकांश को रिपोर्ट वाले वर्ष के दौरान लाभ रहा ।

New Delhi, the 13th July, 1971

S.O. 2762.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947) read with rule 3 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Rules, 1949, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1118, dated the 21st March, 1968 as subsequently amended, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee consisting of the following members, namely:—

Chairman—appointed by the Central Government

1. Shri D. S. Nim, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment).

Vice-Chairmen

2. The Coal Mines Welfare Commissioner.
3. The Director General of Mines Safety.

Nominated by Government of West Bengal

4. Shri S. K. Choudhuri, Deputy Secretary, Labour Department, Government of West Bengal.

Nominated by the Government of Bihar

5. The Commissioner of Labour, Bihar.

Nominated by the Government of Madhya Pradesh

6. The Labour Commissioner, Madhya Pradesh, Indore.

Nominated by the Indian Mining Association

7. Shri R. H. Wright.
8. Shri R. Varma.

Nominated by the Central Government to represent the State Collieries

9. C. Balram.

Nominated by the Indian Mining Federation

10. Shri S. B. Goenka.

Nominated by the Indian Colliery Owners' Association

11. Shri M. L. Agarwalla.

Nominated by the Madhya Pradesh and Vidarbha Mining Association

12. Shri B. K. Poddar.

Nominated by the Central Government to represent the interests of workmen employed in coal mines

13. Shri R. K. Malviya (INTUC).
14. Shri S. Narayan Reddy (INTUC).
15. Shri S. Das Gupta (INTUC).
16. Shri M. Komaraiah (AITUC).
17. Shri Mahesh Desai (HMS).
18. Shri S. N. Jha (HMS).

Nominated by the Central Government

19. Dr. (Mrs.) Seeta Parmanand.

Nominated on the recommendation of the Indian Mine Managers' Association

20. Shri J. S. Grewal.

Nominated on the recommendation of the National Association of Colliery Managers

21. Shri R. N. Sharma.

[No. 3/20/70-MIL.]

C. R. NAIR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1971

का० आ० 2762—कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि नियम, 1949 के नियम 3 के साथ पठित कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) को यथा तत्पश्चात् संशोधित, अधिसूचना सं० का० आ० 1118, तारीख 21 मार्च, 1968 को अधिकांश करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक सलाहकार समिति गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. श्री डी० एस० निम, | अध्यक्ष |
| संयुक्त सचिव, भारत सरकार श्रम और पुनर्वास मंत्रालय | केन्द्रीय सरकार |
| (श्रम और रोजगार विभाग) | द्वारा नियुक्त । |
| 2. कोयला खान कल्याण आयुक्त | उपाध्यक्ष |
| 3. महानिदेशक, खान सुरक्षा | |
| 4. श्री एस० के० चौधरी, उप सचिव | पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा |
| श्रम विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार | नामनिर्देशित । |
| 5. श्रम आयुक्त, बिहार | बिहार सरकार द्वारा नाम निर्देशित |
| 6. श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नाम-निर्देशित । |
| 7. मिस्टर आर० एच० राइट } | इंडियन माइनिंग एसोसिएशन |
| 8. श्री आर० वर्मा | द्वारा नामनिर्देशित । |
| 9. श्री सी० बलराम | राज्य-कोलियरियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित । |
| 10. श्री एस० बी० गोयनका | इंडियन माइनिंग फेडरेशन द्वारा नामनिर्देशित । |
| 11. श्री एम० एल० अग्रवाल | इंडियन कोलियरी ओनर्स एसोसिएशन द्वारा नामनिर्देशित । |
| 12. श्री बी० के० पोद्दार | मध्यप्रदेश एण्ड विदर्भ माइनिंग एसोसिएशन द्वारा नामनिर्देशित । |
| 13. श्री आर० के० मालवीय | कोयला-खानों में नियोजित कर्मकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित । |
| (आई एन टो यू सी) | |
| 14. श्री एस० नारायण रेड्डी | |
| (आई एन टी यू सी) | |
| 15. श्री एस० दास गुप्ता | |
| (आई एन टो यू सी) | |
| 16. श्री एम० कुमारदय्या | |
| (ए आई टी यू सी) | |
| 17. श्री महेश देसाई | |
| (एच एम एस) | |
| 18. श्री एस० एन० झा | |
| (एच एम एस) | |

19. डा० (श्रीमती) सीता परमानन्द केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित ।
20. श्री जे० एच० ग्रेवाल इन्डियन माइन मैनेजर्स एसोसिएशन की सिफारिश पर नामनिर्देशित ।
21. श्री आर० एन० शर्मा नेशनल एसोसिएशन आफ कोलियरी मैनेजर्स की सिफारिश पर नामनिर्देशित ।

[सं० 3/20/70 एम 2]

सी० आर० नायर, अव्वर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 27th May 1971

S.O. 2763.—In pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby directs that the Employees' State Insurance Corporation established under sub-section (i) of section 3 of the said Act shall, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, consist of the following members, namely:—

Chairman

1. Shri R. K. Khadlikar, Minister for Labour, Employment and Rehabilitation, Government of India.

Vice-Chairman

2. Shri A. K. Kisku, Deputy Minister for Health and Family Planning, Government of India.

Members

[Nominated by the Central Government under clause (c) of section 4]

3. Shri P. M. Nayak, Secretary to the Government of India, Department of Labour and Employment.
4. Shri D. S. Nim, Joint Secretary to the Government of India, Department of Labour and Employment.
5. Dr. J. B. Shrivastav, Director General of Health Services, Government of India.
6. Shri B. V. Adavi, Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure.

(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)

7. Shri E. V. Ram Reddi, Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Home (Labour III) Department, Hyderabad.
8. Shri T. S. Gill, Secretary to the Government of Assam, Labour Department, Shillong.
9. Shri I. N. Thakur, Secretary to the Government of Bihar, Labour and Employment Department, Patna.
10. Shri K. N. Zutshi, Secretary to the Government of Gujarat, Panchayat and Health Department, Sachivalaya, Gandhinagar.
11. Shri Bihari Lal Ahuja, Secretary to the Government of Haryana, Labour and Employment Department, Chandigarh.
12. Shri C. K. Kochukoshy, Secretary to the Government of Kerala, Labour and Social Welfare Department, Trivandrum.
13. Dr. S. L. Shah, State Medical Officer, Employees' State Insurance Scheme Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
14. Shri V. S. Subbaian, Secretary to the Government of Tamil Nadu, Labour and Housing Department, Madras.

15. Shri H. Nanjundiah Secretary to the Government of Maharashtra Urban Development, Public Health and Housing Department, Bombay.
16. Shri M.K.Venkateshan, Secretary to the Government of Mysore, Food, Civil Supplies and Labour Department, Bangalore.
17. Shri Rabindra Nath Mohanty, Secretary to the Government of Orissa, Labour Employment and Housing Department, Bhubaneswar.
18. Shri N. K. Joshi, Labour Commissioner and Deputy Secretary to the Government of Rajasthan, Labour Department, Jaipur.
19. Shri B. L. Kukkar, Secretary to the Government of Punjab, Health and Family Planning Department, Chandigarh.
20. Shri Dasrath Singh, Labour Commissioner Uttar Pradesh, Kanpur.
21. Shri S. R. Das Secretary to the Government of West Bengal, Labour Department, Calcutta.

[Nominated by the Central Government under clause (e) of section 4 to represent union territories]

22. Shri V. K. Chanana, Labour Commissioner Delhi Administration, Delhi.

[Nominated by Central Government under clause (f) of section 4 in consultation with organisations of employers recognised by the Central Government for purpose].

23. Shri D. P. Mukherjee, Director, Andrew Yule & Co. Ltd., 8, Clive Row, Calcutta.
24. Shri R. N. Joshi, M/s. Lakshmi-Vishnu Cotton Mills Ltd., 199, Churchgate Reclamation, Bombay-20 BR.
25. Shri Madanmohan Mangaldas, 'Mangal Bag', Ellis Bridge, Ahmedabad.
26. Shri P. Chentsal Rao, Secretary All India Organisation of Employers, 'Federation House', Tansen Marg, New Delhi-1.
27. Prof. V. B. Kamath, 'Hira' Mahal, 171, Shivaji Park, Road No. 5, Bombay-16.

[Nominated by the Central Government under clause (g) of section 4 in consultation with organisations of employees recognised by the Central Government for the purpose].

28. Shri T. N. Sidhanta, Communist Party of India, 208 Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12.
29. Shri M.T. Shukla, Secretary, Textile Labour Association, Gandhi Majoor Sevalaya, Bhadra, Ahmedabad.
30. Shri Bishnu Banerjee, Joint General Secretary, I.N.T.U.C. Bengal Branch, 177/B, Acharya Jagdish Bose Road, Calcutta-14.
31. Shri R. Rangaswamy, General Secretary, INTUC-Tamil Nadu, Branch 2/44, Royapettah High Road, Madras-14.
32. Shri Ram Desai, Secretary, Hind Mazdoor Sabha, Nagindas Chambers, 167, P. D'Millo Road, Bombay-1.

[Nominated by the Central Government under clause (h) of section 4 in consultation with organisations of medical practitioners recognised by the Central Government for the purpose].

33. Dr. J. Majumdar, P-5, New C.I.T. Road, Calcutta-14.
34. Shri Kaviraj Keshav Prasad Atreya, Vice-President, All India Ayurvedic Congress, 49/7 B, Bunglow Road, Delhi-7.

[Elected by Parliament under clause (i) of section 4]

35. Shri Nand Kishore Bhatt, M.P., (Member Rajya Sabha) 16-E, Ferozshah Road, New Delhi-1.
36. } To members of Lok Sabha to be notified later on.
37. }

[Ex-officio member under clause (i) of section 4]

38. The Director General, Employees' State Insurance Corporation, New Delhi.

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 1971

का० आ० 2763.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निवेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम का गठन, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, निम्नलिखित सदस्यों से होगा, अर्थात् :—

अध्यक्ष

1. श्री आर० के० खाडिलकार
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री,
भारत सरकार ।

उपाध्यक्ष

2. श्री ए० के० किस्कू
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री,
भारत सरकार ।

सदस्य

[केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड (ग) के अधीन नाम निर्दिष्ट]

3. श्री पी० एम० नायक,
सचिव, भारत सरकार
श्रम और रोजगार विभाग ।
4. श्री डी० एस० निम,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
श्रम और रोजगार विभाग ।
5. डा० जे० बी० श्रीवास्तव,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक,
भारत सरकार ।
6. श्री बी० बी० अदावी,
उपसचिव, भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।

[राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नाम निर्दिष्ट]

7. श्री ई० वी० रामरेड्डी,
विशेष सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार (श्रम 3) विभाग,
हैदराबाद ।
8. श्री टी० एस० गिल
सचिव, असम सरकार
श्रम विभाग, शिलांग ।

9. श्री आई० एन० ठाकुर,
सचिव, बिहार सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग, पटना ।
10. श्री के० एन० जुत्सी,
सचिव, गुजरात सरकार,
पंचायत और स्वास्थ्य विभाग,
सचिवालय, गांधीनगर ।
11. श्री बिहारी लाल आहूजा,
सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग, चंडीगढ़ ।
12. श्री सी० के० कौचुकोशी,
सचिव, केरल सरकार,
श्रम और समाज कल्याण विभाग,
त्रिवेन्द्रम ।
13. डा० एस० एल० शाह,
राज्य चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम,
मध्य प्रदेश सरकार भोपाल ।
14. श्री वी० एस० सुब्बयाह,
सचिव, तमिलनाडु सरकार,
श्रम और आवास विभाग,
मद्रास ।
15. श्री एच० नंजुनडियाह,
सचिव महाराष्ट्र सरकार,
नगर विकास, लोक स्वास्थ्य और आवास विभाग
मुम्बई ।
16. श्री एम० के० वेंकयेशन,
सचिव, मैसूर सरकार,
खाद्य सिविल प्रदाय और श्रम विभाग,
बंगलौर ।
17. श्री रवीन्द्रनाथ मोहनति,
सचिव, उड़ीसा सरकार,
श्रम, रोजगार तथा आवास विभाग,
भुवनेश्वर ।
18. श्री एन० के० जोशी,
श्रम आयुक्त और उपसचिव, राजस्थान सरकार,
श्रम विभाग, जयपुर ।

19. श्री बी० एल० कक्कड़,
सचिव, पंजाब सरकार,
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग,
चंडीगढ़ ।

20. श्री दशरथ सिंह,
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कानपुर ।

21. श्री एस० आर० दास,
सचिव, पश्चिमी बंगाल, सरकार,
श्रम विभाग, कलकत्ता ।

[केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड (ड) के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत नाम निर्दिष्ट]

22. श्री वी० के० चानन,
श्रम आयुक्त, दिल्ली प्रशासन,
दिल्ली ।

[इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त नियोजकों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड (च) के अधीन नाम निर्दिष्ट]

23. श्री डी० पी० मुखर्जी,
निदेशक, एन्ड्रयूयूल एंड कम्पनी, लिमिटेड,
8, क्लाइव रोड कलकत्ता थ-1 ।

24. श्री आर० एन० जोशी,
मैसर्स लक्ष्मी-विष्णु काटन मिल्स लिमिटेड,
199, चर्चगेट रिवेलमेशन, मुम्बई-20 बी० आर०

25. श्री मदन मोहन मंगलवास,
'मंगल बाग' एलिस ब्रिज, अहमदाबाद ।

26. श्री पी० चन्तसल राव,
सचिव, आल इंडिया आर्गनाइजेशन आफ एम्प्लायर्स,
'फेडरेशन हाऊस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली-1

27. प्रोफेसर बी० पी० कामथ,
'हीरा महल' 171, शिवाजी पार्क, रोड सं० 5, मुम्बई-16 ।

[इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के मान्यता प्राप्त कर्मचारियों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड (च) के अधीन नाम निर्दिष्ट]

28. श्री टी० एन० सिद्धांत,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,
208, विपिन बिहारी गांगूली स्ट्रीट,
कलकत्ता-12

29. श्री एम० टी० गुक्ल,
सचिव, टैक्सटाइल लेबर एसोसिएशन,
गांधी मजूर सेवालय, भादरा, अहमदाबाद ।

30. श्री बिशु बनर्जी,
संयुक्त महासचिव,
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बंगाल शाखा,
177/बी, आचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता-14
31. श्री आर० रंगास्वामी,
महासचिव,
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस-समिल नाडू शाखा
2/44, रायपेट्टियाह हाई रोड, मद्रास-14 ।
32. श्री राम वेसाई,
सचिव, हिन्द मजदूर सभा नगीनावास चैम्बर्स,
167, पी० डी० मैलो रोड, मुम्बई -1

[इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार से मान्यताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायियों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 के खण्ड (ज) के अधीन नाम निर्दिष्ट]

33. डा० जे० मजुमदार,
पी०-5 न्यू सी० आई० टी० रोड,
कलकत्ता-14 ।
34. श्री कविराज केशव प्रसाद आत्रेय,
उपाध्यक्ष, आल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस,
49/7, बी, बंगला रोड, दिल्ली-7
35. श्री नन्द किशोर भट्ट,
एम०पी० (राज्य सभा सदस्य)
16-ई, फिरोजशाह रोड,
नई दिल्ली-1

[संसद द्वारा धारा 4 के खण्ड (झ) के अधीन निर्वाचित]

36. } यी लोक सभा सदस्यों को बाद में नियुक्त किया जाय ।
37. }

[धारा 4 के खण्ड (ण) के अधीन पदेन सदस्य]

38. महानिदेशक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
नई दिल्ली]

[सं० फा० 201/1/70-एच०आई०]

New Delhi, the 6th June 1971

S.O. 2764.—In pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour.

Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. 201/1/70-HI. dated the 27th May, 1971, namely:—

In the said notification, under the heading "Members", in the entries under the sub-heading "[Elected by Parliament under clause (1) of section 4]" of the existing entry against serial numbers 36 and 37, the following entries shall be substituted, namely:—

"36. Shri S. M. Banerjee, M.P. (Member Lok Sabha), 113, North Avenue, New Delhi-1.

(Permanent Address:

15/268, Civil Lines, Kanpur).

37. Shri Raja Kulkarni, M.P. (Member Lok Sabha), 19, Janpath, New Delhi-1.

(Permanent Address:

Indira Co-operative, Kelufkar Road, Shivaji Building Park, Bombay-28)."

[No. F. 201/1/70-HI.]

नई दिल्ली, 6 जून, 1971

का० प्रा० 2764—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० 201/1/70-एच आई, तारीख 27 मई, 1971 में निम्नलिखित संशोधन एतद्वारा करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "सदस्य" शीर्षक के अन्तर्गत, "(धारा 4 के खण्ड (i) के अधीन संसद द्वारा निर्वाचित)" उपशीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टियों में, क्रम संख्या 36 और 37 के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"36- श्री एस० एम० बनर्जी, संसद् सदस्य (लोक सभा सदस्य) 113, नार्थ एवेन्यू,

नई दिल्ली—1

(स्थायी पता :

15/268 सिविल लाइन्स, कानपुर)

"37- श्री राजा कुलकर्णी,

संसद् सदस्य (लोक सभा सदस्य) 19, जनपथ, नई दिल्ली-1

(स्थायी पता :

इन्दिरा को-ऑपरेटिव, केलुफकर रोड, शिवाजी बिल्डिंग पार्क, मुम्बई-28)"

[सं० एक० 201/1/70-एच० आई०]

New Delhi, the 5th July 1971

S.O. 2765.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule annexed hereto in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, specified in column (3) of the said Schedule in the State of Maharashtra, hereby exempts the said factories from the payment of Employer's Special Contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District.	Name of Area	Name of the factory
1	2	3	4
1	Kolaba . . .	Pen . . .	Messrs All India Bakalite Works.
2	North Satara . . .	Koregaon . . .	Messrs Koregaon Taluka Sahakari Oil Mills.
3	Poona . . .	Uruli-Kanchan . . .	Messrs Meghdoot Cement Company.
4	Ratnagiri . . .	Deogad . . .	Messrs State Transport Depot, Deogad.
5	West Khandesh . . .	Nandurbar . . .	Messrs Jai Bharat Trading Company.
		Shirpur . . .	Messrs K. G. Industries.

[No. F. 601/29/70/HI.]

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1971

का० प्रा० 2765.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73—च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस बात को ध्यान में रखकर कि इससे उपबन्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखाने महाराष्ट्र राज्य के उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उन क्षेत्रों में स्थित हैं जिनमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध लागू नहीं हैं, उक्त कारखानों को विशेष नियोजक अभिदाय के सन्दाय से जो उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन उदग्रहणीय है, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में लागू नहीं हो जाते, इनमें जो भी पूर्वतर हो, उस तक के लिए इस द्वारा छू देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कोलाबा	पेन	मेसर्स आल इन्डिया बैकेलाइट वर्क्स.
2.	उत्तर सतारा	कोरेगांव	मेसर्स कोरेगांव तालुका सहकारी आयल मिल्स.
3.	पूना	उरुली-कंचन	मेसर्स मेघदूत सिमेंट कम्पनी.
4.	रत्नगिरी	देवगढ़	मेसर्स स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपो देवगढ़.
5.	पश्चिम खानदेश	नन्दुरबार	मेसर्स जय भारत ट्रेडिंग कम्पनी
		शिरपुर	मेसर्स के० जी० इंडस्ट्रीज ।

[सं० फा० 60/(29)/70-एच० प्रा०]

S.O. 2766.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of the Tamil Nadu in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in

force, hereby exempts the said factories from the payment of employers special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name of Area.	Name of the factory.
1	2	3	4
1	Coimbatore	Bilichi Village	M.s. Plastic Industries, Bilichi Post.
2	Nilgiris	Ootacamund	The Nilgiri Cooperative Printing Works Limited, J. 181, Victoria Hall Ettins Road.
		Pegambahalla	Kundah Power House II Pegambahalla Post.
		Kundapalam	Canada Power House No. I, Kundah Bridge Post.
		Cherambadi	Food Specialities Limited Cherambadi, Choladi Post.
		Sarakarpathi	Sarkarapathy Power House, Sarkarpathi Post (Via) Anaimalai, Pollachi Tq.

[No. F. 602/11/70/HI.]

का० अ० 2766.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस बात को ध्यान में रखकर कि इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखाने तामिल नाडु राज्य के उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उन क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध लागू नहीं होते हैं, उक्त कारखानों को विशेष नियोजक अभिदाय के संदाय से जो उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय हैं, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में, प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में लागू नहीं हो जाते, इनमें से जो भी पहले हो उस तक के लिए इस द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	मिलों का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कोयम्बतूर	बिलिचीग्राम	मेसर्स प्लास्टिक इंडस्ट्रीज बिलिची पोस्ट।
2	नीलगिरी	ऊटाकमण्ड	दी नीलगिरी कोपरेटिव प्रिंटिंग वर्क्स लिमिटेड, स० ज० 181, विक्टोरिया हाल, एटिन्स रोड।

(1)	(2)	(3)	(4)
	पेगामबाहल्ला	कुन्डाह पावर हाऊस—ii, पेगामबाहल्ला पोस्ट ।	
	कुन्डापालाम	कानाडा पावर हाऊस सं ० 1, कुन्डाह ब्रिज पोस्ट ।	
	चेराम्बडी	फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड, चेराम्बडी, चालाही पोस्ट ।	
	साराकारपथी	साराकारपथी पावर हाऊस, साराकारपथी पोस्ट (बरास्ता), अनाईमलाई, पोत्तलाची तालुका ।	

[सं ० एफ ० 602(11)/70-एच ० आई ०]

S.O. 2767.—In exercise of the powers conferred by section 733F of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Maharashtra in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act from the date of publication of this notification in the Official Gazette or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name of Area	Name of the factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Parbhani	Manwath	Messrs Bangad Oil Mills, Station Road.
2	Yeotmal	Narkhed	Shri Hanuman Vijay Saw Mill, Timber Merchant, Mahatma Gandhi Road.

[No. F. 601/29/70-HI.]

का ० प्रा ० 3767.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों को उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के सन्दाय से, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्वारा छट देती है ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पारभनी	मनवश	मैसर्स बंगद आयाल मित्स, स्टेशन रोड ।
2	विश्रोतमाल	नरखेद	श्री हनुमान विजय साँ मिल, टिम्बर मर्चेन्ट, महात्मा गांधी रोड ।

[सं० फा० 601 (29)/70-एच० आई०]

S.O. 2768.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4013, dated the 20th September, 1969 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Himachal Pradesh in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District.	Name of Area.	Name of the factory.
1	2	3	4
1	Bilaspur	Bilaspur.	M/s. Himachal Government Rasin and Turpentine Factory.
2	Kangara.	Ghati.	M/s. Down Stream Batching Plant.
3	Mandi	Harabagh Pandoh	M s. Field Repair Shop. M/s. Electrical Repair and Auto Battery Shop

[No. F. S-38017/14/71-HL.]

का० आ० 2768—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 4013 तारीख 20 सितम्बर, 1969 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश राज्य के ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने के उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के सन्दाय से, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा छूट देती है :

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
1	2	3	4
1	बिलासपुर	बिलासपुर	मैसर्स हिमाचल गवर्नमेन्ट रेजिन और तारपीन फैक्टरी ।
2	कांगड़ा	घाटी	मैसर्स डाउन स्ट्रीम बाचिंग प्लांट ।
3	मण्डी	हराबाग पण्डोह	मैसर्स फील्ड रिपेयर शाप । मैसर्स इलेक्ट्रिकल रिपेयर एण्ड ओटो बैटरी शाप ।

[सं० फा० एस०-38017(14)/71-एच०आर्डी०]

S.O. 2769.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 217, dated the 7th January, 1970, the Central Government hereby appoints Shri J. N. Chhabra, Assistant Provident Fund Commission (Grade I) to be an Inspector for the whole of the States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and the Union territory of Chandigarh for the purposes of the said Act and of any scheme framed thereunder, in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government, or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oil field, or a controlled industry.

[No. A. 12015(4)/71-PF.I.]

का० आ० 2769—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 217 तारीख 7 जनवरी, 1970 को अतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री जे०एन० छाबड़ा, सहायक भविष्य निधि आयुक्त (श्रेणी 1) को उक्त अधिनियम के और उसके अधीन बनाई किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थान के सम्बन्ध में सम्पूर्ण पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है ।

[सं० ए०-12015(4) 71-पी० एफ०-1]

S.O. 2770.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 500 dated the 13th January, 1971 the Central Government having regard to the location of the Steam Laundry attached to the King George Hospital, Visakhapatnam, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said laundry from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st August, 1971 up to and inclusive of the 31st July, 1972.

[No. F. 801/38/70-HI.]

का०आ० 2770—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 500, तारीख 13 जनवरी, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार किंग जार्ज हास्पिटल, विशाखापट्टणम से संलग्न स्टीम लौन्ड्री की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त लौन्ड्री को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 1 अगस्त, 1971 से 31 जुलाई, 1972 तक और इस दिन को भी सम्मिलित करते हुए, एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० फा० 60/(36)/70-एच० आई०]

S.O. 2771.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3611 dated the 23rd October, 1970 the Central Government having regard to the location of the factory, namely, Drainage Main Pumping Station, Ramnad Road, Madurai belonging to the Madurai Municipality, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 31st May, 1971 upto and inclusive of the 30th May, 1972.

[No. F. 601(14)/70-HI.]

का० आ० 2771—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3611 तारीख 23 अक्टूबर 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार मदुरई नगरपालिका के ड्रेनेज मेन पम्पिंग स्टेशन, रामनद रोड, मदुरई नामक कारखाने को ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 31 मई 1971 से 30 मई, 1972 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० फा० 601(14)/70-एच० आई०]

S.O. 2772.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1162 dated the 20th March, 1970 the Central Government having regard to the location of the factory namely, Bhupendra Cement Works, Surajpur in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of the employer's special contribution leviable under chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification.

[No. 602(5)/70-HI.]

का०आ० 2772 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 1162 तारीख 20 मार्च, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार भूपेन्द्र सीमेन्ट वर्क्स, सूरजपुर नामक कारखाने की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० फा० 602 (5)/70-एच० आई०]

S.O. 2773.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1144 dated the 22nd February, 1971 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Maharashtra in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the 9th August, 1971 upto and inclusive of 8th August, 1972, or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of District	Name of Area	Name of the factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Buldhana	Buldhana	Messrs Maharashtra State Road Transport Corporation, Malkapur Road, Buldhana.
2	Wardha	Talegaon	Messrs Maharashtra State Road Transport Corporation, Talegaon.

[No. F. 601/29/70-HI.]

का०आ० 2773—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 1144 तारीख 22 फरवरी, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से, 9 अगस्त, 1971 से 8 अगस्त, 1972 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है और एक वर्ष के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
1	2	3	4
1	बुलडाना	बुलडाना	मैसर्स महाराष्ट्र स्टेट रोड, ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, मलकापुर रोड, बुलडाना।
2	वर्धा	तेलगांव	मैसर्स महाराष्ट्र स्टेट रोड, ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, तेलगांव।

[सं० फा० 601 (29)/70-एच० आई०.]

S.O. 2774.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1443 dated the 8th April, 1970 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Orissa in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employers special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Serial No.	Name of District	Name of Area	Name of the factory
1	2	3	4
1.	Balesore.	Balesore	Orissa Plastic.
2.	Koraput .	Dumariput Mathili	NU Bilt Furniture Company. Saw Mill, Orissa Forest Corporation Limited.

[F. No. 602/15/70/HI.]

का० प्रा० 2774—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1443 तारीख 8 अप्रैल, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उड़ीसा राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के सन्दाय से, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हों, एतद्वारा छूट देती है ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
1	2	3	4
1.	बालासोर	बालासोर	उड़ीसा प्लास्टिक
2.	कोरापुट	डुमारोपुट मैथिली	न्यू बिल्ट फर्निचर कम्पनी सोमिल, उड़ीसा फारेस्ट कारपोरेशन लिमिटेड ।

[सं० फा० 602(15)/70-एन० आई०]

S.O. 2775.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in contribution of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 499, dated the 13th January, 1971 the Central Government having regard to the location of the State Transport Workshops at Meenakshipuram and Rani-thottam of the Kanya Kumari, Branch of the Tamil Nadu State Transport Department in an area in which the provisions of Chapter IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said workshops from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 29th July, 1971 upto and inclusive of the 28th July, 1972.

[No. F.601(35)/70-HI.]

का० प्र० 2775—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34 की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 499 तारीख 13 जनरी, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु राज्य परिवहन विभाग की कन्याकुमारी शाखा की मीनाक्षीपुरम एवं रानीथोत्तमस्थित राज्य परिवहन कर्मशालाओं की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कर्मशालाओं को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से 29 जुलाई, 1971 से 28 जुलाई, 1972 तक जिसमें तद्दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा छुट देती है।

[सं० एफ० 601/(35)/70-एच० आई०]

S.O. 2776.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 369, dated the 22nd January, 1970 the Central Government having regard to the location of the press, namely Punjab, Agricultural University Press, Ludhiana, in an area in which the provisions of the Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said press from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the date of expiry of the period specified in the said notification.

[No. F. S-38017(8)/71-HI.]

का० प्रा० 2776—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 369 तारीख 22 जनवरी, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार पंजाब कृषि विश्वविद्यालय मद्रणालय, लुधियाना नामक मद्रणालय की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक और वर्ष की अवधि के लिये एतद्वारा छुट देती है।

[सं० फा० 38017 (8) / 71-एच० आई०]

S.O. 2777.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4013, dated the 20th September, 1969 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Haryana in which the

provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of Employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Serial No.	Name of District.	Name of Area	Name of the factory
1	2	3	4
1	Ambala . . .	Abdullapur	Messrs India Auto Sales Private Limited, Pinjore Village.
2	Rohtak . . .	Bhalgarh . . .	(i) Messrs Haryana Iron & Steel Rolling Mills, G.T. Road. (ii) Messrs Reclaine Company of India Private Limited. (iii) Messrs Haryana Rang Udog.
		Kundli . . .	Messrs Essex Farms, 17th mile Stone, Village Kundli.

[F. No. S-38017/14/71/HI.]

का० आ० 2777. --कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73व द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 4013 तारीख 20 सितंबर, 1969 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपावध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट हरयाणा राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थित की ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्यमणीय नियोजक के विशेष आदेश के संदाय से, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
1	2	3	4
1	अम्बाला	अब्दुल्लापुर	मैसर्स इंडिया आटो सेल्स प्राईवेट लिमिटेड, पिंजौर गांव।
2	रोहताक	भालगढ़	(1) मैसर्स हरयाणा आयर्न और स्टील रोलिंग मिल्स, जी० टी० रॉड। (2) मैसर्स रैक्लेन कम्पनी, भारतीय प्राईवेट लिमिटेड।

1	2	3	4
	कुण्डली	(3)	मैसर्स हरयाणा रांग उद्योग मैसर्स ऐम्बेक्स फार्म, 17 बी मील का पर्यार, कुण्डली गांव ।
[सं० फा० 38017 (14)/71-एच० आई०]			

S.O. 2778.—Whereas the Central Government was satisfied that (1) Messrs The East India Distilleries and Sugar Factory.

(2) Messrs Andhra Provincial Potteries Limited were situated in Tadepalli area which was a sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Guntur in the State of Andhra Pradesh;

And, whereas by virtue of their location in a sparse area, the aforesaid factories were granted exemption from the payment of the employer's special contribution under Section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in the area by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 2665, dated 2nd November 1961;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Tadepalli area in the district of Guntur in the State of Andhra Pradesh has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In Schedule III to the said notification, against Serial No. 6, the entry "Tadepalli" in column 4 and the corresponding entries in column 5 shall be omitted.

[No. F. 6/79-69-HI.]

का० आ० 2778.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि (1) मैसर्स दी ईस्ट इन्डिया डिस्टिलरी और शुगर फैक्टरी (2) मैसर्स आन्ध्र प्रोविन्शियल पोटर्रीज लिमिटेड, टाडेपल्ली क्षेत्र में स्थित था जो आन्ध्र प्रदेश राज्य के गुन्टूर जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) था;

और, यतः उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2665 तारीख 2 नवम्बर, 1961 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-ब के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रचलित नहीं हो जाते;

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य के गुन्टूर जिले में टाडेपल्ली क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है ।

अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची III में, क्रम संख्या 6 के सामने स्तम्भ 4 प्रविष्टि "टाडेपल्ली" और स्तम्भ 5 की उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[सं० फा० 6/79/69-एच० आई०]

S.O. 2779.—Whereas the Central Government was satisfied that Messrs 132, K. Receiving Station, was situated in Tadepalli area which was a sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500), in the district of Guntur in the State of Andhra Pradesh;

And, whereas by virtue of its location in a sparse area, the aforesaid factory was granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (31 of 1948), until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Department of Social Security No. S.O. 957, dated the 19th March, 1965;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Tadepalli area in the district of Guntur in the State of Andhra Pradesh has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification namely:—

In the Schedule to the said notification, against Serial No. 4, the entry "Tadepalli" in column 3 and the corresponding entry in column 4 shall be omitted.

[No. F.6/79/69-HI.]

का० आ० 2779 यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि सैसर्स 132, के० बी० रिसीविंग स्टेशन, टाडेपल्ली क्षेत्र में स्थित था जो आन्ध्रप्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) था ;

और, यतः उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपयुक्त कारखाने को, भारत सरकार के भूतपूर्व और श्रम रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 957 तारीख 19 मार्च, 1965 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के सदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ;

और, यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि आन्ध्रप्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में टाडेपल्ली क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है ;

अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन० द्वारा उक्त अधिसूचना में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 4 के सामने स्तम्भ 3 की प्रविष्टि ("टाडेपल्ली" और स्तम्भ 4 को उससे सम्बन्धित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ।

[सं० एफ० 6/79/69-एच० आई०]

S.O. 2780.—Whereas the Central Government was satisfied that (1) Messrs Mysore Insecticide Company, (2) Messrs East Coast Food Products Limited were situated in Tadepalli area which was a sparse area (that is, an area whose insurable population was less than 500) in the district of Guntur in the State of Andhra Pradesh;

And, whereas by virtue of their location in a sparse area, the aforesaid factories were granted exemption from the payment of the employer's special contribution under section 73F of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), until enforcement of the provisions of Chapter V of the Act in that area by the Central Government in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 86, dated the 13th March, 1963;

And, whereas the Central Government is satisfied that the insurable population of the Tadepalli area in the district of Guntur in the State of Andhra Pradesh has now exceeded 500, and it is no longer a sparse area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the Schedule to the said notification, against Serial No. 5, the entry "Tadepalli" in column 3 and the corresponding entries in column 4 shall be omitted.

[No. F. 6/79/69-HI.]

का० आ० 2780.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया था कि (1) मैसर्स मैसूर इनसैक्टोरीआईड कम्पनी, (2) मैसर्स ईस्ट कोस्ट फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाडेपल्ली क्षेत्र में स्थित था जो आन्ध्र प्रदेश राज्य के गूंटूर जिले में बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र (अर्थात् ऐसा क्षेत्र जिसकी बीमा योग्य आबादी 500 से कम थी) था ;

और, यतः उसकी बिखरी हुई आबादी के क्षेत्र में अवस्थिति के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त कारखाने को, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिपूचना सं० का० आ० 860 तारीख 13 मार्च, 1963 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-ब के अधीन नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से तब तक के लिए छूट दे दी थी जब तक कि उस अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उस क्षेत्र में प्रवर्तित नहीं हो जाते ;

और, यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य के गूंटूर जिले में टाडेपल्ली क्षेत्र की बीमा योग्य आबादी अब 500 से बढ़ गई है, और वह अब बिखरी हुई आबादी का क्षेत्र नहीं है ;

अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिपूचना में और आग निम्न-लिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिपूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 5 के सामने स्तम्भ 3 की प्रविष्टि "टाडेपल्ली" और स्तम्भ 4 की उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[सं० फा० 6/79/69-एच० आई०]

S.O. 2781.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 267, dated the 7th January, 1971, the Central Government having regard to the location of the factory, namely, Central Jail Factory, Vellore, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 24th June, 1971 upto and inclusive of the 23rd June, 1972.

[No. F. 601/18/70-H.I.]

का० आ० 2780. —कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 267, तारीख 7 जनवरी, 1971 के क्रम में केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल जेल कारखाना, वेल्डोर नामक कारखाने की ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उदग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के सन्दाय से 24 जून, 1971 से 23 जून, 1972 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की कालावधि के लिए एतद्वारा छूट देती है।

[सं० का० 601/(18)/70-एच०आई]

S.O. 2781.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948, (34 of 1948), the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Bihar in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Serial No.	Name of District	Name of Area	Name of factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bhagalpur . .	Colganj	M/s. Khemka Brothers.
2	Champaran . .	Motihari	M/s. Rama Saw Mills, Balnatal.
3	Hazaribagh . .	Petarbar	M/s. Bhagat Construction Company (Private) Limited, Stone Crusher, Village Ultasar.
		Gidi . .	M/s. Gidi Coal Preparation Plant At & P. O. Gidi.
4	Muzaffarpur . .	R. K. Ashram	M/s. Ravi Industrial Corporation, Large Industrial Estate.
5	Palamau . .	Daltenganj	(1) M/s Achruram Kal Khaof & Company, Baratola. (2) M/s. The National Marble Company, Redma.
6	Ranchi . .	Mandar	M/s. Rabindra Nath Engineering Company, Lohardaga Road, Maltigrans.

[No. F. 602/31/70-HI]

का० आ० 2781. —कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की बिहार राज्य में, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उदग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय

के संदाय के इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले ही एतद् द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भागलपुर	कोलगाँव	मैसर्स बिमका ब्रादर्स।
2.	बक्सर	मोतीहारी	मैसर्स रामा सॉन्स लि., बलनाताल।
3.	हजारीबाग	पेतगाँवबार	मैसर्स भगत कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड, स्टोन क्रणर, गाँव-उत्तरपुर।
		गिडी	मैसर्स गिडी कोल प्रीपेरेशन प्लान्ट, गिडी और डाकखाना- गिडी।
4.	जयपुर	आर० के० आश्रम	मैसर्स रवि इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन, लार्ज इंडस्ट्रीयल एस्टेट।
5.	पालास	दलातेनगाँव	(1) मैसर्स अछरुराम कल कोफ एण्ड कम्पनी, बारात ला। (2) नैशनल मार्बल कम्पनी रेडम
6.	रांची	भण्डर	मैसर्स रविन्द्रनाथ इंजीनियरिंग कम्पनी, लोहारदाग रोड, मालतीग्राम।

[सं० फा० 602(31)/70-ए० आई०]

S.O. 2782.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1663, dated the 29th April, 1970 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Bihar in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Serial No.	Name of District	Name of Area	Name of the factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bhagalpur	Sultanganj	M/s. Hanuman Oil Mills.
2.	Muzaffarpur	Dighra	(i) M/s. Muzaffarpur Rolling Mills, R.K. Ashram. (i) M/s. Ratan Aluminium Works Industries. R.K. Ashram.
3.	Santhal Pargana	Bandarjori	M/s. Saw Mills Cum Depot, Forest Department.
4.	Singhbhum	Chandil	M/s. Ratan Lal & Company, Shellac Factory.

[No. F. S-38017/1/71/HL.]

का० आ० 2782. —कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1663, तारीख 29 अप्रैल, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपाबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 —क के अधीन उदग्रहणीय नियोजक के विशेष अधिदाय के सन्दाय से, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपाबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते जो भी पहले हो, एतद्द्वारा छूट देती है ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भागलपुर	सुल्तानगंज	मैसर्स हनुमान आयल मिल्स ।
2.	मुजफ्फरपुर	डिघरा	(i) मैसर्स मुजफ्फरपुर रोलिंग मिल्स, आर० के० आश्रम । (ii) मैसर्स रतन अलुमीनियम वर्क्स इन्डस्ट्रीज, आर० के० आश्रम ।

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	सन्थाल परगना	बन्दरजोरी	मैसर्स लौ मिल्स-कम-डिपो, फारेस्ट डिपार्टमेन्ट. ।
4.	सिधभूम	चन्दिल	मैसर्स रतन लाल एण्ड कम्पनी, शैलाक फैक्टरी ।

[सं० फा० एस०-38017(1)/71-एच आर्डी]

S.O. 2783.- In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2293, dated the 5th June, 1969 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Rajasthan in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Serial No.	Name of District	Name of Area	Name of the factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bhilwara	Bigod	M/s. Kisan Vrihat Behu Whendhi, Sahakari Samiti Limited.
2.	Nagour	Ladnum	The Rajasthan Worsted Spinning Mills.
3.	Pali	Sojat Road	M/s. Asbestos Cement Products.
4.	Sikar	Sikar	M/s. Sikar Ispat Udyog Private Limited.
5.	Sriganganagar	Hanumangarh Junction Suratgarh Junction	Rajasthan Canal Project Workshop, Sub-Division I. The Central Workshop Rajasthan Canal Project.
6.	Udaipur	Fatchnagar	M/s. Shree Gopal Industries.

[No. F. 602/13/70/HI.]

का० आ० 2783.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वसि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2293, तारीख 5 जून, 1969 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के रतम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिदाय के संदाय से, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम

के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, एतद्वारा छूट देती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भीलवाड़ा .	बिगोद	मैसर्स किसान ग्रुप्स बेहू देन्दी सहकारी समिति लिमिटेड ।
2.	नगीर .	लहनन	वी राजस्थान वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स ।
3.	पाली .	सोजात रोड	मैसर्स एस्वेस्टोस सीमेन्ट प्रोडक्ट्स ।
4.	सिकार .	सिकार	मैसर्स सिकार इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड ।
5.	श्रीगंगानगर .	हनुमानगढ़ जंक्शन	राजस्थान कनकल प्रोजेक्ट वर्कशॉप उपमण्डल ।
		सूरस गढ़ जंक्शन	वी सैस्ट्रल वर्कशॉप राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट ।
6.	उदयपुर .	फतेहनगर	मसर्स श्री गोपाल इंडस्ट्रीज ।

[सं० फ़ा० 602(13)/70-एच० आई०]

S.O. 2784.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4013 dated the 20th September, 1969 the Central Government, having regard to the location of the factories specified in column (4) of the Schedule hereto annexed in areas specified in column (3) of the said Schedule in the State of Punjab in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are not in force, hereby exempts the said factories from the payment of employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year from the date of expiry of the period specified in the said notification or until the enforcement of provisions of Chapter V of the said Act in those areas, whichever is earlier.

SCHEDULE

Serial No.	Name of District	Name of Area	Name of Factory
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bhatinda	Bhatinda	M/s. National Industries, Industrial Area.
2.	Ferozepur	Ferozepur	M/s. Sarwan Singh Saw Mills, Ferozepur Cantt.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Gurdaspur	Pathankot	M/s. Indian Oil Corporation Limited.
4.	Patiala	Ambe Magera	M/s. Roshan Lal Ram Lal Iron & Steel Factory.
		Samana	M/s. Janta Engineering Works.
5.	Sangrur	Sunam	M/s. Meenakshi Industries.

[No. F. S. 330/17/14/71-HI]

का० आ० 2784—कर्मचारी राज्य बीम. अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 4013 तारीख 20 सितम्बर, 1969 के क्रम में केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट कारखानों की उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट पंजाब राज्य के ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों की उक्त अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजन के विशेष अभिदाय के सन्दाय में, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या सब तक के लिए जब तक कि उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबन्ध उन क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं हो जाते, जो भी पहले ही, एतद्द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिले का नाम	क्षेत्र का नाम	कारखाने का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भटिंडा	भटिंडा	मैसर्स नेशनल इंडस्ट्रीज, इन्डस्ट्रियल एरिया।
2.	फिरोजपुर	फिरोजपुर	मैसर्स सरवन सिंह सा मिल्स फिरोजपुर कौन्ट।
3.	गुरदासपुर	पठानकोट	मैसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड।
4.	पटियाला	अम्बे मजीरा	मैसर्स रोशन लाल राम लाल आयरन एण्ड स्टील फैक्टरी।
		समाना	मैसर्स जनता इंजीनियरिंग वर्क्स।
5.	संगरूर	सुनाम	मैसर्स मीनाक्षी इंडस्ट्रीज।

[सं० फा० एस० 38017(14)/71-एच०आई०]

S.O. 2785.—In exercise of the powers conferred by section 73F of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 64 dated the 16th December, 1970 the Central Government having regard to the location of the factory, namely, Workshop belonging to the Municipal Corporation, Indore, in an area in which the provisions of Chapters IV and V of the said Act are in force, hereby exempts the said factory from the payment of the employer's special contribution leviable under Chapter VA of the said Act for a further period of one year with effect from the 29th June, 1971 upto and inclusive of the 28th June, 1972.

[No. F.601/2/70-HI.]

का० आ० 2785.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73-ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 64, तारीख 16 दिसम्बर, 1970 के क्रम में केन्द्रीय सरकार नगर निगम, इंदौर की कर्मशाला नामक कारखाने को ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और 5 में उपबन्ध प्रवृत्त हैं, अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त कारखानों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन उद्ग्रहणीय नियोजक के विशेष अभिवाय के संदाय से 29 जून, 1971 से 28 जून, 1972 तक और इस दिन को भी सम्मिलित करते हुए, एक और वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा छूट देती है।

[सं० फा० 601(2)/70-एच०आई०]

New Delhi, the 6th July 1971

S.O. 2786.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kerala Rubber and Reclaims Limited, XXIII/1302, M.G. Road, Cochin-16 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefor, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment with effect from the 30th June 1971.

[No. 8/155/70-PF.II.]

नई दिल्ली, 6 जलाई, 1971

का० आ० 2786.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स केरल रबर एण्ड रिक्लेम्स लिमिटेड XXIII/1302, एम० जी० रोड, कोचीन-16 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी अधिव्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1971 के जून मास की तीस तारीख को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 8/155/70-पी०एफ०-2]

New Delhi, the 8th July 1971

S.O. 2787.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds Act and Family Pension Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 3350 dated the 13th September, 1968, namely:—

In the said notification, for the words "Samir Ch. Ghosh and Benoy Sen", the words "and Samir Ch. Ghosh" shall be substituted.

[No. 21(6)/68-PF.I(1).]

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1971

का० आ० 2787.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3350, तारीख 13 सितम्बर, 1968 में निम्नलिखित संशोधन एतद्वारा करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में 'समीर चन्द्र घोष और विनय सेन' शब्दों के स्थान पर "और समीर चन्द्र घोष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 21(6)/68-पी०एफ०/I(i)]

S.O. 2788.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds Act and Family Pension Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Sarvashri Tapadhir Sen and Debabrata Mukherjee to be Inspectors for the whole of the State of West Bengal and the Union territories of Tripura and Andaman and Nicobar Islands for the purposes of the said Act and of any scheme framed thereunder, in relation to any establishment belonging to, or under the control of, the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oil-field or a controlled industry.

[No. 21(6)/68-PF.I(III).]

का० आ० 2788.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सर्वश्री तपधीर सेन और देवव्रत मुखर्जी को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन स्थापनों के सम्बन्ध में और किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में संपूर्ण पश्चिमोत्तरांचल राज्य, त्रिपुरा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निरोक्षक नियुक्त करती है।

[सं० 21(6)/68-पी०एफ० I(ii)]

S.O. 2789.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds Act and Family Pension Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri V. Devadass Mathuram to be an Inspector for the Pondicherry and Karaikal area in the Union territory of Pondicherry for the purposes of the said Act and of any Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of, the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a mine or an oil-field or a controlled industry.

[No. 20(18)/69-PF. I(i)]

का० आ० 2789.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, और परिवार पेंशन अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री वी० दैवदास माथुरम को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के पाण्डिचेरी और करैकाल क्षेत्र के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० 20(18)/69-पी० एफ-I(i)]

S.O. 2790.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds Act and Family Pension Act, 1952 (19 of 1952), and in continuation of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 626 dated the 19th April 1958, the Central Government hereby appoints Shri S. Mohammed to be an Inspector for the Pondicherry and Karaikal area in the Union territory of Pondicherry also for the purposes of the said Act and of any Scheme framed thereunder, in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a mine or an oil-field or a controlled industry.

[No. 20(18)/69-PF.I(ii)]

का० आ० 2790.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और परिवार पेंशन अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 626 तारीख 19 अप्रैल, 1958 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एस० मुहम्मद को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के सम्बन्ध में पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में के पाण्डिचेरी और करैकाल क्षेत्र के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० 20(18)/69-पी० एफ० I(i)]

S.O. 2791.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds Act and Family Pension Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri P. K. Kurien Ghee Varghese to be an Inspector for the whole of the State of Kerala for the purposes of said Act and of any Scheme framed thereunder, in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oil-field or a controlled industry.

[No. 21/3/68-PF.I.]

का० आ० 2791.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और परिवार पेंशन अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री पी० के० कुरीनगी वर्गीस को उक्त अधिनियम के और इस के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल या नियंत्रित उद्योग के सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण केरल राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० 21 (3) 68-पी० एफ०-1]

S.O. 2792.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds Act and Family Pension Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1133, dated the 12th March, 1969.

[No. 21(6)/68-PF.I(ii)]

DALJIT SINGH, Under Secy.

का० आ० 2792.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और परिदार पेंशन अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 1133, तारीख 12 मार्च, 1969 को एतद्वारा ख़ारिज करती है।

[संख्या 21(6)/68-पी०एफ० I(ii)]

दलजीत सिंह, अधीन सचिव।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 5th July 1971

S.O. 2703.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri B. K. Ghai as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines.

[No. 8/85/69-MI.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1971

का० आ० 2793.—खान अधिनियम, 1962 (1962 का 35) की धारा 5 का उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री बी० के० घई को मुख्य खान निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 8 / 85 / 69-एम. 1]

New Delhi, the 6th July 1971

S.O. 2794.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri H. B. Ghose to be the Chief Inspector of Mines for all the territories to which the said Act extends, with effect from the 8th July, 1971 vice Shri R. G. Deo.

2. The notification of the Government of India, Ministry of Labour and Employment, No. S.O. 4353, dated the 16th November, 1957, relating to the appointment of Shri R. G. Deo as Chief Inspector of Mines, is hereby cancelled with effect from the 8th July, 1971.

[No. A32013/1/71-MI.]

J. D. TEWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1971

का० आ० 2794.—केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री आर० जी० देव के स्थान पर श्री एच० बी० घोष को 8 जुलाई, 1971 से उन सभी क्षेत्रों के लिए, जिन पर उक्त अधिनियम का विस्तार है, खानों का मुख्य निरीक्षक एतद्वारा नियुक्त करती है।

2. भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय की श्री आर० जी० देब की खाती के मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्ति सम्बन्धी अधिसूचना संख्या बा०श्री० 4353 तारीख 16 नवम्बर, 1967, एतद्द्वारा 8 जुलाई, 1971 से रद्द की जाती है।

[सं० ए. 32013/1/71 एम०-1]

जे० डी० तिमारी, अवर सचिव।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 12th July 1971

S.O. 2795.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1870 dated the 1st May, 1969, namely:—

In the Table attached to the said notification—in the entries against item I, in column (2) the words “except the State of Jammu and Kashmir” shall be omitted.

[No. S. 33013(2)/71-WB.]

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

(श्रम और रोजगार विभाग)]

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1971]

का० आ० 2795.—केंद्रीय सरकार, बोनस सन्दाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 1870 तारीख 1 मई, 1969 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में—

मद 1 के सम्मुख प्रविष्टियों में स्तम्भ (2) में “जम्मू-काश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

[सं० ए. 33013/2/71-डब्ल्यू. बी०]

हंस राज छाबड़ा, अवर सचिव।

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 3rd July 1971

S.O. 2796.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 32C of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4650, dated the 19th December, 1967, namely :—

In the Table annexed to the said notification—

for S. No. 12 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
"12.	Labour Court, Hyderabad constituted under section 7 of the said Act by the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 456. Dated the 5th February, 1963.	Entire Telengana Region including the twin cities of Hyderabad and Secundrabad in the State of Andhra Pradesh.
12A.	Labour Court, Guntur constituted under section 7 of the said Act by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2242 dated the 24th May, 1971.	Entire Andhra Region in the State of Andhra Pradesh.

[No. F.1/52/70-LR.I.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1971

का० सा० 2796.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33ग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 4650 तारीख 19 दिसम्बर, 1967 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में—

क्रम सं० 12 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"12	भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 456 तारीख 5 फरवरी, 1963 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, हैदराबाद।	आन्ध्र प्रदेश राज्य में समस्त तेलंगाना क्षेत्र जिसमें हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरों का जोड़ा भी सम्मिलित है।

1	2	3
12क	भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ 2242 तारीख 24 मई, 1971 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, गुटूर :	आन्ध्र प्रदेश राज्य में समस्त आन्ध्र क्षेत्र ।

[सं० फा० 1/52/70-एन० आर० 1]

New Delhi, the 13th July 1971

S.O. 2797.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1277, dated the 24th March, 1969, namely:—

In the Table annexed to the said notification, in the entries relating to Serial number 30, for the entry in column 2, the following entry shall be substituted, namely:—

“Assistant Labour Commissioner (Central), Sambhaji.”

[No. F. S. 11025/16/71-I.R.I.]

नई दिल्ली, 13 जुलाई 1971

का० आ० 2797.—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग), की अधिसूचना सं० का० आ० 1277, तारीख 24 मार्च, 1969 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उगमद्ध सारणी में क्रम सं० 30 से संबंधित प्रविष्टियों में, स्तम्भ 2 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), सम्भाजी ।”

[सं० फा० ए० 11025/16/71—एल० आर० आर०]

ए० ए० सहस्रनाम, अधीक्षक सचिव ।

New Delhi, the 17th July 1971

S.O. 2798.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Central Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th July, 1971.

BEFORE SHRI P. P. R. SAWHNY, B.A. (HONS), CANTAB, BAR-AT-LAW.
PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CENTRAL CHANDIGARH

REFERENCE No. 4/C of 1970

BETWEEN

The workmen and the management of Central Bank of India.

APPEARANCES:

Shri P. S. Nagpal, concerned workman with Sarvshri N. K. Bhalla and M. L. Basur.

Shri C. L. Chopra—*for the respondent Bank.*

AWARD

The Government of India being of the opinion that an Industrial dispute exists between the workmen and the management of the Central Bank of India, regarding the matter specified below, have referred the same to this Tribunal for adjudication—*vide* Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour & Employment Notification No. 23/79/70/LR III), dated 22nd October, 1970:—

SCHEDULE

“Whether the action of the management of the Central Bank of India in not giving the officiating chances to Shri P. S. Nagpal, clerk of their Miller Ganj Branch, Ludhiana as Special Assistant is justified? If not, to what relief is he entitled?”

2. In response to the notices issued to the parties, the concerned workman filed his statement of claim and the respondent Bank its written statement, whereafter the workman filed his replication.

3. Shri P. S. Nagpal, concerned workman, in his statement of claim has *inter alia* stated that he was the seniormost clerk amongst the clerks of the respondent Bank's Miller Ganj branch, Ludhiana and as per relevant provisions of various awards i.e. Sastry Award and subsequent awards and settlements, he as a matter of right was entitled to officiate in the senior post or junior officer or as the case may be as a special assistant, as and when occasion arose, and by virtue of that right accruing to him from the award and settlement, he being the seniormost as clerk-cum-godown keeper, was made to officiate as a special assistant in the Miller Ganj, Ludhiana, branch of the respondent bank from 5th September, 1969 to 6th September 1969 and was duly paid officiating allowance for these two days in the month of September, along with the salary of that month.

that the respondent bank without assigning any reason arbitrarily and contrary to the provisions of the awards mala fide began to ignore him when making officiating appointments as and when an opportunity arose and did not give to him officiating chances which not only caused mental agony to him but made him suffer a monetary loss whenever a person junior to him had been made to officiate as a special assistant from 7th September 1969 onwards.

that despite the representations made by him and the union, the respondent bank did not pay any heed to them and continued to deny him of availing of an officiating chance,

that in this way the respondent bank had acted in a dictatorial, biased and arbitrary manner mala fide, contrary to the principles of natural justice and equity, and

that this act of the respondent bank was not only discriminatory but a mal-labour practice, inasmuch as some clerks placed in similar circumstances as him had not been deprived of postings against senior posts and in particular Shri Thanu Ram, a clerk much junior to him, had been promoted as a junior officer in the Miller Ganj branch, Ludhiana.

4. In the written statement it has been *inter alia* stated by the respondent bank that Shri P. S. Nagpal, concerned workman, was not entitled to officiate in a senior post, or as a special assistant whenever an occasion arose as the promotion even by way of officiating chance is required to be given at the discretion of the bank while taking into consideration the stability and qualifications of the person concerned and seniority by itself does not entail a right for a person to be promoted,

that Shri Nagpal under a misapprehension had been allowed to officiate as a special assistant on 5th and 6th September, 1969 by the local branch manager without seeking any instructions from the controlling office, under pressure of the branch staff, and when the irregularity was discovered, the branch was asked by the controlling office to discontinue Shri P. S. Nagpal from officiating as a special assistant as that post involved higher responsibility, that it was only for the bank to consider who was fit for holding such a post without jeopardising their interests,

that Shri Nagpal was suspended on 19th December, 1966, having been found guilty of all the charges which were levelled against him and punishment of dismissal was first proposed by the enquiry officer, but was reduced to stoppage of two graded increments permanently, and in appeal preferred by Shri Nagpal, order of punishment was confirmed.

that thereafter Shri Nagpal filed a mercy petition to the highest authority of the bank and requested that he be given a chance to officiate as a special assistant,

that this request was turned down and he was debarred from availing of chance for officiation as a special assistant for a period of three years from the date of the order of the enquiry officer,

that Shri Nagpal, who was found guilty of manipulating records so as to provide undue facility to the customers of the respondent bank and had thereby put the bank on more than one occasion to the risk of incurring a loss, and even after he had been reinstated in the respondent bank's service in September, 1969, he had been found guilty again of tampering with the records in the same manner, thus forfeiting confidence of the respondent bank.

that Shri Nagpal had been warned several times for trying to get monetary benefits from his position in the bank, and

that Shri Nagpal had been debarred from availing of any chance for officiating as a special assistant and the next senior employees had been given such chances, and it was denied that Shri Nagpal had suffered any monetary loss or that the respondent bank had not acted bonafide and had in any way discriminated against him.

5. In the replication the concerned workman has more or less reiterated what he had stated in the statement of claim and generally refuted the contention of the management which find mention in their written statement.

6. Since the parties did not claim any other issue than the term of reference, the term of reference was framed as the only issue.

7. The respondent bank has examined only one witness, Shri V. H. Pangey, their Chief Agent at Chandigarh and the concerned workman has examined himself as a witness as also two other witnesses namely, Shri D. P. Suri, Staff Officer in the branch of the respondent bank at Chandigarh and Shri M. K. Sethi, stenotypist in the Central Bank of India, Ambala branch who had brought the summoned record relating to Shri Girhotra.

8. The question that arises for consideration is whether Shri Nagpal, concerned workman, who admittedly officiated as a special assistant for two days, i.e. on 5th and 6th September, 1969 was entitled to be given a chance of promotion on basis of seniority as claimed by him and whether he had been discriminated against in the matter of being given promotion and the action of the management in not giving a chance to him to officiate as a special assistant was malafide and that he had been victimised.

9. The fact that an enquiry was held against Shri Nagpal, which is borne out by the enquiry proceedings, Ext.M/1, and that the enquiry officer found the charges proved against him and recommended stoppage of two increments, is not denied by Shri Nagpal, concerned workman.

From the findings of the enquiry officer it is to be observed that the enquiry officer had stated that he would have confirmed the original punishment proposed by him, i.e. dismissal from service, but taking into consideration the young age, mental agony undergone during the period of suspension and plea of mercy taken by Shri Nagpal, and his representative he, (the enquiry officer) reduced the punishment to stoppage of next two increments permanently.

The aforesaid punishment imposed by the enquiry officer was confirmed by the appellate authority while dismissing appeal by an order dated 23rd October, 1969.

10. It is common ground between the parties that Shri Nagpal, concerned workman, was allowed to officiate as a special assistant for 5th and 6th September, 1969 by the Local Manager of the Miller Ganj branch, Ludhiana, of the respondent bank. According to Shri V. H. Pangey, Chief Agent of the respondent bank, ordinarily when a branch makes an officiating appointment, they secure approval of the controlling Agent, i.e. Chief Agent, but this had not been done in the case of Shri Nagpal and Shri Nagpal had been allowed to officiate with disregard of the directions as contained in Ext.R/2, and that when he (Shri Pangey) came to know of it in due course i.e. about the officiating chance having been given to Shri Nagpal, he sent an intimation to the Local Manager, that Shri Nagpal should not be allowed to officiate as a special assistant from 7th September, 1969.

11. Ext.R/2, an order passed by the Superintendent dated 19th November, 1969, has a mention that the appeal, dated 22nd September, 1969, preferred by Shri Nagpal, against the findings and orders of the enquiry officer had already been disposed of by the appellate authority, Mr. K. Venkataraman, on 23rd October, 1969, Shri Nagpal had after the dismissal of appeal submitted a mercy petition on 8th November, 1969 and requested that he be allowed to officiate as special assistant being the senior-most clerk, and in para 6 of the order Ext.R/2 it is mentioned that in the case of Shri Nagpal enquiry had been held in respect of certain acts of gross misconduct on his part and that he should not be given any chance for officiating as a special assistant for a period of three years, from the date of the orders of the enquiry officer.

It is note-worthy that the above stated orders as contained in Ext.R/2 are dated 19th November, 1969, whereas Shri Pangey has stated that Local Manager of the Miller Ganj Branch, Ludhiana had allowed officiating chance as special assistant to Shri Nagpal on 5th and 6th September, 1969 in utter disregard of the directions contained in the memo, Ext. R/2, which order as has been pointed out above was passed nearly one and a half months afterwards and as such the Local Manager could not be expected to have taken any such document into consideration, which obviously did not exist at that time.

12. The contention of the workman is that as has been mentioned in the statement of claim, in order to appease the rival recognised union, which is the majority union, the respondent bank had victimised him and mala fide deprived him of chance to officiate as a special assistant, while appearing as a witness, he has not only reiterated this plea but has added that he was told by the Manager of the local branch, Shri M. L. Jain, that he could not be allowed to officiate as a special assistant, as the rival recognised union had put pressure upon him (Mr. Jain) not to allow him (Shri Nagpal) to officiate in that capacity, and though Shri M. L. Jain, had been cited as a witness by the respondent management, but they had not examined him, presumably for the reason that if he had appeared, he would have been confronted with the awkward situation of having to admit the fact that it was because of the pressure of the rival recognised union, that Shri Nagpal had not been allowed to officiate as a special assistant.

This allegation of the workman finds further support from the footnote on the charge-sheet, Ext. A/13, wherein it is mentioned that the enquiry officer had been appointed by the respondent management after consulting the rival recognised union and also from letters, Ext.A/9 to A/12, written by the rival recognised union to the respondent bank against Shri Nagpal and in particular from the complaint, Ext.A/12, sent by the General Secretary of the rival union that Shri Nagpal had misbehaved with the chowkidar and nearly one year afterwards it was ordered by the respondent bank that Shri Nagpal be charge-sheeted and an enquiry be held against him, and all that had been manoeuvred so as to mar the service record of Shri Nagpal and to deprive him of a chance to officiate as a special assistant.

It may be mentioned in this connection that Shri Nagpal made a representation Ext.A/1 to the Chief Agent of the respondent bank that he being the senior-most clerk was competent to avail of a chance as a special assistant, and the union had also sent a letter Ext.A/2 to the Regional Manager in this behalf.

The concerned workman has further alleged that by his having been deprived of an officiating chance, he had suffered a loss upto Rs. 200/- per month i.e. by giving some chances to his juniors Sarvashri S. S. Sareen, R. K. Sehgal, O. P. Kulra, and Thanu Ram to officiate as special assistant, and also that about 10 or 12 other juniors had been promoted in preference to him.

The authorised representative of the respondent management has referred to para 5(d) of the Memorandum of agreement regarding promotion policy of clerical and subordinate staff and selection of posts carrying special allowance under the

bipartite settlement between the Central Bank of India and the All India Central Bank Employees Federation, which lays down as under:—

"An employee punished for gross misconduct as provided in the bipartite settlement will be debarred from promotion from the date of punishment."

The so-called memo of agreement, regarding promotion policy, referred to above, is a printed document and has not been got proved by any witness, and legally speaking has no value and as such has to be ignored.

In 1964—II—L. L. J.—347 it has been inter alia laid down:—

"Para 529 of the Sastri award inter alia lays down that promotion is not a matter which could be made automatic. A great deal of discretion, in its very nature, must rest with the management in this connection. It further lays down that it is not only difficult but very undesirable to lay down any single principle for the exercise of such discretion. If the employer who is carrying on a business uses his discretion bonafide and according to the principles laid down in the rules, it is not for the Tribunal itself to evaluate the respective qualifications of the workmen concerned, and come to the conclusion as to whether a particular workman was best suited for a specified job. It has also been laid down in para 529 that seniority alone is not everything. The other factors are efficiency, educational qualifications, character and the nature of responsibility required in connection with the vacancies to be filled in. Once it is conceded that in such matters discretion lies primarily with the management, it follows as a corollary that it is for the management to come to the conclusion as to whether a person is suitable for being appointed to particular job in the back ground of what performance is expected from him and to make any appointment which will be of the benefit to employer's business. If this discretion exercised honestly and keeping in view the various directions mentioned in the Sastry award, then it is not for the tribunal to substitute its own opinion in the place of the management."

In 1966 A.I.R.—Vol.—53—S.C.—688, it has been inter alia laid down that promotion is a function of the management and discretion is with the management unless it were to be shown that the action of the management was that of victimisation or malafide.

13. As has been stated above, Shri Nagpal, concerned workman, was given promotion as a special assistant for 5th and 6th September, 1969 and since the chance of promotion had been withdrawn on 7th September, 1969, it tantamount to punishment with penal consequences and all this had been done without providing any opportunity to Shri Nagpal to show cause.

14. The only witness produced by the respondent management, Shri V. N. Pangey, has not categorically stated that the Manager of the local branch was not competent to give a promotion chance to Shri Nagpal, but has maintained that the manager should have secured approval of the Chief Agent of the respondent bank.

15. This apart, there is nothing on the record to show that the adverse findings, the one contained in para 6 of Ext.R/2, reproduced above on the basis of which Shri Nagpal is said to have been deprived of promotion chance for three years, was ever communicated to Shri Nagpal. No punishment, what to say a punishment of far reaching consequence, can be or ought to be awarded behind one's back, without providing such a person with an opportunity to show cause, and since such an opportunity has not been afforded to Shri Nagpal, there is violation of principles of natural justice.

The fact of the matter is that, as has been admitted by the respondent bank, the enquiry officer had imposed a punishment for alleged misconduct of Shri Nagpal i.e. stoppage of increment for two years, and this punishment was confirmed on appeal and the respondent bank could not thereafter proceed to award a second punishment i.e. debarring him from promotion chance for three years as is to be found from para 6 of Ext. R/2, and that too without providing any opportunity to show cause and it has been claimed by the workman that this is also in violation of the Sastri award.

16. In this connection it may be reiterated that as has been pointed out earlier, Shri Nagpal had been deprived of an officiating chance on 7th September, 1969, when there was no such bar to his being given a chance of promotion as special assistant inasmuch as the bar had been imposed subsequently i.e. on 19th September, 1969 vide para 6 of Ext. R/2 and there was thus no justification for the

respondent bank to have deprived Shri Nagpal of officiating as a special assistant when he had already been allowed to do so on 5th and 6th September, 1969.

17. As regards officiation, in 1970-Labour & Industrial Cases-50, it has been held by the Orissa High Court as under:—

“Officiation in a higher post is ordinarily allowed to test the suitability of a servant, and rendition of satisfactory service in the officiating post is the since quanon for continuation therein, ultimately leading to a substantive promotion of the incumbent to such higher post. To us it appears that the test of the efficiency or suitability of the incumbent is inherent in the process of officiation, and the officiation normally ends up in reversion of the incumbent in case he does not render satisfactory service during officiation.”

It is pertinent to mention that in the case of Shri Lakhi Ram, an employee of the respondent management, who was charge-sheeted vide Ext. A/10 and an enquiry was held as per copy of the enquiry proceedings, Ext. A/21, the respondent bank had acted in a different manner than in the case of Shri Nagpal, which also goes to show that the management had discriminated against Shri Nagpal.

From the statement of Shri M. K. Sethi, it is to be found that Shri Lakhi Ram, godown keeper, was suspended from service on 19th September, 1963 as per Ext. A/15; was discharged from service on 5-5-64 vide Ext. A/16; was re-instated on the basis of a settlement before the Labour Court, that he had officiated as a special assistant from 3rd April, 1969 to 7th April, 1969 vide Ext. A/17, and that he was subsequently promoted as a junior officer vide Ext. A/19. The basis of settlement between Lakhi Ram and the respondent management has not been made known but it is more than clear from the statement made by Shri M. K. Sethi that Shri Lakhi Ram had in fact been discharged from service and thereafter not only reinstated on basis of settlement but subsequently promoted as a junior officer.

18. The concerned workman has also made a grievance of the fact that a number of officials junior to him had been given chances of promotion, which has not been denied by the respondent management's witness Shri V. H. Pangey and that in that way too he has been discriminated against.

While taking into consideration the manner in which the respondent bank has acted in the case of Shri Lakhi Ram and the fact that a number of employees junior to the concerned workman, Shri Nagpal, had been preferred to him while giving chance of promotion, the respondent management has acted in a manner which is not consistent with the principles of natural justice, and appears to have been actuated by malice or at the behest of the rival recognised union which is a majority union.

Shri Pangey who is the only witness that has been examined by the respondent management, has not denied that the rival recognised union had sent a number of complaints to the respondent bank and acting on one such complaint, Ext. A/1, nearly after a year, they had ordered an enquiry to be held against Shri Nagpal.

Besides from the foot note on Ext. A/13, it is to be found that the respondent bank had appointed an enquiry officer to hold enquiry against Shri Nagpal with the consultation of the rival recognised union, and it has also been stated by Shri Nagpal in his statement while appearing as a witness that Shri M. L. Jain, the Local Branch Manager had told him that he had to discontinue his (Mr. Nagpal's) promotion chance as special assistant because of pressure put upon him by the rival recognised majority union.

From all this it can be safely concluded that the rival recognised union was out to mar the career of Shri Nagpal and the respondent bank in order to appease them discriminated against the concerned workman.

In this connection it may be mentioned that in order to prejudice the cause of Shri Nagpal it has been stated by Shri Pandey that two departmental enquiries, were pending against Shri Nagpal, relating to his late coming and man-handling the Chief Agent, but he has had to admit that only one charge sheet had been given so far to Shri Nagpal and that too was a day prior to the day when the present reference was made though according to him memos had been issued earlier in respect of the first charge-sheet.

However, these two departmental enquiries can have no bearing on the present term of reference. In any case their fate is known.

19. The plea taken by the management is that the stoppage of promotion for three years was only a corollary of the first punishment i.e. stoppage of increment for two years, and was in consequence of the punishment imposed by the enquiry officer by way of stoppage of two increments, is clearly untenable for the reasons already given.

20. Having regard to what has been stated above Shri Nagpal is justified in claiming that it is a case of victimisation, discrimination and mala fide and that he was entitled to be given a promotion chance. The observations made by their Lordships of the Supreme Court in 1966—A.I.R.-Vol.-3-668 reproduced earlier are most relevant in this connection.

It is as such held that the action of the respondent management in not giving a chance of promotion to Shri Nagpal to officiate as a special assistant is not justified and he is entitled to be given such a chance.

As regards the claim of Shri Nagpal that he had suffered about Rs.200/-P.M as monetary loss on account of his having been deprived of the promotion chance, he has not placed any satisfactory material on the record to prove what actual loss he may have had to suffer. On the contrary, the respondent management have placed on record a statement which shows that in all Rs. 391.74 paise were paid to different persons junior to Shri Nagpal, for their having officiated as special assistants during the period 1-9-69 to 28-9-70.

In the absence of any satisfactory material having been made available by Shri Nagpal about the actual pecuniary loss alleged to have been suffered by him it is not possible to grant to him appropriate relief in this behalf.

The parties are left to bear their own costs.

The 30th June, 1971.

(Sd.) P. P. R. SAWHNY,

Presiding Officer,
Industrial Tribunal, Central, Chandigarh,

[No. 23/79/70/LRIII.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 12th July 1971

S.O. 2799.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of Shri A. K. Ray, Director (Finance), National Coal Development Corporation Limited, Arbitrator in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Electrical and Mechanical Workshop, National Coal Development Corporation Limited, Post Office Korba Colliery, District Bilaspur, Madhya Pradesh and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st July, 1971.

IN THE MATTER OF AN ARBITRATION

BETWEEN

Employers in Relation to Central Electrical and Mechanical Workshop,
National Coal Development Corporation Limited, Korba,

AND

Their Workmen Represented by the National Coal Organisation Employees Association, Central Electrical and Mechanical Workshop Branch, Korba.

[Vide Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour & Employment) Notification No. 5/9/70-LRII, dated 19th September, 1970].

AWARD

An industrial dispute between the employers in relation to the Central Electrical and Mechanical Workshop, National Coal Development Corporation Ltd., Korba, and their Workmen, represented by the National Coal Organisation Employees Association, Central Electrical and Mechanical Workshop, Korba, occurring in 1970, was referred to me for arbitration under Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment), New Delhi, Notification No. 5/9/70-LRII, dated 19th August, 1970.

2. The specific matters in dispute, as recorded in the agreement between the two parties dated 30th May, 1970 and reproduced in the enclosure to Notification No. 5/9/70-LRII of 19th August, 1970, referred to above, were:

"Keeping in view the Office Orders No. 100/TRG/64 dated 7th August, 1964 and 26th August, 1964 what should be the rules by which the under-noted workmen of the Central Electrical and Mechanical Workshop, NCDC Ltd., Korba, should be guided and what should be the relief to which these workmen are entitled?

1. Shri Jamuna Prasad, Fitter (Mechanical)
2. Shri R. C. Thakur, Fitter (Mechanical)
3. Shri A. Thakur, Fitter (Mechanical)
4. Shri B. P. Singh, Fitter (Mechanical)
5. Shri M. R. Ansari, Fitter (Mechanical).

3. The two parties to the dispute filed before me written statements and various documents in support of their cases. They also made verbal submissions as considered necessary by them in support of their contentions.

4. Arbitration proceedings were held at "Dharbhanga House", Ranchi, on—

15-12-70	at	3-30 P. M.
19-3-71	at	3-30 P. M.
17-5-71	at	11-00 A. M.
2-6-71	at	11-00 A. M.
3-6-71	at	10-00 A. M.
and		
9-6-71	at	3-30 P. M.

5. The time for giving of the Award was extended by mutual consent of the parties from time to time upto the 30th of June 1971.

6.1. The facts of the case appear to be as follows:

6.2. The workmen concerned were appointed as Trainees (Course—I Mechanical Fitters, Opencast) in the Mining Training School of N.C.D.C. Ltd., under the terms and conditions governing such training as given in the Prospectus of the said Training School. Briefly, these required the persons admitted to the Training Course to execute a bond for a specified period, with a surety, undertaking to complete the course of training and to serve the Corporation on successful completion of training in an appropriate post for a minimum period of five years. No employment to the successful Trainees was, however, guaranteed. Subject to availability of vacancies, such successful Trainees would be eligible for appointment in Category VII under the LAT Award on trial for six months. On satisfactory completion of this trial period, they would be promoted to Category IX of the LAT Award. The trial period could be extended by another six months if the ex-trainees' performance was not considered satisfactory by the management. If the performance continued, to be unsatisfactory even during the extended period, the persons would be discharged. The relevant provisions of the MTS Prospectus are reproduced below—

"Part A—Prospectus:

6. Candidates found suitable for admission would be required to submit a bond with a surety for an equal amount undertaking to complete the course of training and to serve the Corporation on successful completion of the training in appropriate post for a minimum period of five years.

The Management does not guarantee employment to successful trainees of various courses. Employment will, however, be offered to successful trainees against vacancies that may arise from time to time (Page 2).

Details of Courses—Course—I Fitters—Mechanical/Electrical

8. Scope of Employment:

Trainees, who obtain the National Coal Development Corporation Certificate, will, subject to vacancies, be eligible for appointment in Category VII under the L.A.T. Award, on trial for six months. On satisfactory completion of this trial period they will be promoted to Category IX of the L.A.T. Award.

Where the Management is of the opinion that an ex-trainee has not proved satisfactory during the trial period of six months in Category VII, the period will be further extended by another six months, if after the extended period also the trainee fails to prove satisfactory he would be discharged (Pages 5 and 6).

6.3. The five employees involved in the dispute executed the required bonds and on completion of the prescribed course of training in or about August 1964 were posted under office Order No. 100/TRG/64, dated 7th August, 1964 (copy enclosed as Annexure-I) as follows:—

1. Shri Ayodhya Thakur—Singrauli
2. Shri Md. Mojibur Rehman Ansari—Singrauli
3. Shri Birendra Pd. Singh—South Balanda.
4. Shri Ram Chandra Thakur—South Balanda.
5. Shri Jamuna Prasad—South Balanda.

6.4. It seems that these Projects were not in a position to accept the placement of these employees. The Orders dated 7th August, 1964 were thereafter superseded under orders dated 26th August, 1964 (copy enclosed as Annexure-II) in accordance with which these employees were posted at Gidi Washery of NCDC. The Area General Manager, Kawanpura, in his letter No. E/Surplus-PH/64/25515-16 dated 5/8th September, 1964 (copy enclosed as Annexure-III.) did not accept these placements and requested withholding of the release of these Fitters. They were thereafter directed to report to Bhurkunda Colliery of the NCDC. Under covering sanction conveyed in order No. 100/TRG/64, dated the 26th November, 1964, (copy enclosed as Annexure-IV) these employees were treated as posted at Bhurkunda Colliery, w.e.f. 17th August, 1964, till the date of their absorption against the sanctioned posts. The expenditure on their wages etc. were to be, however, booked under the head "253-A (Tech. Training Scheme) (d) Salary and allowances to passed-out trainees." Thus these five persons appeared to have been paid Category VII wages from or about the date of their passing out of the Training School sometime early in August 1964 even though their actual placement seemed to have been later.

6.5. All these five employees were released from their bonds and given 'No Objection' certificates under identical Orders of Joint Chief Mining Engineer (Training) dated 31st August, 1965 (copy enclosed as Annexure-V). They were also released from their "further training" and the terms of the bond executed by them under Office Order No. 100/TRG/64/4638-64 dated 1st September, 1965 (copy enclosed as Annexure-VI). Thereafter, all of them applied on the 15th October 1965, and three of them again on 25th October, 1965 asking to be considered for appointment in the Central E & M Workshop, Korba (copies enclosed as Annexures VII and VIII). Under Office Order No. 100/TRG/64 dated 10th January 1966 (copy enclosed as Annexure-IX) these employees were posted to Central Workshop, Korba, under Category IX of the L.A.T. Award; this order also stated that they would be guided by LAT Award for service conditions etc.

7.1. The representatives of the workmen and of the employer made their submissions through written statements of case as well as orally. They also cited a number of legal rulings in support of their contentions. The main points urged by the two parties are briefly indicated below.

7.2. It was stated on behalf of the management that the present industrial dispute arose from a reference made by the Asstt. Secretary (A) N.C.O.E.A., Central Electrical & Mechanical Workshop, Korba, to the Asstt. Labour Commissioner (C), Bilaspur, in February, 1970. The employees had been appointed in the Central Elec. & Mech. Workshop, Korba, under Office Order No. 100/TRG/64 dated 10th January, 1966 (Annexure IX) which indicates the terms and conditions of such appointment. Since the employees had accepted these terms and conditions over a period of four years their right to raise any dispute stood waived by efflux of time.

7.3. The management had no obligation to guarantee employment to passed-out trainees from the Mining Training School of the N.C.D.C. No vacancies for placement of these employees were available after they had successfully completed the prescribed course of training. Office Order No. 100/TRG/64 dated 26th August, 1964 (Annexure-II) indicated that the trainees will be appointed on the terms and conditions specified therein. No specific appointment order in pursuance of this was issued. The management tried to obtain placement for these trainees at various projects but since such efforts were not successful they were placed under "training" at Bhurkunda Colliery. During such period of extended training their wages and allowances were debitable to the Training Scheme. In effect, these employees were retained as paid Apprentices.

7.4. Subsequently such further training was terminated w.e.f. 1st September, 1965; the employees were released from the training and the bonds executed by them. Prior to such release they were given 'No objection' certificates for applying for outside jobs. This was no retrenchment as the workers had not been

appointed to any posts. Even if these workers were to be viewed as having been on probation, no orders making them permanent on the expiry of probationary period was issued. This meant that their probationary period was extended and thereafter terminated.

7.5. Their earlier arrangement for training and subsequent chances of employment in N.C.D.C. thus came to an end from 1st September, 1965. These circumstances were known and admitted, and, therefore, can be taken to have been accepted by the employees who applied for fresh appointment in N.C.D.C. on the 15th and 25th October, 1965.

7.6. Their appointment under Office Order No. 100/TRG/64 dated 10th January, 1966 (Annexure IX) represents the commencement of a second and an entirely separate and fresh chapter. These were fresh appointments with self-contained terms and were at par with the workers recruited afresh from open market. The word 'posted' used in the Order of 10th January, 1966 also means 'appointment as per the dictionary meaning of that word.

7.7. The jurisdiction of the arbitrator is confined to the terms of reference. Since the operation of the provisions contained in Office Order No. 100/TRG/64 dated 7th August, 1964 and 26th August, 1964 (Annexures I & II) came to an end with the termination of connection between the N.C.D.C. and the workmen concerned w.e.f. 1st September, 1965, the question of these workmen being governed by the Corporation Rules on their fresh appointment in the Central Electrical and Mechanical Workshop, Korba, did not arise.

7.8. The representative of the management urged that even otherwise the words "Corporation Rules which may be in force from time to time" occurring in the Order No. 100/TRG/64 dated 26th August 1964 have to be considered in its proper context. The National Coal Development Corporation was established as a Government Company with effect from 1st October, 1956 with eleven State Railway Collieries then in existence which, along with the employees, the Corporation took over. Such employees fell in two broad categories, viz., daily rated including price rated workers, and monthly rated employees. The monthly rated employees also fell in two categories—(a) persons governed by Railway Rules, and (b) persons governed by Civil Rules. Their continued governance by such rules as these stood on 30th September, 1956 was guaranteed by the Corporation. Monthly rated employees recruited on or after 1st October, 1956 were initially recruited on the condition that their service conditions would be the same as for corresponding temporary Central Government employees. The Board of the Corporation in its meeting held on 5th December, 1958 finalised the Corporation Rules which made provisions for terms and conditions of service, Staff Provident Fund Rules, leave rules, conduct and Discipline Rules, etc., for monthly rated employees recruited on or after 1st October, 1956. The Corporation Rules were, therefore, applicable only to monthly rated employees. Daily rated and piece rated workers in the service of the State Railway Collieries till 30th September, 1956 were governed by the Wage structure, paid holidays, etc. as per the various Awards. For annual leave they were governed by the Mines Act. So far as the Conduct and Discipline Rules were concerned, certified standing orders applied. Therefore, the Corporation Rules did not apply to the daily rated employees and at the relevant time there was no case in which daily rated employees had been given the benefit of service conditions as applicable to monthly rated employees under the Corporation Rules.

7.9. The expression "Corporation Rules" may also be interpreted to refer to certified standing Orders as these are also rules framed by the Corporation except that they had been certified by the certifying authority under the Industrial Employment (Standing Orders) Act. The workmen themselves accepted the position inasmuch as they became contributors to the Coal Mines Provident Fund while at Bhurkunda colliery. Further the words "Corporation rules which may be in force from time to time" occurring in Office Order No. 100/TRG/64 dated 26th August, 1964 could also mean the Corporation Rules which may be applicable to the employees at the relevant time.

8.1. It was urged on behalf of the workmen that the trainees under the Mining Training School Scheme had to execute bonds to serve the NCDC, if so required, five years on successful completion of training. This enjoined a corresponding obligation on the Corporation to provide employment to the successful trainees for an equivalent period of five years.

8.2. Under the conditions embodied in the Prospectus of the NCDC's Mining Training School, passed out trainees were to be initially appointed on trial for six months which could be extended by another six months if the ex-trainees' performance was not considered satisfactory. If after the extended period also the

trainee failed to perform satisfactorily, he would be discharged. There is, however, no provision in the Corporation's own Scheme for further training after a candidate has passed out from the M.T.S. The workmen concerned have therefore to be viewed as having been appointed on probation under orders No. 100/TRG/64 dated 7th August, 1964 and 26th August 1964. They were not informed about their performance being unsatisfactory during such probationary period. On the other hand, their services were terminated with effect from 1st September, 1965 which was about a month after the maximum permissible 12 months' probationary period had been completed. Even if it is conceded for arguments sake that the workmen concerned were governed by certified standing orders then the permissible probationary period would have been three months and termination of their services in the manner done would not be valid. Since the workmen concerned had the right to be provided with employment under NCDC for a minimum period of five years after the successful completion of the training and as termination of their services on 1st September, 1965 was not valid, their appointment under Order No. 100/TRG/64 dated 10th January, 1966 would be a continuation of the earlier appointment under the orders No. 100/TRG/64 dated 7th August, 1964 and 26th August, 1964. Consequently, their service conditions continue to be governed by Corporation Rules as provided in the orders dated 7th August, 1964 and 26th August, 1964.

8.3. It was open to the Corporation to give these workmen, though daily rated, the benefit of being covered by the Corporation Service rules. Mining Training School trainees who had executed bonds before 15th August, 1967 were allowed to enjoy benefits of Corporation service conditions.

8.4. The argument of the representative of the management that these workmen were to be viewed as paid apprentices does not stand scrutiny. Apprentices are given specific allowances and not wages. The various orders commencing with Orders No. 100/TRG/64 dated 7th August, 1964 and 26th August, 1964 describe these passed out trainees as Mechanical Fitters (O.C.). Subsequent orders do not materially affect this position.

8.5. Apart from extension of probationary period beyond six months without any communication about unsatisfactory performance to the workmen concerned, the action to do away with their services with effect from 1st September, 1965, after the 12 months' probationary period was exceeded by another month or so, was *mala fide*. It was obligatory on the part of the management to continue the workmen in employment on their completion of the probationary period; no evidence has been brought on record to prove that this could not be done because of lack of vacancies. On the other hand, Corporation Rules, under which these workmen were governed at that time, do not permit termination of the services of a probationer after the expiry of the probationary period, otherwise than by way of punishment. Therefore, the refusal to give category IX wages to these workmen or their release from employment really constitutes lay-off or lock-out.

8.6. The term "time to time" referred to in the context of the words "will be guided by Corporation Rules which may be in force from time to time" cannot be interpreted to mean that the workmen concerned would be governed by the standing orders. Certified Standing Orders also cannot be taken as Corporation Rules.

8.7. The Arbitrator's jurisdiction in an industrial dispute is not restricted to his terms of reference and he is not to be governed by merely technical or legalistic considerations. The principles of natural justice have to be followed with the object of maintaining industrial peace and progress. Since the dispute in question has been referred to Arbitration, there is no force in the Management's contention that the workmen's right to raise dispute stands waived by efflux of time.

8.8. In that view and as the release of these workmen from employment on 1st September, 1965 was not in order, their further employment from 10th January, 1966 should be deemed as continuous and they would be eligible to be governed by Corporation Rules in respect of earned leave, conduct and discipline rules, paid holidays, casual leave, etc.

9.1. The various points urged and the evidence adduced by the two parties, whether briefly recounted at paras 7 and 8 above or not, have been carefully examined by me. I have considered the issues involved from the point of view of equity and natural justice rather than on merely technical and legalistic grounds.

9.2. The management's contention that the workmen's right to raise the dispute in question stands waived by efflux of time is not, in my opinion, tenable.

9.3. The deployment of the five workmen, *viz.*, S/Shri (1) Jamuna Prasad, (2) R. C. Thakur, (3) A. Thakur, (4) B. P. Singh, and (5) M. R. Ansari, on further training after they had passed out of the Mining Training School of the Corporation is not in accordance with the NCDC's own Scheme in this regard. They cannot also be considered as paid apprentices. It was agreed by the representative of the management that these arrangements were certainly extraordinary. For practical purposes, therefore, they have to be viewed as having been appointed under the NCDC's Office Order No. 100/TRG/64 dated 7th August, 1964 as superseded by Office Order No. 100/TRG/64 dated 26th August, 1964. Their release from employment nearly a month after the expiry of the maximum probationary period provided in the above orders is somewhat unusual even though specific orders on their confirmation had not been issued. The management of the Corporation cannot certainly be complimented on the manner in which they dealt with these cases. On the other hand, there is no validity in the contention that, because of the execution of the bond, there was a corresponding obligation on the part of the Corporation to provide the concerned workmen with employment for a minimum period of five years. The same para of the Mining Training School prospectus which called for execution of the bonds by the trainees says that the "Management does not guarantee employment to successful trainees of the various courses."

9.4. The point which logically next comes in for consideration is the implication of the words "will be guided by the Corporation Rules which may be in force from time to time" occurring in Office Order No. 100/TRG/64 dated 7th August, 1964 as superseded by Office Order No. 100/TRG/64 dated 26th August, 1964. Though the term "Corporation Rules" may perhaps be theoretically construed to mean appropriate applicable rules to different categories of employees, there is no denying the fact that, by usage, in the NCDC the words "Corporation Rules" refer to the body of Printed and Published Rules of that description containing terms and conditions of service, Leave Rules, Conduct and Discipline Rules, etc., applicable to monthly paid employees *i.e.*, staff and officers. The contention of the employer that these words could also mean applicability of Certified Standing Orders has, in my opinion, very little force.

9.5. While this would appear to be the technical position, the matter has also to be viewed in the context of the general position in this regard then obtaining in the Corporation. From the statements made and evidence adduced in the Arbitration it does not appear that when the orders dated 7th August, 1964 and 26th August, 1964 were issued, any daily rated employee of the Corporation was governed by Corporation Rules. A decision to give such a benefit to a few specified daily rated employees could hardly be taken at a level lower than that of the Top Management of the Corporation as such a decision, if it were not to be discriminatory and lead to industrial unrest, would have been issued as a general order of universal applicability at the appropriate level. Obviously therefore, the mention of the workmen concerned as being guided by Corporation Rules is indicative of an inadequate if not loosely worded order issued by an officer of the Corporation not normally authorised to take a decision of such a magnitude.

9.6. Nevertheless, on a literal interpretation of these words, the five workmen concerned could claim to be governed by Corporation Rules. But if reliance is placed on such an approach, it is possible to hold a view that under the Corporation's Conduct and Discipline Rules their release would be cases of termination of service at the end of period of probation, not constituting penalties. The absence of specific orders of confirmation, and the small time-lag between the expiry of 12 months probationary period and actual termination of service may enforce such a conclusion. It is also possible to hold a view that these were cases of termination of services on reduction of establishment as permissible under Corporation Rules.

9.7. Considering the matter from the point of view of equity, it would have been unusual to grant the benefit of being governed by Corporation Rules to a handful of daily rated workmen when all other daily rated workmen in the Corporation were not allowed the same benefit. It is true that, taking the orders in question literally, the workmen in question have to be viewed as having been governed by Corporation Rules on their appointment under the order dated 26th August 1964. In that event I do not find sufficient material to question the validity of the termination of their services with effect from 1st September, 1965 under the permissible provisions of Corporation Rules. Therefore, their appointment in the Korba Central Elec. and Mech. Workshop under the orders dated 10th January, 1966 has to be viewed as fresh appointment. Enquiry, however, warrants that the workmen concerned should be given some compensation for the somewhat unusual termination of the earlier appointments.

10. On an overall consideration of the matter I hold that the workmen concerned are not eligible to be governed by Corporation Rules as regards their service conditions on appointment as Fitters (Mechanical) in the Central Electrical and Mechanical Workshop, Korba. They shall be governed by the same rules as are applicable to other similar directly recruited daily rated employees in that Workshop. The termination of their employment with effect from 1st September, 1965 was, however, somewhat unusual for which some compensation has to be allowed. The Management should condone the break in their service between 1st September, 1965 and the date of their joining the posts in the Korba Central Electrical and Mechanical Workshop by grant of leave due or leave without pay, as found possible. The purpose of such condonation would be to enable any benefits relating to emoluments like increment, gratuity, which accrued to these workmen because of service in Bhurkunda colliery being carried forward in their fresh appointment in the Central Electrical and Mechanical Workshop, Korba.

(Sd.) A. K. RAY,
Arbitrator.
25-6-71.

Darbhangha House,
Ranchi.

ANNEXURE I

NATIONAL COAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED DARBHANGA HOUSE, RANCHI

No. 100/TRG/64.

Dated, the 7th August, 1964.

OFFICE ORDER

The passed out trainees of Course I Batch 5 of M.T. School, Giridih and Course I Batch 7 of M.T. School Bhurkunda are posted at the collieries/projects shown against their names in the enclosed list on the following terms and conditions:—

- (1) The passed out trainees will be employed as Elec. U.G./Mechanical Fitter (Diesel Engine or O.C. as the case may be) under the Category VII of L.A.T. Award on probation for six months. After successful completion of their probationary period they will be eligible for appointment under Category IX of L.A.T. Award as per existing rules.
- (2) If the services of a passed out trainee is not found satisfactory his probation period may be extended for another six months. If after the extended period also he fails to prove satisfactory he would be discharged.
- (3) He will be guided by the Corporation Rules which may be in force from time to time.
- (4) The passed out trainees are allowed 7 days joining time with effect from the date of their release from the school so that they may be appointed in the retrospective effect i.e. the next day from the date of their release.

Encl: List.

(Sd.) J. M. DHAWAN,
Jt. Chief Mining Engineer (Production)
and Director of Training.

Distribution :

1. A.G.M. (Orissa) Talcher.
2. A.G.M. (Korba), Korba.
3. C.E. (E&M) Ranchi
4. C.P.O. (PD)
5. Dy. S.O.C. Singrauli
6. Dy. S.O.C. South Balanda.
7. Project Officer, Monjidi/Sudamdih.
8. Regional Accounts Officer, (MP), Baikunthpur/
Orissa, Talcher Korba (Korba)
9. Accounts Officer (HO) Ranchi.
10. Principal, M.T.S. Bhurkunda.
11. Officer-in-charge M.T.S. Giridih.

This issues with the approval
of M.D. For information and
necessary action.

ANNEXURE II

NATIONAL COAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
DARBHANGA HOUSE: RANCHI

No. 100/TRG/64.

Dated the 26th August, 1964.

OFFICE ORDER

In supersession of this Office order of even No. dated 7th August, 1964 the following passed out Bhurkunda are posted at Gidi Washery/Central Workshop, as shown against their names as mentioned below:—

1. Mechanical Fitter (O.C.)

1. Shri Ayodhya Thakur	Gidi Washery.
2. Shri Md. Mojibur Rehman Ansari	Gidi Washery.
3. Shri Birendra Prasad Singh	Gidi Washery.
4. Shri Ram Chandra Thakur	Gidi Washery.
5. Shri Jamuna Prasad	Gidi Washery.

Mechanical Fitter (Diesel Engine)

1. Shri Abisalam Mundu	Central Workshop, Barkakana.
2. Shri Raphael Turi	Central Workshop, Barkakana.

The above trainees will be appointed on the following terms and conditions:—

They will be employed under category VII of L.A.T. Award on probation for six months. After successful completion of their probationary period they will be eligible for appointment under category IX of L.A.T. Award as per existing rules, if they are found fit for promotion to Category IX.

2. If the services of a passed out trainee is not found satisfactory his probation period may be extended for another six months. If after the extended period also he fails to prove satisfactory he would be discharged.

3. He will be guided by the Corporation rules which may be in force from time to time.

4. The trainees are allowed 7 days joining time with effect from the school so that they may be appointed in the retrospective effect i.e. the next day from the date of their release.

(Sd.) J. M. DHAWAN,

Jt. Chief Mining Engineer (Production).

Distribution :

1. A.G.M. Talcher.
 2. CE (E&M) Ranchi
 3. C.P.O. (C.D.), Ranchi.
 4. Dy. S.O.C. Singrauli
 5. Dy. S.O.C. South Balasore.
 6. Regional Accounts Officer, Talcher
 7. Accounts Officer (HQ) Ranchi.
 8. Project Officer, Gidi Washery.
 9. Supdt. Central Workshop, Barkakana.
 10. Principal, M.T.S. Bhurkunda.
 11. AGM (K)
- Copy to :—
12. Shri Abisalam Mundu.
 13. Shri Raphael Turi.

For information and necessary action.

ANNEXURE III

NATIONAL COAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Office of the Area General Manager (K)

ARGADA

No. E/Surplus-PII/64/25615-16.

Dated 5/31th September, 1964.

To

The Principal,

M.T. School, Bhurkunda.

Re: Placement

Dear Sir,

Please refer to your letter No. Placement/64/2935-42, dated 31st August, 1964 addressed to S/Shri Birendra Pd. Singh Ram Chandra Thakur and Jamuna Prasad, Course I Batch 7, Mechanical Fitters, M.T. School, Bhurkunda.

Please note that I do not require the services of Open Cast Fitters and I have already informed Mr. Murthy about this. You are requested to withhold the release of these fitters.

Yours faithfully,

(Sd.) C. BALRAM,

AGM (K)

Copy to:— Jt. C.M.C. (Production) NCDC, Ranchi

ANNEXURE IV

NATIONAL COAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

DARBHANGA HOUSE: RANCHI

No. 100/TRG/64.

Dated the 26th November, 1964.

This is to convey the sanction of the Dy. General Manager for the payment of Wages category VII of L.A.T. Award to the following passed out trainees of Course-I Batch 7 with effect from 17th August, 1964 till the date of their absorption against the sanctioned posts.

MECH. FITTER O.C.

POSTED AT

1. Shri Ayodhya Thakur.
2. Shri Mojcebur Rahman Ansari
3. Shri Ram Chandra Thakur.
4. Shri Jamuna Prasad.
5. Shri Birendra Prasad Singh.

}
}
}
}
}

Bhurkunda Colliery.

Mech. Fitter (Diesel)

1. Shri Abisalan Munda.
2. Shri Raphael Tiru.

}
}

Central Workshop,
Barkakana.

The expenditure may be charged to the following head of Accounts:—

253-A (Tech. Training Scheme)

(d) Salary and allowances to passed out trainees.

This issues with the concurrence of the Finance.

(Sd.) J. M. DHAWAN,

Jt. Chief Mining Engineer (Production)
and Director of Training

Distribution :

1. Dy. Supdt. of Collieries, Bhurkunda.
2. Superintendent, Central Workshop, Barkakana.
3. Principal, M.T. School, Bhurkunda.
4. Chief Personnel Officer (PD), Ranchi

} He is requested to take necessary
} action for their absorption
} with Chief Personnel Officer
} (PD) Ranchi as desired
} by D.G.M.

ANNEXURE V

No. 100/TRG/64.

Dated, the 31st August, 1965.

Shri Jamuna Prasad, a passed out trainee from I.T.I. has undergone one year training as opencast Fitter in heavy-earth moving machinery at Mining Training School, Bhurkunda. After that he has been working as Fitter (Trainee) in category VII of the L.A.T. Award since 17th August, 1964. As there is no immediate prospect to absorb him in a permanent post, in any project, he is being given 'no objection certificate' to apply outside for any job and if he is selected for outside employment he will be released from the Corporation service and from the terms of the bond executed by him and his surety.

(Sd.) J. M. DHAWAN,
Jt. Chief Mining Engineer (Trg)

ANNEXURE VI

NATIONAL COAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
DARBHANGA HOUSE: RANCHI

No. 100/TRG/64/4638-64.

Dated, the 1st September, 1965.

OFFICE ORDER

The following Course I, Batch-7, M.T.S. passed out trainees who were posted for further training in Bhurkunda Colliery as Opencast trainee Fitter *vide* this office letter of even no. dated 22nd September, 1964 are hereby released from training as there are no vacancies to absorb them as opencast Fitters in any project. They are also released from the terms of the bond executed by them and their surety. Their cases will be considered for posting in case any vacancies arise in future in the projects and they will be duly informed in case they are interested in taking appointment.

1. Shri Majeibur Rahman Ansari.
2. Shri Ayodhya Thakur.
3. Shri Birendra Prasad Singh.
4. Shri Ram Chandra Thakur.
5. Shri Jamuna Prasad.

(Sd.) J. M. DHAWAN,
Jt. Chief Mining Engineer (Trg.)

Distribution:

1. Dy. S.O.C. Bhurkunda.
2. Person concerned (registered A/D).
3. Principal, MMTI, Bhurkunda.

ANNEXURE VII

To
The Chief Engineer (E&M)
N.C.D.C. Ltd., Ranchi.
Sir,

We, the following Ex-trainees of Fitter (Opencast)'s course of Mining Training School, NCDC beg to state that we have been released from training *vide* Jt. CME (Trg)'s letter No. 100/Trg/64/4662 dated the 1st September, 1965 as at that time there were no vacancies to absorb us. In the above mentioned letter we were also informed by Jt. CME (Trg) that in future if there are vacancies in the projects, we will be offered appointment. In this connection we beg to inform you that recently, it is understood some Fitters, Mechanists etc., are required for Korba Central Workshop. We shall therefore be highly obliged if you will kindly consider our case and offer us the post of fitters in the Korba Central Workshop as we are already trained hand and have been released by the NCDC as there were no vacancies for absorption at that time after passing out from Mining Training School. We would also like to inform you that we have worked for one year in Bhurkunda Colliery as Fitters satisfactorily after completion of Training. We shall accept the salary according to the Central Workshop scale. Our appointment letter should be sent at our home address which are available in the Training Section.

Encl: 1.

Yours faithfully,

(Sd.) RAM CHANDRA THAKUR,
AYODHYA THAKUR,
BIRENDRA PRASAD SINGH,
JAMUNA PRASAD,
MOJEEBUR RAHMAN ANSARI.

RANCHI,
Dated the 15th October, 1965.

ANNEXURE VIII

To

The Chief Engineer (M),
NCDC Limited, Darbhanga House,
Ranchi.

(Through Executive Engineer, Bhk.)

Dear Sir,

Having come to understand that there are some vacancies for the post of Fitter & Mechanic at N.C.D.C. Central Workshop, Korba. We, the undermentioned persons are beg to state the following for your kind perusal.

We undergone the training for one year (1963-64) at M.T.S. Bhurkunda (As per course conducted by the NCDC) and subsequently, we have got appointment at Bhurkunda Workshop. Unfortunately, we have been retrenched by the Corporation in the month of August, 1965, thus the problem of unemployment is arising.

As we have got preference due to our prior experience in this Corporation, we request you Sir, to kindly consider our case favourably.

Thanking you,

Dated the 25 October, 1965.

Yours faithfully,

(Sd.) AYODHYA THAKUR,
RAMCHANDRA THAKUR,
JAMUNA PRASAD.
C/o Executive Engineer
(M) P.O. Bhurkunda,
Distt. Hazaribagh.

ANNEXURE IX

NATIONAL COAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
DARBHANGA HOUSE: RANCHI

Dated, the 10th January, 1966.

No. 100/TRG/64.

OFFICE ORDER

The following persons are posted to the Central Workshop, Korba with immediate effect. They should report to the Supdt. Central Workshop, Korba.

1. Sri Ajodhya Thakur.
2. Sri Birendra Prasad Singh.
3. Sri Ram Chandra Thakur.
4. Sri Jamuna Prasad.
5. Sri Majeebur Rahman Ansari.

They will be employed under Category IX of L.A.T. Award and they will be guided by the conditions of the services and other benefits as admissible under L.A.T. Award.

(Sd.) B. R. PAI,
Chief Mining Engineer (Hqrs.)

[No. 5/9/70-LR.II.]

New Delhi, the 14th July 1971

S.O. 2800.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of East Buggatdih Colliery of Messrs East Buggatdih Colliery Company Private Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th July, 1971.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2)
JHARIA, AT DHANBAD**

PRESENT:

Shri Nandagiri Venkata Rao, Presiding Officer.

REFERENCE NO. 36 OF 1970

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

PARTIES:

Employers in relation to the East Buggatdih Colliery of Messrs. East Buggatdih Colliery Company Private Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad.

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the employers.—Shri B. P. Dabrol, Chief Personnel Officer.

On behalf of the workmen.—Shri S. P. Singh, Secretary, Khan Mazdoor Congress.

STATE: Bihar.

INDUSTRY: Coal.

Dhanbad, 2nd July, 1971/11th Asadha, 1893 (Saka)

AWARD

The Central Government, being of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the East Buggatdih colliery of Messrs East Buggatdih colliery Company Private Limited, Post office Jharia, District Dhanbad and their workmen, by its order No. 2/149/70-LR.II dated 9th December, 1970 referred to this Tribunal under Section 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication the dispute in respect of the matters specified in the schedule annexed thereto. The schedule is extracted below:—

SCHEDULE

“Whether the action of the management of East Buggatdih colliery of Messrs East Buggatdih Colliery Company Private Limited, Post office Jharia, District Dhanbad, in dismissing Sri Hari Kamal Mitra, Mining Sirdar, with effect from 18th May, 1970 was justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. Employers as well as the workmen filed their statement of demands.

3. From the statement of demands filed by the employers itself the undisputed facts giving rise to the industrial dispute emerge. They may be stated in brief. The affected workman, Hari Kamal Mitra is a mining sirdar in East Buggatdih colliery of the employers since 1965. His father, Bhola Nath Mitra was an overman in the same colliery and his services have come to an end sometime in 1969. While he was in service, Bhola Nath Mitra was allotted a quarter in the colliery premises which he has not vacated on termination of his service and continues to live in it. The affected workman also was residing in the quarter along with his father. The affected workman was allotted a quarter in Kamini Kalayan Area and was directed to occupy the quarter allotted to him and vacated the previous quarter in which he was living with his father. In this connection there were some letters exchanged between the affected workman and the management. On 5.2.1970 a letter was issued to the affected workman by the manager directing him to move himself to the quarter allotted to him and vacate the one where he was staying and

also stating that in default he would make himself liable for disciplinary action. On 2.3.1970 the manager issued a memo to the affected workman stating that as he had not vacated the quarter and shifted to the new one in compliance with the direction contained in the letter dated 5.2.1970, the affected workman was to show cause as to why disciplinary action should not be taken against him for insubordination. To this charge-sheet the affected workman submitted his reply denying the allegation. Thereafter also some correspondence continued between the affected workman and the manager. Ultimately the manager issued a notice stating that the Personnel Officer would be holding a domestic enquiry on 29.4.1970 in respect of the charge-sheet dated 2.3.1970, and that the affected workman should present himself before the enquiry. The Personnel Officer held the domestic enquiry into the charge-sheet on 29.4.1970 and submitted his report dated 7.5.1970 finding the affected workman guilty of the charges levelled against him. In pursuance of the report and after obtaining the approval of the Agent the manager issued a letter on 18.5.1970 to the affected workman informing him that he is dismissed from the company's service with immediate effect. Now, the case of the workmen is that the dismissal of the affected workman was illegal and unjustified and that it was only to pressurise the affected workman to get the quarter vacated by his father, Bholanath Mitra. The defence of the employers is that the affected workman was dismissed in accordance with the certified standing orders for the proved misconduct of persistent insubordination. The employers have also pleaded that the Reference is incompetent and bad in law. The workmen were represented by Shri S. P. Singh, Secretary Khan Mazdoor Congress and the employers by Shri B. P. Dabrol, Chief Personnel Officer. On admission by employers Exts. W.1 to W.21 for the workmen and on admission by the workmen, Exts. M.1 to M.20 for the employers were marked. The affected workman was examined as WW1 on behalf of the workmen and the employers examined the Personnel Officer as MW.1 and marked Exts. M.21 to M.23. As directed by the Tribunal the employers also produced certified standing orders.

4. I propose to deal with the legal objections taken by the employers. In para 1 of their statement of demands the employers have simply pleaded that, "the reference is incompetent and bad in law in that the dispute is not an industrial dispute and does not have the constituents that would convert an individual dispute into an industrial dispute." No further facts or reasons are mentioned to show why the dispute in the reference is not an industrial dispute. Obviously, the workmen had no opportunity to adduce evidence to meet the objection of the employers. The reference is as regards justification of dismissal from service of the affected workman, Hari Kamal Mitra. The dispute being in connection with the dismissal of the affected workman, it is covered by S.2-A of the Industrial Disputes Act, 1947. This section has to be read as an explanation to S.(k). A long line of decisions have established that an individual dispute cannot *per se* be an industrial dispute but may become one if it is taken up by a trade union or a substantial number of workmen. The provision under S.2-A does away with the requirement of espousal of an individual dispute for converting it into an industrial dispute in cases where a dispute or a difference arises out of discharge, dismissal, retrenchment, or otherwise termination of service of an individual workman. Under the section the dismissal itself shall be deemed to be an industrial dispute notwithstanding that no other workman nor any union of workmen is a party to the dispute. Shri B. P. Dabrol, the learned representative of the employers has argued that neither the union representing the affected workman nor the affected workman himself had raised the dispute as regards dismissal of the affected workman with the employers before they raised it with the Conciliation Officer and, as such the dispute could not be an industrial dispute and the Central Government was not competent to make the reference. It is true that the Supreme Court in *Sindhu resettlement Corporation, Ltd. v. Industrial Tribunal, Gujarat and others*, (1968-1-L.L.J. 584) and the decisions of the Delhi High Court in *F.L. Corporation (P) Ltd. v. Union of India* (1970-Lab. I.C. 421) support the legal proposition putforth by Shri B. P. Dabrol. But the question whether a particular dispute is an "industrial dispute" or not is a question of fact and requires to be decided on the material on record. Shri Dabrol has not scrutinised the record properly before contending that the affected workman had not raised the dispute with the management before it was raised with the Conciliation Officer. He is also not correct in stating that the union representing the affected workman had also not done so. The failure report accompanying the order of reference shows that the Branch Secretary, Khan Mazdoor Congress, Jharia served 4 points charter of demands on the employers *vide* his letter dated 29th May, 1970 before it was received in the office of the Assistant Labour Commissioner (C) Dhanbad on 2nd June, 1970 and that the demand No. 1 of the charter related to reinstatement of the affected workman. It is then argued by Shri Dabrol that on the date of submission of the charter of demands, i.e. 29th May, 1970 the affected workman was not a member of the union. Even if it is so, the dispute in the reference having been covered by S.2-A, it was sufficient

if the affected workman himself had raised the dispute with the employers. The affected workman was dismissed from service under the letter of the manager, dated 18th May, 1970, Ext. W.5. Ext. W.4 is a letter from the affected workman, dated 21st May, 1970 to the manager with reference to the letter of dismissal, Ext. W.5, describing the action taken against him as nothing but black mail and also requesting reconsideration of the same. Ext. W.11 is a reply to the letter of the affected workman, Ext. W.4 from the manager stating that there could be no reconsideration of his case. It is manifest that the affected workman had demanded reconsideration of his dismissal order and the same was refused by the management and this was done before the dispute was raised by the union before the Assistant Labour Commissioner (C) Dhanbad. It is to be noted that Exts. W.4 and W.11 are marked for the workmen on admission by the employers. I also find no substance in the argument of Shri Dabrol that the union, Khan Mazdoor Congress could not represent the affected workman in the present reference, as it has not proved that the affected workman was its member at the relevant time. The failure report shows that the affected workman, along with others had become member of the union before 1st July, 1970, long before the date of order of Reference. Shri S. P. Singh, Secretary, Khan Mazdoor Congress has represented the affected workman also on the personal authority given to him by the affected workman under Sec. 36 of the Industrial Disputes Act, 1947. This authority is never challenged. Hence, the legal objections raised by the employers are over ruled.

5. For dismissing the affected workman the justification pleaded by the employers is that he was guilty of the misconduct of persistent insubordination in terms of the certified standing orders and that he was dismissed after a proper domestic enquiry. The charge-sheet issued to the affected workman is Ext. M2 and it is dated 2nd March, 1970. It states that as per the direction in the letter, dated 5th February, 1970 he had to vacate the quarter and shift to the new one and, as he did not obey the directions he was to show cause as to why disciplinary action should not be taken against him for insubordination. To understand the direction the letter, dated 5th February, 1970, Ext. M1 requires to be read with the charge-sheet, Ext. M2. Ext. M1 says that the affected workman was residing along with his father in a quarter allotted to him (father), that no quarter had so far been allotted to the affected workman, that the affected workman was thereby directed to move himself to the quarter allotted to him and vacate the one where he was staying. Thus, the direction mentioned in Ext. M1 and for disobedience of which he is charged for as insubordination in Ext. M2, is two fold, viz. (1) to move himself to the quarter allotted to him and, (2) vacate the quarter which was allotted to his father and in which he was living with his father till then. Though it was stated in Ext. M1 that no quarter was allotted to the affected workman, it is an admitted fact that the affected workman was allotted a quarter at Kamini Kalayan Area on 29th January, 1970 and he has moved in to it in April, 1970, before the domestic enquiry was held. On behalf of the employers only one witness is examined and he was the Personnel Officer of the colliery who held the domestic enquiry into the charge-sheet, Ext. M2. The report submitted by him is Ext. M22 whereby he found the affected workman guilty of the charge. The enquiry Officer, MW.1 after discussing the evidence, says at page 4 that there was doubt about the quarter being in the name of his father, that it was allotted to his father while he was in the company's service and that when his father was discharged he was asked to hand over the vacant possession of the quarter and collect his dues. It is also stated in the same page that the affected workman had moved to the quarter allotted to him but it did not appear that he had handed over the vacant possession of the quarter which has been under his occupation (the quarter which was allotted to his father and is still in his occupation). It, therefore, follows that the enquiry officer found the affected workman guilty because he had failed to hand over vacant possession of the quarter which was allotted to his father and which is still in possession of his father. The question is whether the direction given to the affected workman to vacate and hand over vacant possession of the quarter which is in possession and in the name of his father, was lawful or reasonable? In the certified standing orders misconduct is punishable under clause 29 and wilful insubordination is referred to in sub-clause 1 thereof. As per the sub-clause the wilful insubordination should be of any lawful or reasonable order of a superior. The affected workman was appointed as mining sirdar in 1965 and his father, Bhola Nath Mitra was discharged from service as a senior overman on 14th April, 1969. The management was in correspondence with Bhola Nath Mitra asking him to vacate the quarter and Bhola Nath Mitra was putting it off or refusing to vacate the quarter on some ground or other, justified or otherwise as is seen from the evidence of the witnesses examined during the enquiry. Even if it is conceded that in one of his letters the affected workman had stated

that he was in occupation of the quarter allotted to his father, it does not appear to me justifiable to demand of the affected workman that he should hand over vacant possession of the quarter when his father was occupying and residing in it, asserting his own right. From the beginning the affected workman was pleading that he was being pressurised to get the quarter vacated by his father and in the same process he was dismissed. This allegation is probabished by the dismissal order, Ext. W.5, which says that the order would be reconsidered should the affected workman handover within 10 days the vacant possession of the quarter which was originally allotted to his father, Bhola Nath Mitra. Out of the two directions mentioned in Ext. M1 read with Ext. M2 the affected workman has complied with the first and the order relating to the second direction was neither lawful nor reasonable. The charge brought against the affected workman itself was neither lawful nor reasonable. Even before this Tribunal nothing new is proved which the enquiry proceedings, Ext. M21 and enquiry report, Ext. M22 did not reveal. Hence, I do not find any justification for dismissal of the affected workman.

6. I, therefore, find that the action of the management of East Bhuggatdih colliery of Messrs East Bhuggatdih colliery company Private Limited, Post Office Jharia, District Dhanbad in dismissing the affected workman, Hari Komal Mitra, mining sirdar with effect from the 18th May, 1970 was not justified, consequently, he is entitled to his wages, emoluments and other dues as though he is continuing in service without any break from 18th May, 1970. The Award is made accordingly and submitted under Sec. 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Sd.) N. VENKATA RAO,

Presiding Officer,

Central Govt. Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad.

[No. 2/149/70-LR.II.]

ORDERS

New Delhi, the 29th May 1971

S.O. 2801.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Methani Colliery (Bejdih Unit) of Messrs Equitable Coal Company Limited, Post Office Sitarampur, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Methani Colliery (Bejdih Unit) of Messrs Equitable Coal Company Limited, Post Office Sitarampur, District Burdwan in retiring Shri Jagan Pandey, Guard with effect from the 1st August, 1970 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. L-1912/41/71-LR.II.]

अस और रोजगार विभाग

आदेश

नई दिल्ली, 29 मई 1971

का० आ० 2801—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स इक्वीटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर सीतारामपुर, जिला बर्द्धमान की सेवानो कोलियरी (बेजडीह यूनिट) के प्रबन्धनत्व से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 के उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कचकला को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स इक्वीटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर सीतारामपुर, जिला बर्धमान की मैदानी कोलियरी (बेजडीह युनिट) के प्रबन्धतन्त्र की श्री जगन प्रसाद, गार्ड की पहली श्रमस्त, 1970 से सेवानिवृत्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुसूचिप्राप्त अधिकार है ? "

[सं० एल०-1912/41/71-एल० प्रा० 2]

New Delhi, the 3rd June 1971

S.O. 2802.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Lodna Colliery of Messrs. Lodna Colliery Company (1920) Limited, Post Office Jharla, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed.

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Lodna Colliery of Messrs. Lodna Colliery Company (1920) Limited, Post Office Jharla, District Dhanbad, in dismissing Shri Moti Lall Prasad, Clerk, with effect from the 18th January, 1971, is justified? If not to what relief is the workman entitled?"

[No. L/2012/55/71-LRII.]

नई दिल्ली, 3 जून 1971

का० प्रा० 2802—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स लोदना कोलियरी कम्पनी (1920) लिमिटेड, डाकघर झरिया, जिला धनबाद की लोदना कोलियरी के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

“क्या मेसर्स लोदना कोलियरी कम्पनी (1920) लिमिटेड, डाकघर झरिया, जिला धनबाद की लोदना कोलियरी के प्रबन्धतंत्र की श्री मोती लाल प्रसाद, क्लर्क को 18 जनवरी, 1971 से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुसूच का हकदार है?”

[सं. एल०/2012/55/71-एल० आर०-2]

S.O. 2803.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bansdeopur Colliery of Messrs. N. B. Colliery Company Private Limited, Post Office Kusunda (Dhanbad), and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

“Whether Shri Baban Singh was working continuously in Bansdeopur Colliery of Messrs. N. B. Colliery Company Private Limited, Post Office Kusunda (Dhanbad), in the capacity of Prop. Mazdoor from the year 1965 and in the capacity of Night Guard with effect from the 1st August, 1967? If so, whether the action of the management of the aforesaid colliery in refusing him employment with effect from the 19th November, 1970, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

[No. L. 2012/61/71-LRII.]

का० आ० 2803.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों के बारे में मेसर्स एन० बी कोलियरी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, डाकघर कुसूदा (धनबाद) की बंसदेवपुर कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से संबंधित नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है:

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री बाबन सिंह मेसर्स एन० बी० कोलियरी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, डाकघर कुसूदा, (धनबाद) की बंसदेवपुर कोलियरी में वर्ष 1965 से प्राप्त मजदूर की हैसियत से और पहली अगस्त,

1967से रात्रि शिफ्ट की हैसियत से लगातार काम कर रहा था यदि हा, तो क्या पूर्वोक्त कोलियरी के प्रबन्ध पत्र की उसे 19 नवम्बर, 1970 से रोजगार मना करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनतोष का हकदार है?

[स० एल० 2012/61/71-एल० आर० 2]

S.O. 2804.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Digwadih Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Digwadih Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad in dismissing Shri Ram Prabesh Ojha, Banksman from service with effect from the 17th November, 1970 is justified? If not, to what relief is he entitled?”

[No. L-2012/77/71-LRII.]

का० आ० 2804.—यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, डाकघर जीलगोरा, जिला धनबाद की डिग्वाडिह कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उन के कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वाछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“क्या मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, डाकघर जीलगोरा, जिला धनबाद की डिग्वाडिह कोलियरी के प्रबन्धतंत्र की श्री राम प्रवेश ओझा, बैंक्समैन को 17 नवम्बर, 1970 से सेवा से पदच्युत करने को कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किस अनतोष का हकदार है ?”

[स० एल० -20127

र०-2]

S.O. 2805.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of East Bastacolla Colliery of Messrs. East Bastacolla Colliery Company, Post Office Jharia, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government¹ considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of East Bastacolla Colliery of Messrs. East Bastacolla Colliery Company, Post Office Jharia, District Dhanbad, in dismissing Sri Chandreshwar Rewani, Prop Mazdoor, from service with effect from the 6th November, 1970, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

[No. L-2012/54/71-LRII.]

का० आ० 2805—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयो के बारे में मैसर्स ईस्ट बस्ताकोल्ला कोलियरी कम्पनी, डाकघर झरिया, जिला धनबाद की ईस्ट बस्ताकोल्ला कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजको और उन के कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उस विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 1) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स ईस्ट बस्ताकोल्ला कोलियरी कम्पनी, डाकघर झरिया, जिला धनबाद की ईस्ट बस्ताकोल्ला कोलियरी के प्रबन्धतंत्र की श्री चन्द्रशंकर, रेवानी, प्रोप मजदूर को 6 नवम्बर, 1970 को सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ।

[सं० एल-2012/54/71—एल०आर०-2]

New Delhi, 5th June 1971

S.O. 2806.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of East Chora Colliery, Post Office Bahula, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the

Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the management of East Chora Colliery, Post Office Bahula, District Burdwan are justified in stopping the work of Sarvashri Darshan Singh and Jaila Singh, Coal Cutting Machine Drivers with effect from the 16th August, 1969, and if not, to what relief the workmen are entitled?"

[No. L-1912/7/71-LR.II.]

नई दिल्ली, 5 जून, 1971

क्र० प्र० 2803.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ईस्ट चोरा कोलियरी, डाकघर बाहुला, जिला बर्दवान के प्रबन्ध मण्डल से सम्बद्ध निरोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या ईस्ट चोरा कोलियरी, डाकघर बाहुल, जिला बर्दवान के प्रबन्ध मंडल का सर्वश्री दर्शन सिंह और जैला सिंह, कोल कटिंग मशीन ड्राइवर्स को 16 अगस्त, 1969 से काम से बंद करना न्यायोचित है और यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनतोष के हकदार हैं?"

[सं० एल०-1912/7/71—एल० प्रार०-2]

S.O. 2807.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Desmet India Private Limited, Ahmedabad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri I. G. Thakore, as Presiding Officer with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

"I. Whether the management of Messrs Desmet (India) Private Limited, Khanna Construction House, 44, Maulana Abdul Gaffar Road, Bombay, engaged at Navagam Central Tank Farm is justified in denying the following workmen work by closing down their site at Navagam Central Tank Farm—Oil fields of Oil and Natural Gas Commission, Navagam? If not, to what relief are these workmen entitled?"

II. Sr. No.	Name of the worker	Designation
1.	Shri P.R. Roy	Welder
2.	„ J. Fernandis	Do.
3.	„ Epan	Do.
4.	„ Gopi Ray	Do.
5.	„ Kumar	Do.

Sl. No.	Name of the worker	Designation
6	Shri Vidhyadharan	Welder
7.	" Shivdasan	Do
8.	" Rajendra Roy	Do.
9.	" Bhawar Singh	Fitter
10.	" Amarjeet	Do.
11.	" Philips	Do
12.	" Mathues	Do.
13.	" Sukhdev Singh	Do.
14.	" Vasant Rao	Jacker
15.	" Rangha Rao	Do.
16.	" Rathod	Do.
17.	" Shreemall	G Cutter
18.	" Gurnam Singh	Do.
19.	" Davender	B. Smlth
20.	" M.L. Patel	W. Man
21.	" Ishurcharan	Grinder
22.	" Manasha	Do.
23.	" Budha Bhal	Do.
24.	" Serial	Do.
25.	" Mohan	Rigger
26.	" Satidln	Do.
27.	" Lakha	Labour
28.	" Victor	Do.
29.	" Sita Ram	Helper
30.	" Baldev Kumar Patel	Store Keeper
31.	" Saka Ram	Do.
32.	" Josaf M.	Water Boy.
33.	" Amosh	Painter
34.	" Prjaya	Do.
35.	" Imanul H	Labourer
36.	" Imanul P	Do.
37.	" Gopal	Do
38.	" Rusal Mia	Washer
39.	" Ganpat	Labour
40.	" Thiophill	Washer
41.	" Rajan	Welder
42.	" Roopa	Helper
43.	" Chimon Bhai	Do.
44.	" Moti Parmar	Do.
45.	" Parmar Kala	Do.
46.	" Daya Bhal	Do.
47.	" Jeevan	Do.
48.	" Kesraj	Do.
49.	" Asha D.	Do.
50.	" Daniaal	Do.
51.	" Imanial D.	Do.
52.	" Damodar	Do.
53.	" Salmon	Do
54.	" Arvind	Do.
55.	" Karsan	Do.
56.	" Moses	Do.
57.	" Jayanti Patel	Do.
58.	" Rawaji Bhai	Do.
59.	" Jayanti S.	Do.
60.	" Vishwas	Do.
61.	" Sapatar Miya	Do.
62.	" Hareish Wardha	Do.
63.	" M.A. Parmar	Mukadam
64.	" Dhurakala	Helper
65.	" Walji	Do.
66.	" Allji Bhai	Do.
67.	" Tagga Bhal	Do.
68.	" Sha ikra	Do.
69.	" Tagi Bhen	Do.
70.	" Vijyan	Furicator
71.	" Gopi N Nayar	Welder

Sr. No.	Name of the worker	Designation
72-	Shri Shree Dharan	Grinder
73-	" Shivdarani	Crascutter
74-	" Dharam Palan	Asstt. Pipe Fitter
75-	" Surandran	Helper
76-	" Soman	Do.
77-	" Shivan Kutty	Do.
78-	" Kanti Bhai	Do.
79-	" Surendran	Do.
80-	" Chanudev	Do.
81-	" Emomel	Do.
82-	" Vijyan	Do.
83-	" Amraram	Labour
84-	" Lakema	Do.
85-	" K.D. Ayer	Storekeeper
86-	" Seshadan Matu	Do.

II. Whether the management of Messrs. Dramet (India) Private Limited, Bombay, engaged on Central Tank Kalol-oil field it justified in denying the following workers the employment by way of closing the site with effect from the 31st March, 1971. If not, to what relief are these workmen entitled?

Sr. No.	Name of the worker	Designation
1.	Shri Jagdish Singh	Welder
2.	" Patel C.M.	Do.
3.	" Sarvan Singh	Gas Cutter
4.	" Kanti Bhai	Do.
5.	" Patel A.	Taker
6.	" Ram Thankar	Fitter
7.	" Swaprasad	Do.
8.	" Thakur Swami	Painter
9.	" K.J. Patel	Do.
10.	" Dara Singh	Rigger
11.	" M.I. Khan	Do.
12.	" Guru Charan Singh	Do.
13.	" Bhika Bhai	Do.
14.	" Hamraji	Do.
15.	" Pratap Singh	Do.
16.	" Patel C.B.	Do.
17.	" Raju	Grinder
18.	" Munna Singh	Helper
19.	" Bechoe Chancha	Do.
20.	" Patel R.A.	Do.
21.	" Umaji	Do.
22.	" Kalia	Do.
23.	" Ramaji	Labour
24.	" Pannaji	Do.
25.	" Puraji	Do.
26.	" Metha	Do.
27.	" Dharmaji	Do.
28.	" Gamaji	Do.
29.	" Krushna Ram	Do.
30.	" Boparam	Do.
31.	" Sangra Bhai	Do.
32.	" Sunder Bhai	Do.
33.	" Ugam Bhai	Do.
34.	" Tara Sena	Do.
35.	" Heera Bhai	Do.
36.	" Ram Lal	Electrician.
37.	" Prem Chander R	Clerk
38.	" R.B. Singh	Store Keeper
39.	" Raghunath	Labour
40.	" Dhoraji Rajiji	Winchman
41.	" Garib Das	Fitter
42.	" Gulab Das	Do.
43.	" Kali Din	Rigger
44.	" Dilip Singh	Gas Cutter

S. No.	Name of the worker	Designation
45.	Shri Mohinder Singh	Welder
46.	„ Rameshwar	Rigger
47.	„ Jagroop	Do.
48.	„ Ram Narayan	Grinder
49.	„ R.B. Patel	Helper
50.	„ Mohan Patel	Tacker
51.	„ R.N. Mehta	Welder
52.	„ Mohinder Singh Seni	Do.
53.	„ Satpal	Helper
54.	„ Jarnail Singh Seni	Welder
55.	„ Tehsildar	Rigger
56.	„ Bala ji	Helper
57.	„ M.M. Patel	Store Keeper
58.	„ Sonia	Water Lady
59.	„ Pyara Singh	Electrician
60.	„ Nandev	Helper
61.	„ Tham Singh	Rigger
62.	„ Jawahar	Do.
63.	„ Ramachal	Do.
64.	„ Seva Ram	Do.
65.	„ Keshav ji	Helper
66.	„ Salvaraj	Do.
67.	„ Mehraj	Do.
68.	„ Ram Sea	Rigger

[No. L. 30011.4/71-DR IV.]

का० आ० 2807.—यत् केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स वेस्मे : इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद के प्रबंधमण्डल से सम्बन्धित विवादों और उनके कर्मकारी के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और आ० केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री साई० श्री० ठाकुर होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“1. क्या मैसर्स वेस्मे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, खन्ना कंस्ट्रक्शन हाउस, 44, मोलाना अब्दुल गफ्फार रोड, बम्बई के प्रबंधमण्डल का, जो नवगांम सेंट्रल टैंक फार्म में काम कर रहे थे, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, नवगांम के नवगांम सेंट्रल टैंक फार्म-लेते-क्षेत्रों में अपने कार्य-स्थल को बंद करके निम्नलिखित कर्मकारों को काम से बर्चित करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

कर्म संख्या

कर्मकार का नाम

पदनाम

1.	श्री पी० आर० राय	वैल्डर
2.	श्री जे० फरनडीज	वैल्डर
3.	श्री एपन	वैल्डर
4.	श्री गोपीराय	वैल्डर
5.	श्री कुमार	वैल्डर
6.	श्री विद्याधरन	वैल्डर
7.	श्री सिववासन	वैल्डर
8.	श्री राजेन्द्र राय	वैल्डर
9.	श्री भंवर सिंह	फिटर
10.	श्री भमरजीत	फिटर
11.	श्री फिलिप्स	फिटर
12.	श्री मैथ्यूस	फिटर
13.	श्री सुखदेव सिंह	फिटर
14.	श्री वसंत राव	टेकर
15.	श्री रंभा राव	यथोपरि
16.	श्री राठीर	यथोपरि
17.	श्री माली	जी० कटर
18.	श्री गुमान सिंह	यथोपरि
19.	श्री देवेन्द्र	बी० स्मिथ
20.	श्री एम० एल० पटेल	इन्स्पेक्टर-मैन
21.	श्री ईश्वर चरन	ग्राइंडर
21.	श्री मनाशा	ग्राइंडर
23.	श्री बुद्धा माई	ग्राइंडर
24.	श्री सीरियल	ग्राइंडर
25.	श्री मोहन	रिग्गर
26.	श्री सतिशिन	रिग्गर
27.	श्री लाखा	मजदूर
28.	श्री विकटर	मजदूर
29.	श्री सीताराम	सहायक
30.	श्री बलदेवकुमार पटेल	भंडारी
31.	श्री साका राम	भंडारी
32.	श्री जोसफ एम०	वाटर बाय
33.	श्री भमोश	रंगसाज
34.	श्री प्रजया	रंगसाज
35.	श्री इमानुल एच०	मजदूर
36.	श्री इमानुल पी०	मजदूर
37.	श्री गोपाल	मजदूर

संख्या	कर्मकार	पदनाम
38.	श्री रूसल मियां	वाशर
39.	श्री गनपत	मजदूर
40.	श्री थियोफिल	वाशर
41.	श्री राजन	बैल्डर
42.	श्री रूपा	सहायक
43.	श्री क्षिमोन भाई	सहायक
44.	श्री मोती परमार	सहायक
45.	श्री परमार काला	सहायक
46.	श्री दया भाई	सहायक
47.	श्री जीवन	सहायक
48.	श्री केसराज	सहायक
49.	श्री आशा डी०	सहायक
50.	श्री इनिमाल लालू	सहायक
51.	श्री इमानियल डी	सहायक
52.	श्री दामोदर	सहायक
53.	श्री साइमन	सहायक
54.	श्री भरविद	सहायक
55.	श्री कर्सन	सहायक
56.	श्री मोसेस	सहायक
57.	श्री जयंती पटेल	सहायक
58.	श्री राजजी भाई	सहायक
59.	श्री जयंती एस०	सहायक
60.	श्री विश्वास	सहायक
61.	श्री सपातार मियां	सहायक
62.	श्री हरेण यार्धा	सहायक
63.	श्री एम० ए० परमार	मुकदम
64.	श्री धुराकाला	सहायक
65.	श्री बाल्जी	सहायक
66.	श्री अलल जी भाई	सहायक
67.	श्री तग्गा भाई	सहायक
68.	श्री शंकरा	सहायक
69.	श्री तगी भैन	सहायक
70.	श्री विडयन	फुरिकेटर
71.	श्री गोपी एन० नायर	बैल्डर
72.	श्रीधरन	ग्राइंडर
73.	श्री शिवदानी	कासकटर
74.	श्री धर्म पालन	सहायक पाइप फिटर
75.	श्री सुरन्द्रन	सहायक

क्रम संख्या	कर्मकार का नाम	पदनाम
76.	श्री सोमन	सहायक
77.	श्री शिवन कुट्टी	सहायक
78.	श्री कान्ति भाई	सहायक
79.	श्री सुरेन्द्रन	सहायक
80.	श्री चनुदेव	सहायक
81.	श्री एमोमेल	सहायक
82.	श्री विजयान	सहायक
83.	श्री भद्रा राम	भंडार
84.	श्री लकेमा	भंडार
85.	श्री के 0 डी 0 आयर	भंडारी
86.	श्री सेनादन भाट्ट	भंडारी

2. क्या मैसर्स. देसमेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, के प्रबंधमंडल का, जो सेंट्रल टैंक क्लोल-तेल क्षेत्र में काम कर रहे थे, निम्नलिखित कर्मकारों को 5 मार्च, 1971 से कार्य-स्थल को बंद करके नियोजक से वंचित करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

क्रम संख्या	कर्मकार का नाम	पदनाम
1.	श्री जावीश सिंह	बैल्डर
2.	श्री पटेल सी 0 एम 0	बैल्डर
3.	श्री सर्वन सिंह	गैस कटर
4.	श्री कान्ति भाई	गैस कटर
5.	श्री पटेल ए 0	टेकर
6.	श्री राम थंकर	फिटर
7.	श्री स्वाप्रसाद	फिटर
8.	श्री ठाकुर स्वामी	रंगसाज
9.	श्री के 0 जे 0 पटेल	रंगसाज
10.	श्री दारा सिंह	रिगगर
11.	श्री के 0 आर् 0 खान	रिगगर
12.	श्री जैकचरन सिंह	रिगगर
13.	श्री लीका भाई	रिगगर
14.	श्री हीमरानी	रिगगर
15.	श्री प्रताप सिंह	रिगगर
16.	श्री पटेल सी 0 बी 0	रिगगर
17.	श्री राजू	ग्राइंडर
18.	श्री मुन्ना सिंह	सहायक
19.	श्री बेचो चंभा	सहायक

क्रम संख्या	कर्मकार का नाम	पदनाम
20.	श्री पटेल आर० ए०	सहायक
21.	श्री उमाजी	सहायक
22.	श्री कालिया	नहायक
23.	श्री रामाजी	मजदूर
24.	श्री पन्नाजी	मजदूर
25.	श्री पुराजी	मजदूर
26.	श्री मेघा	मजदूर
27.	श्री धर्माजी	मजदूर
28.	श्री गामाजी	मजदूर
29.	श्री कृष्णा राम	मजदूर
30.	श्री बोषाराम	मजदूर
31.	श्री साप्पा भाई	मजदूर
32.	श्री सुंदर भाई	मजदूर
33.	श्री उगम भाई	मजदूर
34.	श्री तारा सेना	मजदूर
35.	श्री होरा भाई	मजदूर
36.	श्री राम लाल	बिजली-मिस्त्री
37.	श्री प्रेम चंदर आर	मजदूर
38.	श्री आर० बी० सिंह	भंडारी
39.	श्री रघुनाथ	मजदूर
40.	श्री घोराजी राजीजी	विद्यमान
41.	श्री गरीब दास	फिटर
42.	गुलाब दास	फिटर
43.	श्री कालीवीन	जिग्गर
44.	श्री दिलीप सिंह	गैस कटर
45.	श्री मोहिन्दर सिंह	वैल्डर
46.	श्री रामेश्वर	रिग्गर
47.	श्री जगरूप	रिग्गर
48.	श्री राम नारायण	ग्राइंडर
49.	श्री आर० बी० पटेल	सहायक
50.	श्री मोहन पटेल	टैकर
51.	श्री आर० एन० मेहा	वैल्डर
52.	श्री मोहिन्द्र सिंह सेनी	वैल्डर
53.	श्री सप्तपाल	सहायक
54.	श्री जरनैल सिंह सेनी	वैल्डर
55.	श्री तहसीलदार	गिग्गर
56.	श्री बाला जी	सहायक
57.	श्री बी० एम० पटेल	भंडारी

क्रम संख्या	कर्मकार का नाम	पदनाम
58.	श्री सोनिया	वाटर लेडो
59.	श्री प्यारा सिंह	बिजली-मिस्त्री
60.	श्री नन्देव	सहायक
61.	श्री थाम सिंह	रिग्गर
62.	श्री जवाहर	रिग्गर
63.	श्री रामाचल	रिग्गर
64.	श्री सेवा राम	रिग्गर
65.	श्री केशव जी	सहायक
66.	श्री साठ्ठाराज	सहायक
67.	श्री मेहराज	सहायक
68.	श्री राम सिया	रिग्गर

[संख्या एल०-30011/4/71-एल०आर० 4]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th June 1971

S.O. 2808.—In the Order of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1710, dated the 1st March, 1971 published on pages 2130-2131 of the Gazette of India, Part-II, Section 3 Sub-section (II), dated the 24th April, 1971, in page 2131 in line 4, for "29th October, 1970" read "29th September, 1970".

[No. 6/103/70-LR.II.]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 10 जून 1971

क्र० प्र० 2808—भारत के राजपत्र, तारीख 24 अप्रैल, 1971, भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (ii) के पृष्ठ 2131 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश संख्या का० प्र० 1710, तारीख पहली मार्च, 1971 की अनुसूची में तीसरी पंक्ति में "29 अक्टूबर, 1970" के स्थान पर "29 सितम्बर, 1970" पढ़िए।

[सं० 6/103/70-एल० आर० 2]

आर० कुंजीयापदम, अव्वर सचिव।

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 17th February 1971

S.O. 2809.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jalpuria Kajora Colliery, Post Office Andal, District Burdwan and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the management of Jaipuria Kajora Colliery of Messrs Swadeshi Mining and Manufacturing Company Limited Post Office Pandaceswar, District Burdwan was justified in stopping from work Shri Ram Ratan Bhattacharjee, Attendance Clerk with effect from 26th May, 1970? If not, to what relief the workman is entitled?"

[No. F. 6/45/70-LRIL.]

(अम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी 1971

का० आ० 280६—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में जयपुरिया कजोरा कोलियरी डाकघर आंखाल, जिला बर्धमान के प्रबन्ध-तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड डाकघर पांडवेश्वर जिला बर्धमान की जयपुरिया कजोरा कोलियरी के प्रबन्धतंत्र का श्री राम रतन भट्टाचार्य हाजिरी क्लर्क को 26 मई 1970 से काम से रोकना न्यायोचित था ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० 6/45/70-एल० आर०-2]

New Delhi, the 18th March 1971

S.O. 2810.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jealgora Colliery of Messrs East Indian Coal Company Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jealgora Colliery of Messrs East Indian Coal Company Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad, in dismissing Shri Gaffur, M. C. Loader, E.B. No. 43189, with effect from the 1st October, 1970 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

[No. 1/2012/22/71-LRII.]

KARNAIL SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 मार्च 1971

का० आ० 2810—यतः केन्द्रीय सरकार को राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स ईस्ट इंडियन कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर जीलगोरा, जिला धनबाद की जीलगोरा कोलियरी के प्रबन्धन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्राथमिक अधिकरण, (सं० 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है :

अनुसूची

"क्या मैसर्स ईस्ट इंडियन कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर जीलगोरा, जिला धनबाद की जीलगोरा कोलियरी के प्रबन्धन की ओर गफ्फूर, एम० सी० लोडर, ई० बी० नं० 43189, को पहली अवसर, 1970 से पदभ्युत्थन करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मचार किस अनुबोध का हकदार है ?"

[सं० एल०/2012/22/71-एल०आर-2]

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 7th April 1971

S.O. 2811.—Whereas, the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Singareni Collieries Company Limited, Post Office Kothagudem Collieries (Andhra Pradesh), and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri T. Chandrasekhara Reddy, as Presiding Officer with headquarters, at Afzal Lodge, Tilak Road, Ramkote, Hyderabad-I, and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Singareni Collieries Company Limited in refusing work to Shri Sayab Hussain and five others,

pump khalasis and Shri Eda Rajam and seven others, Haulage Khalasis, No. 2 Incline, Ramagundam Division and laying off all other workers of the second shift on the 20th July, 1970 is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?

[No. 7/24/70-LR.II.]

U. MAHABALARAO, Dy. Secy..

(अभ्य और रोज़ार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1971

का० प्रा० 2811.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड डाकघर कोथागुडम कोलियरीज (आन्ध्र प्रदेश) से सम्बद्ध नियोजकों और उन के कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7—क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० चन्द्रशेखर रेड्डी होंगे, जिनका मुख्यालय अप्पल लोज, तिलक रोड, रामकोटे, हैदराबाद होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध-मंडल की नं० 2 इन्क्लाइन रामागुडम डिवीजन के श्री सयाब दुसैन तथा पाँच अन्य पम्प खलासियों और श्री एडा राजम तथा सात अन्य दुलाई खलासियों को काम देने से इन्कार करने और दूसरी पारी के अन्य सभी कर्मकारों की, 20 जुलाई, 1970 को कामबन्दी की कार्यवाही न्यायनिरत है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० 7/24/70—एल० आर०—2]

यू० महाबला राव, उप-सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 3rd June 1971

S.O. 2812.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Sahukara Bank Limited, Miller Ganj, Ludhiana and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which

Shri P. P. R. Sawhney shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh, and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Sahukara Bank Limited, Miller Ganj, Ludhiana, in reverting Shri Bhagwan Dass from the post of Supervisor to the post of Clerk with effect from the 30th September, 1970, was justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

[No. L. 12012/33/71-LR.III.]

T. K. RAMACHANDRAN, Under Secy.

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून 1971

का० आ० 2812—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में साहुकार बैंक लिमिटेड मिलरगंज लुधियाना से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री पी० पी० आर० साहनी होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

“क्या साहुकार बैंक लिमिटेड मिलरगंज लुधियाना के प्रबन्धमण्डल की श्री भगवान दास को 30 सितम्बर 1970 से पर्यवेक्षक के पद से लिपिक के पद पर प्रतिवर्तित करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल० 12012/33/71 एल० आर० 3]

टी० के० रामचन्द्रन, धवर सचिव ।

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 17th July 1971

S.O. 2813.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the Management of the Food Corporation of India, Visakhapatnam and their workmen represented by the Port Khalasis Union;

And, whereas, the said employers and their workmen have, by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government, under sub-section (3) of Section 10A of the said Act, a copy of the said arbitration agreement;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of Section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement.

Agreement under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947

BETWEEN

Representing Employers.—Shri S. G. Tekwani, Senior Deputy Manager (PO), Food Corporation of India, Visakhapatnam-1.

Representing Workmen.—Shri P. M. Naidu, President, Port Khalasis Union (INTUC), Visakhapatnam-1.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri O. Venkatachalam, Chief Labour Commissioner (Central), Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-1.

(i) *Specific matters in dispute.*—"Whether the demand of the Port Khalasis Union to revise the existing piece-rate and to introduce a Progressive Incentive Scheme for Dock Clearance Workers of Food Corporation of India at Visakhapatnam Port as made applicable to the Shore Handling Labour of Visakhapatnam Port Trust from 1st October, 1970 is justified. If so, what should be the wage structure, number of members of the gang, etc. If not, what should be the new Piece-rate and Progressive Incentive Scheme for these workers having due regard to the nature of work performed by the said workers".

(ii) *Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.*—1. Food Corporation of India, Port Operations, Visakhapatnam-1.

2. The Port Khalasis Union (INTUC), Ramakrishna Street, Visakhapatnam-1.

(iii) *Name of Union, if any, representing the workmen in question.*—The Port Khalasis Union (INTUC), Ramakrishna Street, Visakhapatnam-1.

(iv) *Total number of workmen employed in the undertaking affected.*—680 approximately.

(v) *Estimated number of workmen affected or likely, to be affected by the dispute.*—680 approximately.

We further agree that the decision of the Arbitrator shall be binding on us.

The Arbitrator shall make his Award within a period of three months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the Award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Dated the 26th day of February, 1971.

Signature of the Parties

Representing Employers:
(Sd.) S. G. TEKWANI,
Senior Dy. Manager (PO),
Food Corporation of India,
Visakhapatnam-1.

Representing Workmen:
(Sd.) P. M. NAIDU,
President,
Port Khalasis Union (INTUC),
Visakhapatnam-1.

Witnesses:

1. Shri T. V. N. Reddi, Senior Assistant Manager (L).
2. Shri S. Nagireddi, Assistant Manager (M).

[No. 76/11/70-P & D.]

AJIT CHANDRA, Under Secy.

(अथ और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1971

का० प्र० 2813—यतः भारतीय खाद्य निगम, विशाखापट्टणम, के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों, जिनका प्रतिनिधित्व पोर्टे खलासीज यूनियन करती है, के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यतः उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-(क) की उपधारा (1) के अधीन लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति उक्त अधिनियम की धारा 10-(क) की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10-(क) की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त करार को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-(क) के अधीन करार—

निम्नलिखित के बीच

नियोजकों का प्रतिनिधित्व

करने वाले :

श्री एस० जी० टेकवानी,

ज्येष्ठ उप प्रबन्धक (पी प्रो),

भारतीय खाद्य निगम,

विशाखापट्टणम-1

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

श्री पी० एम० नायडू,

अध्यक्ष, पोर्टे खलासीज यूनियन

(इंटक)

विशाखापट्टणम-1

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को श्री ओ० वेंकटाचलम, मुख्य श्रम प्रायुक्त, (केन्द्रीय) श्रम शक्ति भवन, रफो मार्ग, नई दिल्ली-1, के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का एतद्द्वारा करार किया गया है।

(i) विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय :—

“क्या पोर्टे खलासीज यूनियन की, विशाखापट्टणम पत्तन के भारतीय खाद्य निगम के डाक निकासी कर्मकारों के लिए विद्यमान मातृानुपाती दर को पुनरीक्षित करने की और क्रमवर्द्धी प्रोत्साहन स्कीम को, जैसा कि 1-10-70 से विशाखापट्टणम पत्तन न्यास के शोअर हेन्डलिंग श्रमिक को लागू किया गया है, पुरा स्थापित करने की मांग न्यायोचित है? यदि है, तो मजदूरी का ढाँचा टोली के सदस्यों की संख्या आदि कैसी होनी चाहिए। यदि नहीं तो उक्त कर्मकारों द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मकारों के लिए नयी मातृानुपाती दर और क्रमवर्द्धी प्रोत्साहन स्कीम कैसी होनी चाहिये”।

(ii) विवाद के पक्षकारों का, अंतरित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है, विवरण।

1. भारतीय खाद्य निगम, पत्तन, संक्रियाएं, विशाखापट्टणम-1

2. दि पोर्टे खलासीज यूनियन (इंटक), रामकृष्ण स्ट्रीट, विशाखापट्टणम-1

(iii) यदि कोई संघ, प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो, तो उसका नाम :

दि पोर्टे खलासीज यूनियन (इंटक), रामकृष्ण स्ट्रीट, विशाखापट्टणम-1

(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों का कुल संख्या — लगभग 680.

(V) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या—लगभग 680

हम आगे यह करार करते हैं कि माध्यस्थ का विनिश्चय हम पर बाबद्धकर होगा।

माध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की अवधि के भीतर या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि ऊपर वर्णित अवधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता, तो माध्यस्थम् के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नये माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

तारीख 1971 की फरवरी का 26 वां दिन

पक्षकारों के हस्ताक्षर

निर्णायकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

ह०/-एस० जी० टेकवानी

ह०/-पी० एम० नायडु

ज्येष्ठ उप प्रबन्धक (पीओ),

अध्यक्ष,

भारतीय खाद्य निगम,

पोर्ट खलासीज यूनियन

विशाखापट्टणम - 1.

(इंटेक),

विशाखापट्टणम-1

साक्षी :—

ह०/-

1. श्री टी० बी० एन० रेड्डी,

सीनियर ऐसीस्टेंट मैनेजर।

ह० -

2. श्री एस० नागी रेड्डी,

ऐसीस्टेंट मैनेजर।

[सं० 76/11/70-पी० और बी०]

अजीत चन्द्र, अधीक्षक सचिव।

(DEPARTMENT OF REHABILITATION)

(Office of the Chief Settlement Commissioner)

New Delhi, the 3rd July 1971

S.O. 2814.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation Act, 1954) (44 of 1954) and in supersession of this office notification No. 3(2)LR/67, dated the 24th December, 1970, the Central Government hereby appoints the Sub-Divisional Officer (Civil), Una and Naib Tehsildar (Sales), Una and Sub-Divisional Officer (Civil), Kangra and Naib-Tehsildar, (Sales) Kangra in Himachal Pradesh as Settlement Officers and Managing Officers respectively in their respective jurisdictions of (1) District Simla, Tehsil Una of Kangra district and Mahasu, Bilaspur

and Sirmur districts, and (ii) Kangra District (excluding Una Tehsil), Kulu, Lahaul and Spiti, Chamba and Mandi Districts, for the purpose of performing, in addition to their own duties as Sub-Divisional Officers (Civil) and Naib Tehsildars (Sales), the functions assigned to Settlement Officer and Managing Officer by or under the said Act in respect of (i) urban acquired evacuee properties and urban agricultural lands and (ii) rural acquired evacuee properties including agricultural lands and shops, houses, cattle-sheds and vacant sites in any rural area, forming part of the Compensation Pool.

[No. 3(2)/L&R/67.]

JANKI NATH, Under Secy.
and Settlement Commissioner.

(पुनर्वास विभाग)

(मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त कार्यालय)

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1971

एस० ओ० 2814—विस्थापित व्यक्तियों की धारा 3 की उपधारा (1) (क्षति-पूर्ति तत्पयी पुनर्वास अधिनियम, 1954) (1954 का 44) द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा 24 दिसम्बर, 1970 के इस कार्यालय की अधिसूचना सं० 3(2) एल आर। 67 का अधिलेखन करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा उप मंडल अधिकारी (सिविल), ऊना, तथा नायब तहसीलदार, (विक्रय), ऊना तथा उप मंडल अधिकारी, (सिविल), कांगडा, तथा नायब तहसीलदार (विक्रय), कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को क्रमशः बन्दोबस्त अधिकारी तथा प्रबन्धक अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है जो अपने-अपने क्षेत्रों शिमला जिलों कांगड़ा जिले की ऊना तहसील, तथा माहसू, विलासपुर तथा सिरमौर जिले के क्षेत्रों में तथा (ii) कांगड़ा जिलों (ऊना तहसील को छोड़कर) कुलू, लाहौल तथा स्पीटी, चम्बा तथा मंडी जिलों में, उप-मंडल, अधिकारी (सिविल) तथा नायब तहसीलदार (विक्रय) के रूप में अपनी-अपनी ज्यूटी का पालन करने के साथ-साथ उक्त अधिनियम के अधीन एवं द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी तथा प्रबन्धक अधिकारी को सौंपे गये कार्यों का सम्पदान करने के उद्देश्य से ऐसे कार्य करेंगे, जो (i) निष्क्रांत सम्पत्ति तथा शहरी कृषि भूमि तथा (ii) ग्रामीण अधिग्रहीत निष्क्रांत, जिसमें कृषियोग्य भूमि, तथा दुकानों, मकानों, पशुशालाएँ तथा किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के खाली स्थानों से सम्बन्धित हैं तथा जो क्षति-पूर्ति विक्रय के अंग हैं।

[सं० 3(2)/एज० और आर०]

जानकी नाथ अवसर सचिव तथा बन्दोबस्त आयुक्त

(Department of Rehabilitation)

(Office of the Chief Settlement Commissioner)

New Delhi, the 6th July 1971

S.O. 2815.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under Section 33 of the said Act, shall be exercisable also by the Secretary to the Government of Himachal Pradesh (Relief & Rehabilitation) in respect of proceedings pertaining to acquired urban and rural properties and urban and rural agricultural lands forming part of the Compensation Pool, transferred to the State Government in 'Package Deal' or under the administrative and financial arrangements, subject to the condition that he shall not exercise

any of such powers in relation to any matter in which an order has been made by him in any other capacity.

[No. 3(16)/L&R/69.]

D. KRISHNA AYYAR, Jt. Secy.

(पुनर्वास विभाग)

(मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, 7 जुलाई 1971

एस० ओ० 2815.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (1) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम की धारा 33 की शक्तियाँ भी हिमाचल प्रदेश (सहायता तथा पुनर्वास) के सचिव को प्रयोग करने का आदेश देती है ताकि वे "पैकजडीज" या प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थाओं के अधीन राज्य को हस्तान्तरित प्रतिकर पूल की अर्जित शहरी तथा ग्रामीण सम्पत्तियों और शहरी तथा ग्रामीण कृषि भूमियों के विषय में कार्यवाही कर सके। वे इन अधिकारों का उन मामलों में प्रयोग नहीं करेंगे जिनके फैसले वे किसी और पद की हैसियत में पहले कर चुके हैं।

[संख्या 3 (16)/एल० तथा आर०/69]

ध० कृष्णा अय्यर, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 5th July 1971

S.O. 2816.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) (2nd Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 18th day of January, 1971.

2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in the Fifth Schedule, in paragraph 2, after the entry "Deputy Assistant Director General (M.S.) and Depot Managers of the Government Medical Store Depots functioning as Head of Depots", the entry "Director, National Fire Service College, Nagpur" shall be inserted.

[No. 2(14)-EV(B)/71.]

S. S. L. MALHOTRA, Under Secy.

(Department of Banking)

New Delhi the 19th June 1971.

S. O. 2817.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 4th June 1971
BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES		Rs.	ASSETS		Rs.
Capital Paid Up		5,00,00,000	Notes		11,79,48,000
Reserve Fund		150,00,00,000	Rupee Coin		2,18,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund .		172,00,00,000	Small Coin		3,77,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund . . .		37,00,00,000	Bills Purchased and Discounted:—		
			(a) Internal		16,67,92,000
			(b) External
			(c) Government Treasury Bills.		29,05,65,000
			Balances Held Abroad*		90,15,64,000
			Investments**		61,70,51,000
			Loans and Advances to:—		
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund .		95,00,00,000	(i) Central Government
			(ii) State Governments @		358,88,71,000
Deposits:—			Loans and Advances to:—		
(a) Government			(i) Scheduled Commercial Banks†		139,27,77,000
(i) Central Government		56,16,21,000	(ii) State Co-operative Banks††		224,78,63,000
(ii) State Governments		4,04,41,000	(iii) Others		6,78,85,000
(b) Banks			Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund		
(i) Scheduled Commercial Banks		194,72,91,000	(a) Loans and Advances to:—		
(ii) Scheduled State Co-operative Banks		10,13,16,000	(i) State Governments		42,03,32,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks		76,19,000	(ii) State Co-operative Banks		20,21,39,000
(iv) Other Banks		34,71,000	(iii) Central Land Mortgage Banks
			(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures		..
			Loans and advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.		9,62,09,000

(c) Others	64,01,78,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks. Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.	947,39,000
Bills Payable	70,56,56,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank	39,01,21,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank
Other Liabilities	<u>255,55,76,000</u>	Other Assets	<u>55,77,18,000</u>
	Rupees		Rupees.
	1115,31,69,000		1115,31,69,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Government.

†Includes Rs. 68,06,92,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 4th day of June 1971.

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department.	11,79,48,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	4424,76,70,000		(a) Held in India.	182,53,11,000	
Total Notes issued		4436,56,18,000	(b) Held outside India.		
			Foreign Securities.	278,42,00,000	
			TOTAL		460,95,11,000
			Rupee Coin		37,68,61,000
			Government of India Rupee Securities.		3937,92,46,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper.		
TOTAL LIABILITIES		4436,56,18,000	TOTAL ASSETS		4436,56,18,000

Dated the 9th day of June 1971.

S. JAGANNATHAN,
Governor.

[No. F.3(3)-BC/71]

वित्त मंत्रालय
(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 19 जून, 1971

एस० ओ० 2817

4 जून 1971 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	प्राप्तियां	रुपये
चुक्ता पूंजी	5,00,00,000	नोट	11,79,48,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपय का सिक्का	2,18,000
		छोटा सिक्का	3,77,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	172,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	37,00,00,000	(क) देशी	16,67,92,000
		(ख) विदेशी	
		(ग) सरकारी खजाना बिल	28,05,65,000
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	95,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	90,15,64,000
जमा राशियां :—		निवेश**	61,70,51,000
(क) सरकारी		ऋण और अप्रिम	
(i) केन्द्रीय सरकार	56,16,21,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	
(ii) राज्य सरकारें	4,04,41,000	(ii) राज्य सरकारों को	358,88,71,000
(ख) बैंक		ऋण और अप्रिम	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	194,72,91,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	139,27,77,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	10,13,16,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को††	224,78,63,000
		(iii) दूसरों को	6,78,85,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अप्रिम और निवेश	

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	76,19,000	(क) ऋण और अग्रिम	-
(iv) अन्य बैंक	34,71,000	(i) राज्य सरकारों को	42,03,32,000
(ग) अन्य	64,01,78,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	20,21,39,000
देश बिल	0,58,56,000	(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	9,62,08,000
अन्य देयताएं	255,63,78,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	9,47,39,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और	
		अग्रिम राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	
		से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	39,01,21,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गए बांडों।	
		डिबेंचरों में निवेश	55,77,18,000
		अन्य आस्तियां	
रुपये	1115,31,69,000	रुपये	1115,31,69,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय [कृषि ऋण] (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की धारा 17(4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 68,06,92,000/ रुपये शामिल हैं।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

एस० जगन्नाथन,
गवर्नर।

तारीख 9 जून, 1971

रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जून 1971 को 4 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा
इस विभाग

वेयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	11,79,48,000		सोने का सिक्का और बुलियन :-		
संचलन में नोट	4424,76,70,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
जारी किए गए कुल नोट		4436,56,18,000	(ख) भारत के बहार रखा हुआ		
			विदेशी प्रतिभूतियां	278,42,00,000	
			जोड़		460,95,11,000
			रुपये का सिक्का		37,68,61,000
			भारत सरकार की रूपया प्रतिभूतियां		3937,92,46,000
			देशी विनिमय बिल और		-
			दूसरे वाणिज्य पत्र		
कुल वेयताएं		44,36,56,18,000	कुल अस्तियां		4436,56,18,000

एस जगन्नाथन

गवर्नर

तारीख 9 जून 1971

[सं० एफ० 3(3)- बी०सी०/71]

New Delhi, the 2nd July 1971

S. O. 2818.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 18th June 1971.

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	25,03,38,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	3,71,000
		Small Coin	4,03,000
		Bills Purchased and Discounted:—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund .	172,00,00,000	(a) Internal	12,85,69,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund . . .	37,00,00,000	(b) External	12,09,87,000
		(c) Government Treasury Bills	81,63,04,000
		Balances Held Abroad*	59,14,16,000
		Investments**	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund. .	[95,00,00,000	Loans and Advances to:—	
		(i) Central Government	
		(ii) State Governments@	428,61,58,000
Deposits:—		Loans and Advances to:—	
(a) Government		(i) Scheduled Commercial Banks†	179,73,62,000
(i) Central Government	128,06,06,000	(ii) State Co-operative Banks††	211,44,31,000
(ii) State Governments	2,68,27,000	(iii) Others	7,62,50,000
(b) Banks		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund.	
(i) Scheduled Commercial Banks.	216,48,99,000	(a) Loans and Advances to:—	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks.	11,83,65,000	(i) State Governments	42,01,89,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks.	[81,44,000	(ii) State Co-operative Banks.	20,95,40,000
(iv) Other Banks, &c.	25,24,000	(iii) Central Land Mortgage Banks.	
		(b) Investments in Central and Mortgage Bank Debentures	
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.	10,14,98,000

		Loans and Advances to State Co-operative Banks .		11,07,59,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund—		
(c) Others	61,43,16,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank		43,18,21,000
Bills Payable	40,72,97,000	(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank
Other Liabilities	281,03,50,000	Other Assets		56,69,32,000
Rupees		Rupees		1202,33,28,000
				1202,33,28,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 95,84,62,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 23rd day of June, 1971.

An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 18th day of June, 1971.

ISSUE DEPARTMENT.

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department.	25,03,38,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	<u>4475,53,99,000</u>		(a) Held in India.	182,53,11,000	
Total Notes Issued.		4500,57,37,000	(b) Held outside India
			Foreign Securities.	<u>293,42,00,000</u>	
			TOTAL		475,95,11,000
			Rupee Coin		36,69,19,000
			Government of India Rupee Securities.		3987,93,07,000
			Internal Bills of Exchange and other Com- mercial paper.
TOTAL LIABILITIES.		4500,57,37,000	TOTAL ASSETS.		4500,57,37,000

Dated the 23rd day of June, 1971.

S. JAGANNATHAN,
Governor.

R. K. SUNDARESAN, Under Secy.

[No. F. 3(3)-BC/71]

CORRIGENDUM

In the statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on 16th April 1971 published at page 2840 of part II-Section 3 (ii) of the Gazette of India issue dated 15th May 1971 the figure against head "Foreign Securities" appearing on the Assets side of the statement should be read as 288,42,00,000 instead of 286,42,00,000.

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1971

एस० न्रो० 2818—18 जून 1971 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यालय का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियाँ	रुपए
वृकता पंजी	5,00,00,000	नोट	25,03,38,000
प्रारक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	3,71,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	4,03,000
(दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	172,00,00,000	खरीदे और मुनाये गये बिल :—	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	12,85,69,000
(स्थिरीकरण) निधि	37,00,00,000	(ख) विदेशी	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		(ग) सरकारी खजाना बिल	12,09,87,000
(दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि	95,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	81,63,04,000
जमा राशियाँ :—		निवेश**	59,14,16,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम :—	
(i) केन्द्रीय सरकार	128,06,06,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	
(ii) राज्य सरकारें		(ii) राज्य सरकारों को @	428,61,58,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	216,48,99,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को †	179,73,62,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	11,83,65,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को ‡	211,44,31,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	81,44,000	(iii) दूसरों को	7,62,50,000

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
(iv) अन्य बैंक	25,24,000	(क) ऋण और अग्रिम	42,01,98,000
		(i) राज्य सरकारों को	20,95,40,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को
		(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को
(ग) अन्य	61,43,16,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,14,98,000
देय बिल	40,72,97,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	11,07,59,000
अन्य देयताएं	281,03,50,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	11,07,59,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	43,18,21,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए बांडों/डिबेंचरों में निवेश	1,56,69,32,000
		अन्य आस्तियां	
	रुपये 1202,33,28,000	रुपये	1202,33,28,000

* नगदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

** राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि में से किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थाई ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

† रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिए गए 95,84,62,000 रुपये शामिल हैं।

‡ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख 23 जून 1971

एस० जगन्नाथन,
गवर्नर।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण म जून 1971 की 18 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा
इशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियाँ	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	25,03,38,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
संचयन में नोट	4475,53,99,000		(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
			विदेशी प्रतिभूतियाँ	293,42,00,000	
			जोड़		475,95,11,000
जारी किए गये कुल नोट		4500,57,37,000	रुपये का सिक्का		36,69,19,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ		3987,93,07,000
			देशी विनियम बिल और दूसरे		
			वाणिज्य पत्र		..
कुल देयताएँ		4500,57,37,000	कुल आस्तियाँ		4500,57,37,000

तारीख 23 जून 1971

एस० जगन्नाथन, गवर्नर

[सं० एफ० 3(3)-बी० सी०/71]

शुद्धिपत्र

आर० के० सुन्दरसन,

भारत के राजपत्र के 15 मई, 1971 के अंक के भाग II, खंड 3(ii) के पृष्ठ 2840 में प्रकाशित 16 अप्रैल, 1971 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप के विवरण के आस्तियों वाले पक्ष में "विदेशी प्रतिभूतियां" शीर्षक के सामने 286,42,00,000 की जो संख्या छपी है, उसके बदले 288,42,00,000 संख्या पढ़ी जाए।

(Department of Banking)

New Delhi, the 26th June 1971

S.O. 2819.—Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, as on the 11th June 1971.

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	12,01,38,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupees Coin	3,27,000
		Small Coin.	3,75,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund.	172,00,00,000	Bills Purchased and Discounted:—	
		(a) Internal	13,73,78,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	37,00,00,000	(b) External
		(c) Government Treasury Bills	38,59,05,000
		Balances Held Abroad*	81,02,61,000
		Investments**	52,49,18,000
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	95,00,00,000	Loans and Advances to:—	
		(i) Central Government	
Deposits:—		(ii) State Governments@	390,39,61,000
(a) Government		Loans and Advances to:—	
(i) Central Government	89,36,43,000	(i) Scheduled Commercial Banks†	15,62,97,000
(ii) State Governments	3,43,09,000	(ii) State Co-operative Banks‡	221,78,80,000
		(iii) Others	7,13,00,000
(b) Banks		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(i) Scheduled Commercial Banks	213,72,49,000	(a) Loans and Advances to:—	
(ii) Scheduled State Co-operative Banks, §	11,74,00,000	(i) State Governments	42,03,32,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	81,43,000	(ii) State Co-operative Banks	20,30,86,000
(iv) Other Banks.	37,90,000	(iii) Central Land Mortgage Banks
(c) Others	60,28,91,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.	9,62,09,000

Bills Payable	31,84,91,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.	10,91,14,000
Other Liabilities	279,93,15,000	(a) Loans and Advances to the Development Bank	39,55,21,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank
		Other Assets.	56,22,29,000
Rupees	1150,52,31,000	Rupees	1150,52,31,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 89,09,62,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

‡Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 16th day of June, 1971.

P. N. DAMRY,
Dy. Governor.

An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 11th day of June, 1971.

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department.	12,01,38,000		Gold Coin and Bullion:—		
Notes in circulation	4502,91,06,000		(a) Held in India	182,53,11,000	
Total Notes issued		4514,92,44,000	(b) Held outside India	
			Foreign Securities	293,42,00,000	
			TOTAL		475,95,11,000
			Rupee Coin		36,04,73,000
			Government of India Rupee Securities.		4002,92,60,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper.
TOTAL LIABILITIES		4514,92,44,000	TOTAL ASSETS		4514,92,44,000

Dated the 16th day of June 1971.

P. N. DAMRY,
Dy. Governor.

[No. F. 3(3)-BC/71]

A. BAGCHI, Under Secy

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 26 जून 1971

एस० ग्रा० 2819.—11 जून 1971 को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के बैंकिंग विभाग के कार्यालय का विवरण

देयताएँ	रुपये	आस्तिया	रुपये
चुक्ता पूंजी	5,00,00,000	नोट	12,01,38,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	3,27,000
		छोटा सिक्का	3,75,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि	172,00,00,000	खरीदे और भुनाए गये बिल :—	
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	37,00,00,000	(क) देशी	13,73,78,000
		(ख) विदेशी
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि	95,00,00,000	(ग) सरकारी खजाना बिल	38,59,05,000
जमा राशियाँ :—		विदेशों में रखा हुआ बकाया *	81,02,61,000
(क) सरकारी		निवेश**	52,49,18,000
(i) केन्द्रीय सरकार	89,36,43,000	ऋण और अग्रिम :—	
(ii) राज्य सरकारें	3,43,09,000	(i) केन्द्रीय सरकार को
(ख) बैंक		(ii) राज्य सरकारों को†	390,39,61,000
(i) अनुसूचित वाणिज्य बक	213,72,49,000	ऋण और अग्रिम :—	
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	11,74,00,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को††	154,62,97,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को@	221,78,80,000
		(iii) दूसरों को	7,13,00,000

देयताएँ	रुपये	आस्तियाँ	रुपये
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम	
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	81,43,000	(i) राज्य सरकारों को	42,03,32,000
(iv) अन्य बैंक	37,90,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	20,30,86,000
(ग) अन्य	60,28,91,000	(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को	
		(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	9,62,09,000
देय बिल	31,84,91,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरी करण) निधि से ऋण और अग्रिम	
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	10,91,14,000
अन्य देयताएँ	279,93,15,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	39,55,21,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गए बांडों/डिबेंचरों में निवेश अन्य आस्तियाँ	56,22,29,000
	रुपये 1150,52,31,000		रुपये 1150,52,31,000

* नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

** राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि में से किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों के अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†† रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम की धारा 17 (4) (ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 89,09,62,000,,
ऋण रुपये शामिल हैं।

@ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख : 16 जून 1971

पी० एन० डामरी, उप गवर्नर।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में जून 1971 की 11 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा
इशु विभाग

देयताएं	रुपये	पये	अस्तित्वा	रुपये	पये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए			सोने का सिक्का और बुलियन :—		
नोट	12,01,38,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,11,000	
संचलन में नोट	4502,91,06,000		(ख) भारत के बाहर रखा		
			हुआ		
			विदेशी प्रतिभूतियां	253,42,00,000	
जारी किए गये कुल नोट		45,14,92,44,000			
			जोड़		475,9511,000
			रुपये का सिक्का		30,04,73,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ		4002,92,60,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे		
			वाणिज्य पत्र		
कुल देयताएं		4514,92,44,000	कुल अस्तित्वा		4514,92,44,000

तारीख 16 जून 1971

पी० एन० डामरी,

उप गवर्नर

[सं० एफ० 3 (3)-बी० सी०/71]

अ० बागची, अनु सचिव ।

(Department of Banking)

New Delhi, the 1st July 1971

S.O. 2820.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the Dubey Co-operative Commercial Bank Ltd., Bilaspur, for the period 31st December, 1970 to 29th February, 1972.

[No. F. 15-6/71-Ac II.]

L. D. KATARIA, Dy. Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली 1 जुलाई, 1971

एस० नो० 2720.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का दसवां) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबन्ध दूबे को-ऑपरेटिव कामर्शियल बैंक लिमिटेड, बिलासपुर पर 31 दिसम्बर, 1970 से 29 फरवरी, 1972 तक की अवधि के दौरान लागू नहीं होंगे ।

[सं० एफ० 15-6/71-ए० सी० II.]

एल० डी० कटारिया, उप सचिव ।

(Department of Economic Affairs)

(Office of the Controller of Capital Issues)

New Delhi, the 15th June 1971

S.O. 2821.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 6 of the Capital Issues (Control) Act, (29 of 1947), the Central Government hereby exempt the Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, from the provisions of Section 3 and 5 of the said Act, in respect of issue of Promissory Notes of the value not exceeding D.M. 10,000,000 (Ten Million Deutsche Marks) to be made by the said Corporation to Kreditanstalt Fur Wiederaufbau of the Federal Republic of Germany in terms of the Loan Agreement to be entered into between the said two parties.

[No. R-95. CCI/71-1363.]

RAJ K. NIGAM,

Addl. Controller of Capital Issues.

आर्थिक कार्य विभाग

पूँजी इशारा नियंत्रक का कार्यालय

नई दिल्ली, 15 जून, 1971

एस० नो० 2821.—कपिटल इश्यूज (कंट्रोल) एक्ट (1947 का 29) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय औद्योगिक उधार और विनिधान निगम लिमिटेड को उक्त निगम द्वारा फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के क्रेडिटैन्स्टैट फर वीडेराफबॉ को उक्त दो पक्षकारों के बीच किये जाने वाले उधार के करार के निबन्धनों के अनुसार,

जारी किये जाने वाले 10,000,000 द० मा० (एक करोड़ वृत्त्ये मार्क) से अनधिक मूल्य के वचनपत्र जारी करने की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 3 और 5 के उपबन्धों से एतद्वारा छूट देती है।

[सं० आर० 95-सी० सी० आई०/71-1363]

राज के० निगम,

अपर पूंजी-इजारा-नियंत्रक

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX

New Delhi, the 14th June 1971

S.O. 2822.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises Shri M. P. Samudra who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from 21st June, 1971.

[No. 177/F. No. 404/62/71-ITCC.]

(राजस्व और बीमा विभाग)

आयकर

नई दिल्ली, 15 जून 1971

एस० ओ० 2822.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एम० पी० समुद्रा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना 21 जून, 1971 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 177/फा०सं० 404/62/71-आई० टी० सी० सी०]

S.O. 2823.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises Shri M. D. Phadnis who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from 21st June, 1971.

[No. 179/F. No. 404/62/71-ITCC.]

एस० ओ० 2823.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एम० डी० फणनीस को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं० 179/फा०सं० 404/62/71-आई० टी० सी० सी०]

S.O. 2824.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises Shri T. M. Ramaswamy who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

1. This Notification shall come into force on the 21st June, 1971.

[No. 182/F. No. 404/46/71-ITCC.]

एस० प्रो० 2824 —आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री टी० एम० रामस्वामी को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना 15 फरवरी, 1971 से प्रवृत्त होगी।

[स० 182/फा०/404/46/71—आई० टी० सी० सी०]

New Delhi, the 18th June 1971

S.O. 2825.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises:

1. Shri S. V. Panjwani
2. Shri R. K. Chauha
3. Shri K. L. Batra
4. Shri Krishan Kumar

who are Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from 1st July, 1971.

[No. 194/F. No. 404/35/71-ITCC.]

S. K. LALL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 जून, 1971

एस० प्रो० 2825.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 1. श्री एस० वी० पन्जवानी 2. श्री आर० के० चौहला 3. श्री के० एल० बत्रा 4. श्री कृष्ण कुमार को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1971 से प्रवृत्त होगी।

[स० 194/फा० सं० 404/35/71—आई० टी० सी० सी०]

एस० के० लाल,

उप सचिव।

(Department of Revenue and Insurance)

ESTATE DUTY

New Delhi, the 28th June 1971

S.O. 2826.—Whereas the Legislature of the State of Haryana has passed the resolution under clause (i) of article 352 of the Constitution, adopting the amendments made to, or in relation to, the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), by—

- (i) the Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963),
- (ii) the Finance Act, 1964 (5 of 1964),
- (iii) the Taxation Laws (Continuation of Validation of Recovery Proceedings) Act, 1964 (11 of 1964),
- (iv) the Direct Taxes (Amendment) Act, 1964 (31 of 1964),

- (v) the Finance Act, 1965 (10 of 1965),
- (vi) the Finance (No. 2) Act, 1965 (15 of 1965),
- (vii) the Taxation Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1965 (41 of 1965), and
- (viii) the Finance Act, 1966 (13 of 1966),

in so far as they relate to estate duty in respect of agricultural lands situate in the territories comprised in the said State;

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in clause (b) of sub-section (2A) of Section 5A of the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953), the Central Government hereby specifies the State of Haryana to which the above mentioned amendments shall apply, and shall be deemed to have applied, on the from the dates on which the amendments made by each of the Acts aforesaid respectively took effect, to estate duty in respect of agricultural lands situate in its territories.

[No. 9(71)/F. No. 1/9/64-E.D.]

BALBIR SINGH, Dy. Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

संपदा शुल्क

नई दिल्ली 28 जून 1971

का० आ० 2826.—यतः हरियाणा राज्य के विधान मण्डल ने संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (i) के अधीन निम्नलिखित द्वारा संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) में या उसके सम्बन्ध में किए गए संशोधनों को, जहां तक कि वे उक्त राज्य में समाविष्ट राज्यक्षेत्र में स्थित कृषि भूमि के विषय में संपदा शुल्क से सम्बन्धित हों:—

- (i) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54)
 - (ii) वित्त अधिनियम, 1964 (1964 का 5)
 - (iii) कर विधि (वसूली कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण चालू रखना) अधिनियम, 1964 (1964 का 11)
 - (iv) प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964 (1964 का 11)
 - (v) वित्त कर, 1965 (1965 का 10)
 - (vi) वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1965 (1965 का 15)
 - (vii) करविधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1965 (1965 का 41)
- और
- (viii) वित्त अधिनियम, 1966 (1966 का 13)

अतः अब, संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 5क की उपधारा (2क) के खण्ड (ख) में समाविष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा हरियाणा राज्य को विनिर्दिष्ट करती है जिसको कि ऊपर उल्लिखित संशोधन लागू होंगे और, उपरोक्त अधिनियमों में से प्रत्येक द्वारा बनाए गए संशोधन क्रमशः जिन जिन तारीखों को और से प्रभावी हुए, उन तारीखों को इसके क्षेत्र में स्थित कृषि के संबंध में संपदा शुल्क को लागू हुए समझे जाएंगे।

[सं० 9 (71)/एफ० सं० 1/9/64 ई०डी०]

बलबीर सिंह, उप सचिव।

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX

New Delhi, the 1st July 1971

S.O. 2827.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Indian Council of Medical Research, the 'prescribed authority' for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961:

Institution

Indian Medical Research Society, Bombay.

[No. 203/F. No. 203/12/71-IT(AII).]

(राजस्व और बीमा विभाग)

आयकर

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1971

एस० ओ० 2827.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए "विहित प्राधिकरण" अनुमोदित किया गया है।

संस्था

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान सोसाइटी, मम्बई,

[सं० 203/फा० सं० 203/12/71—आई० टी० (ए० 2)]

S.O. 2828.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Council of Scientific and Industrial Research, the prescribed authority, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961):

Institution

The Institute of Engineers (India), Calcutta.

[No. 204/F. No. 203/13/71-ITAIL.]

S. N. NAUTIAL, Dy. Secy.

एस० ओ० 2828.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए "विहित प्राधिकरण" अनुमोदित किया गया है।

संस्था

इंजीनियर संस्थान (भारत), कलकत्ता।

[सं० 204/फा० सं० 203/13/71—आई० टी० ए० 2]

एस० एन० नौटियाल, उप सचिव।

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

INCOME-TAX

New Delhi, the 21st April 1971

S.O. 2829.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following amendments

In the Schedule appended to its Notification No. 34 (F. No. 261/8/70-ITJ) dated 25th March, 1970 and No. 45 (F. No. 261/7/70-ITJ) dated 31st March, 1970, viz. Against Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Aurangabad Range, Aurangabad under Col. No. 2. the following shall be added:

Sr. No. 11 Income-tax Officer, A-Ward, Jalna.

Sr. No. 12 Income-tax Officer, B-Ward, Jalna.

This notification shall take effect from 1st May, 1971.

Explanatory Note

This amendment has become necessary on account of creation of two new charges of the Income-tax Officer at Jalna.

(This note does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 126 (F. No. 261/9/71-ITJ).]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 1971

एस० ओ० 2829.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे उस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 34 (फा० सं० 261/8/70 आई० टी० जे०) तारीख 25 मार्च, 1970 और सं० 45 (फा० सं० 261/7/70 आई० टी० जे०) तारीख 31 मार्च, 1970 से उपाबद्ध अनुसूची में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

सहायक आयकर आयुक्त (अधीन) औरंगाबाद रेंज, औरंगाबाद के सामने स्तम्भ सं० 2 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

क्रम सं० 11 आयकर अधिकारी, ए—वार्ड, जालना।

क्रम सं० 12 आयकर अधिकारी, बी—वार्ड, जालना।

यह अधिसूचना प्रथम मई, 1971 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण :—

यह संशोधन जालना में आयकर अधिकारी के दो नए भारसाधनों की सृष्टि के कारण आवश्यक हुआ है।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है बल्कि इसका आशय स्पष्टीकरण मात्र है।)

[सं० 126/का० सं० 261/9/71—आई० टी० जे०]

New Delhi, the 30th April 1971

S.O. 2830.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in that behalf and in modification of Notification No. 185 (F. No. 261/17/70-ITJ) dated 23rd November, 1970, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 1 of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to income-tax or super-tax, or wealth-tax or gift-tax or expenditure tax, in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in corresponding entry in

column 2 thereof, excepting those that have been specifically allotted to the Appellate Controller of Estate Duty, Hyderabad by Notification No. 140 (F. No. 261/11/71-ITJ) dated the 30th April, 1971.

A.A. C.'s Range	Income-tax Circle, Ward and District.
(1)	(2)
1. A-Range, Hyderabad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Circle-III, Hyderabad 2. Company Circle, Hyderabad. 3. Salary Circle, Hyderabad. 4. Nizamabad. 5. Company Ward of Secunderabad Circle, Hyderabad. 6. Company Circle (Old), Hyderabad.
2. B-Range, Hyderabad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Circle-II (Old), Hyderabad. 2. Circle-II, Hyderabad. 3. Special Circle, Hyderabad. 4. Central Circle, Hyderabad. 5. Nirmal. 6. Central Circle (Old), Hyderabad. 7. Sangareddy.
3. C-Range, Hyderabad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Circle-I, Hyderabad. 2. Kothangudem. 3. Project Circle, Hyderabad. 4. Warangal Circle, Hyderabad. 5. M.P.P. Circle, Hyderabad. 6. Karimnagar. 7. Khammam.
4. Visakhapatnam Range, Visakhapatnam.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visakhapatnam. 2. Vizianagaram. 3. Crikakulam. 4. Bobbili. 5. Anakapalli. 6. Circle-I, Kakinada. 7. Circle-II, Kakinada. 8. Ramachandrapuram (Old) 9. Kakinada (Old). 10. Amalapuram. 11. Rajahmundry. 12. Palacole.
5. Vijayawada Range, Vijayawada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vijayawada Circle. 2. Machilipatnam. 3. Gudivada. 4. Eluru. 5. Tanuku. 6. Tenali. 7. Bapatla.
6. Guntur Range, Guntur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guntur. 2. Nellore. 3. Mica Circle, Nellore. 4. Cuddapah. 5. Tirupathi.
7. Anantapur Range, Anantapur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anantapur. 2. Hindupur. 3. Adoni. 4. Proddatur. 5. Chittoor. 6. Kurnool. 7. Nandyal. 8. Mahaboobnagar.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom the Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date of this notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1st May, 1971.

Explanatory Note:

The amendment have become necessary on account of the re-allocation of jurisdiction of the Appellate Assistant Commissioners in the charges of Andhra Pradesh I & II.

(This note does not form a part of the Notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 139/F. No. 261/11/71-ITJ.]

नई दिल्ली, 30 अप्रैल 1971

एस० ओ० 2830.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे उस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं० 185 (फा० सं० 261/17/70—आई० टी० जे०) तारीख 23 नवम्बर, 1970 के उपांतरण में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि निम्नलिखित अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आयकर आयुक्त (अपील) उन कृत्यों को छोड़कर जो अधिसूचना सं० 140 (फा० सं० 261/11/71—आई० टी० जे०) तारीख 30 अप्रैल, 1971 द्वारा सम्पदा सम्पदा शुल्क अपील नियंत्रक, हैदराबाद को विनिर्दिष्टतः आवंटित किए गए हैं, उसके स्तंभ 2 को तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सफिलों, बोर्डों और जिलों में आयकर या अतिकर, या धनकर या दानकर अथवा व्ययकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आयों की वास्त अपने कृत्यों का पालन करेंगे।

सहायक आयुक्त, (अपील) रेंज	आयकर सफिल, बाई और जिला
(1)	(2)
1. क—रेंज, हैदराबाद	1 सफिल, III, हैदराबाद 2 कम्पनी सफिल, हैदराबाद 3 बेतन सफिल, हैदराबाद 4 निजामाबाद 5 सिकन्दराबाद सफिल का कम्पनी बाई, हैदराबाद 6 कम्पनी सफिल (पुराना), हैदराबाद।
2. ख—रेंज, हैदराबाद	1 सफिल—II (पुराना), हैदराबाद 2 सफिल—II, हैदराबाद 3 विशेष सफिल, हैदराबाद 4 केन्द्रीय सफिल, हैदराबाद

(1)

(2)

-
- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| | 5 निर्मल |
| | 6 केन्द्रीय सर्किल (पुराना), हैदराबाद |
| | 7 संगरेड्डी |
| 13. ग—रेंज, हैदराबाद | 1 सर्किल—I, हैदराबाद |
| | 2 कोठान गुडेम |
| | 3 परियोजना सर्किल, हैदराबाद |
| | 4 धारंगल सर्किल, हैदराबाद |
| | 5 एम०पी० पी० सर्किल, हैदराबाद |
| | 6 करीमनगर |
| | 7 खमाम |
| 14. विशाखापत्तनम | 1 विशाखापत्तनम |
| रेंज, विशाखापत्तनम | 2 विजिएनाग्राम |
| | 3 श्री काकुलम |
| | 4 बोड्डिली |
| | 5 अनाकापाली |
| | 6 सर्किल—I, काकीनाड़ा |
| | 7 सर्किल—II, काकीनाड़ा |
| | 8 रामाचन्द्रापुरम (पुराना) |
| | 9 काकीनाड़ा (पुराना) |
| | 10 अमलापुरम |
| | 11 राजामुन्द्री |
| | 12 पालसूले |
| 15. विजयवाड़ा रेंज, | 1 विजयवाड़ा सर्किल |
| विजयवाड़ा | 2 मठलीपत्तनम |
| | 3 कूडीवाड़ा |
| | 4 इलरू |
| | 5 टानुकु |
| | 6 तैनाली |
| | 7 बेपाटला |
| 16. गुन्टूर रेंज, गुन्टूर | 1 गुन्टूर |
| | 2 नेल्लोर |
| | 3 माइका सर्किल, बेल्लोर |
| | 4 कूडप्पा |
| | 5 तिरुगथी |
-

(1)

(2)

7. अनन्तपुर

1 अनन्तपुर

2 निन्दुपुर

3 अदोनी

4 परोदाटूर

5 चित्तौड़

6 कुरुनूल

7 नन्ड्याल

8 महबूबनगर

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सर्किल, बोर्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज को अन्तरित हो गया हो वहां उस आय-कर सर्किल, बोर्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणाम स्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिस से वह आय-कर सर्किल, बोर्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थी, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, बोर्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दो जाएंगे जो उन के संबंध में कार्यवाही करेगा ।

यह अधिसूचना प्रथम मई, 1971 से प्रभावी होगी ।

स्पष्टीकारक टिप्पण : —

यह संशोधन आन्ध्र प्रदेश, 1 और 11 के भारसाधनों में सहायक आयुक्तों (अपील) की अधिकारिता के पुनः आखंडन के कारण आवश्यक हुआ है ।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है बल्कि इसका आशय स्पष्टीकरण मात्र है ।)

[सं० 139/फा० सं० 261/11/71—आई० टी० जे०]

S.O. 2831.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) in modification of Notification No. 83 (F. No. 261/17/70-ITJ) dated the 20th May, 1970 and No. 17 (F. No. 39/1/67-ED) dated the 27th February, 1969 the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner appointed to be an Appellate Controller of Estate Duty, Hyderabad shall in addition to the functions of Appellate Controller of Estate Duty, Hyderabad also perform the functions of Appellate Assistant Commissioner in respect of all persons assessed to Direct Taxes other than Income-tax viz., Gift-tax, Wealth-tax and Expenditure-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in column 1 below, which functions the Appellate Assistant Commissioners noted in column 2, shall henceforth cease to perform:—

SCHEDULE

Income-tax Circle, Ward, District.	A.A.C.'s Range.
(1)	(2)
1. Circle-III, Hyderabad.	A-Range, Hyderabad.
2. Company Circle, Hyderabad.	
3. Company Ward of Secunderabad Circle, Hyderabad.	

(1)	(2)
4. Company Circle, (Old), Hyderabad.	
5. Salary Circle, Hyderabad.	
6. Niz-amabad.	
1. Circle-II (Old), Hyderabad.	B-Range, Hyderabad.
2. Circle-II, Hyderabad.	
3. Special Circle, Hyderabad.	
4. Central Circle Hyderabad.	
5. Nirmal.	
6. Central Circle (Old), Hyderabad.	
7. Sangareddy.	
1. Circle-I, Hyderabad.	C-Range, Hyderabad.
2. Kothagudem.	
3. Project Circle, Hyderabad.	
4. Warangal Circle.	
5. M.P.P. Circle, Hyderabad.	
6. Karimnagar.	
7. Khammam.	

Where an Income-tax Circle, Ward, or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from which the Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date of this Notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1st May, 1971.

Explanatory Note:

The amendments have become necessary on account of the re-allocation of jurisdiction of the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax in the charges of Andhra Pradesh I & II.

(This note does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 140(F. No. 261/11/71-ITJ).]

एस० नो० 2831.--धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं० 85 (फा० सं० 261/17/70-आई० टी० जे०) तारीख 20-5-70 और 17 (फा० सं० 39/1/67-ई० डी०) तारीख 27-2-69 के उपांतरण में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि सम्पदा शुल्क अपील नियंत्रक, हैदराबाद की हैसियत में नियुक्त सहायक आयुक्त (अपील) सम्पदा शुल्क आयुक्त अपील नियंत्रक के कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित स्तम्भ 1 में आय-कर सफिलों बाडों और जिलों में आयकर से भिन्न प्रत्यक्ष करों, अर्थात्, दान-कर, धन कर और व्यय-कर के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों की बाबत सहायक आयुक्त (अपील) के कृत्यों का पालन करेगा, जिन्हें स्तम्भ 2 में दिए गए सहायक आयुक्त अपील अब से नहीं करेंगे :

अनुसूची

आयकर सफिल, बाड, जिला	ए० ए० सी० की रेंज
1	2
1 सफिल-III, हैदराबाद	क-रेंज, हैदराबाद,
2 कम्पनी सफिल, हैदराबाद	

1

2

- | | |
|------------------------------------------------|------------------|
| 3 सिकन्दराबाद सर्किल का कम्पनी वार्ड, हैदराबाद | |
| 4 कम्पनी सर्किल (पुराना) हैदराबाद | |
| 5 बेतन सर्किल, हैदराबाद | |
| 6 निजामाबाद | |
| 1 सर्किल-II (पुराना) हैदराबाद | ख-रेंज, हैदराबाद |
| 2 सर्किल-II. हैदराबाद | |
| 3 विशेष सर्किल, हैदराबाद | |
| 4 केन्द्रीय सर्किल, हैदराबाद | |
| 5 निर्मल | |
| 6 केन्द्रीय सर्किल, (पुराना) हैदराबाद | |
| 7 संगरेड्डी | |
| 1 सर्किल-I, हैदराबाद | ग-रेंज, हैदराबाद |
| 2 कोठागुडम | |
| 3 परियोजना सर्किल, हैदराबाद | |
| 4 वारंगल सर्किल | |
| 5 एम० पी० पी० सर्किल, हैदराबाद | |
| 6 करीमनगर | |
| 7 खमाम | |

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरी रेंज को अन्तरित हो गया हो वहां उस आय-कर सर्किल, वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें, जो इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थीं, इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के, जिसको उक्त सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दी जाएंगी जो उनके संबंध में कार्यवाही करेगा।

यह अधिसूचना प्रथम मई, 1971 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण :

ये संशोधन आन्ध्र प्रदेश I और II के भार साधनों में सहायक आयकर आयुक्तों (अपील) की अधिकारिता के पुनः आवंटन के कारण आवश्यक हुए हैं।

(यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है बल्कि इसका आशय स्पष्टीकरण मात्र है)

[सं० 140 (फा० सं० 261/11/71-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 7th May 1971

S.O. 2832.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following

amendment in the Schedule appended to its Notification No. 201 (No. 261/4/70-ITJ) dated the 30th December, 1970:—

In the said Schedule the existing entry at Item I under column 2 against, D-Range, New Delhi shall be substituted by the following:—

"1. District III (10), (11), (12), (12) Addl., (13), (14),
14 Addl., (15) (16), 16 Addl., (17) & (18), New Delhi."

2. This notification shall take effect from 7th May, 1971.

Explanatory Note:

This amendment has become necessary on account of creation of a new Income-tax District known as 'District III (16) Addl., New Delhi.

(The above note does not form part of notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 141 (F. No. 261/14/71-ITJ)]

नई दिल्ली, 7 मई 1971

एस०ओ० 2832.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे उस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 201 (फा० सं० 261/4/70 आई० टी० जे०) तारीख 30 दिसम्बर, 1970 से उपाबद्ध अनुसूची में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करत है, अर्थात:—

उक्त अनुसूची में धा-रेंज नई दिल्ली के सामने स्तम्भ 2 के अधीन मद 1 पर विद्यमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"1 जिला III (10), (11), (12) अतिरिक्त, (13), (14), (14) अतिरिक्त, (15) (16), (16) अतिरिक्त (17) और (18), नई दिल्ली।"

यह अधिसूचना 7-5-1971 को प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण

यह संशोधन "जिला III (16) अतिरिक्त नई दिल्ली नामित नए आयकर जिला की सृष्टि के कारण आवश्यक हुआ है।

(उपरोक्त टिप्पण इस अधिसूचना का भाग नहीं है बल्कि इस का आशय स्पष्टीकरण मात्र है)।

[सं० 141 (फा० सं० 261/14/71-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 17th May 1971

S.O. 2833.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf and in partial modification of Board's order No. 193 (F. No. 261/19/70-ITJ) dated 5th December, 1970, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column 1 of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax or super-tax in the Income-tax circles/Wards and Districts specified in the corresponding entry in column 2 thereof:—

SCHEDULED

Range (1)	Income-Tax Circle, Wards and Districts (2)
C-Range, Ahmedabad.	1. Circle-I, Wards-A, B, C, D, E, F, and K.
E-Range, Ahmedabad,	1. Circle-VI, Ahmedabad. 2. Circle-I. Wards-G, H, I, J, L' M and N.

Where an Income-tax Circle, Ward and District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall, from the date this notification shall take effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1st May, 1971.

Explanatory Note:

The amendments have become necessary on account of reallocation of workload amongst above-mentioned Appellate Assistant Commissioners in the Commissioner's charge.

(This note does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 149 (F. 261/15/71-ITJ).]

नई दिल्ली, 17 मई 1971

एस० नो० 2833.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बोर्ड के आदेश सं० 193 (फा० सं० 261/19/70-आई० टी० जे०) तारीख 5-12-1970 में आंशिक उपांतरण करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा यह निर्देश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के आयकर सहायक आयुक्त (अपील), उसके स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर सफिल/वार्ड और जिले में आयकर या अधिकार से निर्धारित सभी व्यक्तियों और कार्यों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे।

अनुसूची

रेंज	आयकर सफिल, वार्ड और जिले
(1)	(2)
ग-रेंज, अहमदाबाद	1-सफिल-I, वार्ड-क, ख, ग, घ, ङ, च और ट
घ-रेंज, अहमदाबाद	1-सफिल-VI अहमदाबाद
	2-सफिल-I वार्ड, छ, ज, झ, ञ, ट, ड और ठ

जहां कोई आयकर सफिल वार्ड और जिला या उसका भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो जाते हैं वहां उस आयकर सफिल, वार्ड या जिले या उसके भाग में किए गए निर्धारणों से उद्भूत और उस रेंज के जिससे वह आयकर सफिल वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित किया गया है सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख से तुरंत पूर्व लंबित अपीलें इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से, उस रेंज के, जिसे उक्त सफिल/वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तरित होगी और वही उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

यह अधिसूचना 1-6-1971 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण

ये संशोधन, आयुक्त के भार साधन में के उपरिबर्णित सहायक आयुक्तों (अपील) को कार्य-भार के पुनः आवंटन के कारण आवश्यक हो गए हैं (उपयुक्त टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है, किन्तु केवल स्पष्टीकारक रूप में आशयित है)।

[सं० 149 (फ० 261/15/71-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 8th June 1971

S.O. 2834.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following amendment in the Schedule appended to its notification No. 3 (F. No. 261/8/70-ITJ) dated 6th January, 1971, namely:—

Against Poona Range I, Poona—15 Collection III, Poona.

Against Thana Range, Thana—27 Collection, Sholapur.

This notification shall take effect from 10th June, 1971.

Explanatory Note:

The amendment has become necessary on account of creation of new circles, namely Collection III, Poona, and Collection, Sholapur in the Commissioner's charge.

(This note does not form part of the notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 176 (No. 261/16/71-ITJ.)]

नई दिल्ली, 8 जून 1971

एस० ओ० 2834.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 3 फा० सं० 261/8/70 आई टी जे) तारीख 6-1-71 से उपाबद्ध अनुसूची में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातः—

पूना रेंज 1, पूना के सामने, 15 संग्रहण III, पूना थाना रेंज, थाने के सामने, 27, संग्रहण, शोलापुर

यह अधिसूचना 10-6-71 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकारक टिप्पण

यह संशोधन आयुक्त के भार साधन में संग्रहण, III पूना और संग्रहण, शोलापुर नामक नए सर्किलों के बनाए जाने के कारण आवश्यक हो गया है (यह टिप्पण अधिसूचना का भाग नहीं है किन्तु केवल स्पष्टीकारक के रूप में आशयित है)

[सं० 176 (सं० 261/16/71 आई० टी० जे०)]

CORRIGENDA

New Delhi, the 22nd April 1971

S.O. 2835.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the following correction shall be made in its Notification No. 113 (F. No. 261/7/71-ITJ) dated the 13th April, 1971:

In the last line of the Notification after the words "from" for '15-4-1971' read '1-5-1971'.

[No. 127 (F. No. 261/7/71-ITJ.)]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 अप्रैल 1971

एस०ओ० 2853.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे उस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 113 (फा० सं० 261/7/71-आई० टी० जे०) तारीख 13 अप्रैल, 1971 में निम्नलिखित शुद्धि की जाएगी :

अधिसूचना की अन्तिम लाइन में "से" शब्द के पश्चात् '15-4-1971' के लिए '1-5-1971' पढ़िए।

[सं० 127 (फा० सं० 261/7/71-आई० टी० जे०)]

New Delhi, the 5th June 1971

S.O. 2836.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that the following correction shall be made in its Notification No. 127 (F. No. 261/7/71-ITJ), dated 22nd April, 1971:

In the last line of the Notification, for '1-5-71' read '22-5-71'.

[No. 171 (F. 261/7/71-ITJ).]

C. V. GUPTE, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 जून 1971

एस०ओ० 2836.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी अधिसूचना सं० 127 (फा० सं० 261/7/71-आई० टी० जे०) तारीख 22 अप्रैल, 1971 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

अधिसूचना की अन्तिम लाइन में '1-5-71' को '22-5-71' पढ़े

[सं० 171 (फा० सं० 261/7/71-आई० टी० जे०)]

सी० वी० गुप्ते, अव्वर सचिव।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 28th June 1971

S.O. 2837.—In pursuance of sub-section (3) of section 4 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966), read with paragraph 44 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S. O. 1760, dated the 17th April, 1971, the Central Government hereby directs

that accumulations out of provident fund contributions, interest and other receipts as reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the following pattern, namely:—

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (i) in Central Government securities | .. Not less than 45%. |
| (ii) in State Government securities, the securities guaranteed by the Central Government or the State Governments, in the tax-free Small Savings securities and in the 1-year, 3-year and 5-year Time Deposits in Post Offices. | .. Balance. |

2. All re-investment of provident fund accumulations (whether invested in securities created and issued by the Central Government or in savings certificates issued by the Central Government or in securities created and issued by a State Government) shall also be made according to the pattern mentioned in the first paragraph.

3. The above pattern shall be in force for the period from the 1st day of April, 1971 to the 31st day of March, 1972.

4. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1971.

[No. 5-MT(7)/70.]

नीवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नयी दिल्ली, 28 जून, 1971

एस० ओ० 2837—नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के साथ पठित नाविक निर्वाह निधि अधिनियम 1966 (1966 का 4) की धारा 4 की उप-धारा (3) के अनुसरण में और भारत सरकार के नीवहन तथा परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सं० आ० 1760 दिनांक 17 अप्रैल, 1971 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है निर्वाह निधि अंशदानों, व्याज और अन्य आय की संचित राशि में, जिस में से अनिवार्य वहिर्गामी राशियों को कम कर दिया गया है, को निम्नलिखित ढंग से लगाया जायेगा, अर्थात् :—

- (1) केन्द्रीय सरकार की सेक्युरिटीज में 50 प्रतिशत ।
- (2) राज्य सरकारों की सेक्युरिटीज में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों शेष ।
द्वारा गारंटी शुद्ध सेक्युरिटीज, कारमुक्त अल्प बचत सेक्युरिटीज में और
डाकघरों के एक वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष की सावधि जमा में ।

2. निर्वाह निधि संस्थानों के सभी पुनर्निवेश (चाहे वे केन्द्रीय सरकार द्वारा सृजित और जारी की गयी सेक्युरिटीज अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये बचत प्रमाण-पत्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी की गई सेक्युरिटीज में लगाये गये हों) भी प्रथम पैराग्राफ में दिये गये ढंग के अनुसार किये जायेंगे ।

3. निवेश का उपर्युक्त ढंग 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि के लिये लागू होगा ।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1971 से लागू हुई समझी जायेगी ।

[सं० 5-एम० टी० (7)/70]

(MERCHANT SHIPPING)

New Delhi, the 6th July 1971

S.O. 2838.—In pursuance of clause (v) of rule 5 of the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Office, Bombay) Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Communications (Department of Transport) No. S.R.O. 1407, dated the 30th June, 1958, namely:—

In the said notification, in paragraph 7, for the words "six members of the Board are present", the words and brackets "six members, in the case of the Seamen's Employment Board (Foreign-going) or four members, in the case of the Seamen's Employment Board (Home Trade), are present" shall be substituted.

[No. 15-MT(1)/71.]

व्यापार पोत

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1971

एस० ओ० 2838.—भारतीय व्यापार पोत (नाविक रोजगार कार्यालय, बंबई) नियम, 1954 के नियम 5 के खंड (5) का अनुसरण करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन तथा संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1407, दिनांक 30 जून, 1958 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 7 में "बोर्ड के छह सदस्य उपस्थित हों" शब्दों के स्थान में "नाविक रोजगार बोर्ड (विदेशगामी) के मामले में छह सदस्य अथवा नाविक रोजगार बोर्ड (स्वदेश-व्यापार) के मामले में चार सदस्य, उपस्थित हों" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं 15-एम०टी (1)/71]

S.O. 2839.—In pursuance of clause (v) of rule 5 of the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Office, Calcutta) Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Communications (Department of Transport) No. S.R.O. 1408, dated the 30th June, 1958, namely:—

In the said notification, in paragraph 7, for the words "six members of the Board are present", the words and brackets "six members, in the case of the Seamen's Employment Board (Foreign-going), or four members, in the case of the Seamen's Employment Board (Home Trade), are present" shall be substituted.

[No. 15-MT(1)/71.]

HARBANS SINGH, Dy. Secy.

एस० ओ० 2839.—भारतीय व्यापार पोत (नाविक रोजगार कार्यालय) नियम, 1954 के नियम 5 के खंड (5) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन तथा संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1408, दिनांक 30 जून, 1958 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 7 में "बोर्ड के छह सदस्य उपस्थित हों" शब्दों के स्थान में "नाविक रोजगार बोर्ड (विदेशगामी) के मामले में छह सदस्य अथवा नाविक रोजगार बोर्ड (स्वदेश-व्यापार) के मामले में चार सदस्य उपस्थित हों" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[15-एम०टी० (1) 71]

हरबन्स सिंह, उप-सचिव।

(Transport Wing)

New Delhi, the 8th July 1971

S.O. 2840.—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Calcutta Port Act, 1890 (Bengal Act III of 1890), the Central Government is pleased to authorise the Commissioners for the Port of Calcutta to raise on the 1st July, 1971 a debenture loan of Rs. 150 lakhs (Rupees one hundred and fifty lakhs) repayable on the 1st July, 1981.

[No. 9-PG(54)/71.]

K. L. GUPTA, Under Secy.

(परिवहन रुकंध)

नयाँ दिल्ली, 8 जुलाई, 1971

एस० ओ० 2840.—कलकत्ता पत्तन अधिनियम, 1890 (1890 का बंगाल अधिनियम 3) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों को, प्रथम जुलाई, 1971 को 150 लाख रुपये (एक सौ पचास लाख रुपये) का डिबेंचर उधार लेने के लिये प्राधिकृत करती है, जो प्रथम जुलाई 1981 का प्रतिसंदेव होगा।

[9-पी०जी० (54)/71]

के० एल० गुप्ता, अवसर सचिव।

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 3rd July 1971

S.O. 2841.—In exercise of the powers conferred by Clause (c) of sub-section (2) of Section 5 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby directs that in the notification of the Government of India in the late Ministry of Education No. F. 9-47/66-U2, dated the 30th December, 1966 in the first paragraph, the words and figures "and until 5-7-1971" shall be omitted and shall be deemed always to have been omitted.

2. Under sub-section (3) of section 5 of the University Grants Commission Act, 1956, aforesaid, read with rule 5(ii) of the University Grants Commission (Disqualification, Retirement and Conditions of Service of Members) Rules, 1956, and in pursuance of the contract entered into with Dr. D. S. Kothari, the Central Government hereby notifies that the said Dr. Kothari shall hold office as Chairman for a further period beyond the 5th July, 1971 up to and including the 13th January, 1973.

[No. F. 9-59/70-U. 2.]

T. P. SINGH, Secy.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1971

एस० ओ० 2841.—विश्व विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में अधिकार प्रदान करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा मंत्रालय की अधिशुल्का संख्या एक० 9-47/66 यू० 2 दिनांक 30 दिसम्बर, 1966 के पहले वेरे में लिखे गये शब्द तथा अंक "और 5-7-1971 तक" हटा दिये जायेंगे और ये सदैव हटाये गये समझे जायेंगे।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अयोग्यता, निवृत्ति और सेवा की शर्तों) नियम 1956 के नियम 5 (iii) के साथ उपरोक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन तथा डा० डी० एस० कोठारी के साथ किये गये

अनुबन्ध के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि पूर्वोक्त डा० कोठारी अध्यक्ष के रूप में इस पद पर 5 जुलाई, 1971 से आगे 13 जनवरी 1973 समेत तक की अवधि पर्यन्त आसीन रहेंगे।

[रं० एरु०-9-59/70-यू० 2.]

टी० पी० सिंह, सचिव।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 30th June, 1971

S.O. 2842.—Whereas certain draft rules further to amend the Coriander Grading and Marking Rules, 1964 were published as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), at pages 4881-4882 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 24th October, 1970, with the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, (Department of Agriculture), No. S.O. 3468, dated the 5th October, 1970, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the 10th November, 1970;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 24th October, 1970;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act the Central Government hereby makes the following rules namely:—

Rules

1. These rules may be called the Coriander Grading and Marking (Amendment) Rules, 1971.

2. In the Coriander Grading and Marking Rules 1964, for Schedule II, the following Schedules shall be substituted namely:—

SCHEDULE II

(See rules 3 and 4)

Grade, designations and definition of quality of coriander seeds (Dhania)

Grade Designations	Special Characteristics				General Characteristics	
	Extraneous matter (percentage by weight maximum).	Split seeds (percentage by weight maximum).	Damaged, blackened and insect-bored seeds (percentage by weight maximum).	Shrivelled and immature seeds (percentage by weight maximum).	Moisture (percentage by weight maximum).	
1	2	3	4	5	6	7
Special . . .	1.5	10.0	1.0	1.0	10.0	Coriander seeds shall :— (a) be the dried mature fruits of the plant botanically known as (<i>coriandrum sativum</i> L.); (b) be free from visible mould, live insects, any harmful foreign matter and musty odour;
Good . . .	3.0	15.0	2.0	2.0	10.0	
Fair . . .	7.0	30.0	4.0	3.0	10.0	
X	7.0	As agreed to between the buyer and seller in the firm order.	4.0	3.0	10.0	

1	2	3	4	5	6	7
					(c) generally conform to the characteristic size, shape, taste, colour and aroma of the variety/type.	

Definitions:—

1. "Extraneous matter" dust, dirt, stones, earth, chaff, stalks, stems, straw or any other foreign matter.
2. "Split seeds" are those fruits which have split longitudinally.
3. "Damaged and blackened seeds" are those fruits or split fruits which are damaged or blackened materially affecting the quality.
4. "Insect bored seeds" are those fruits or split fruits which are partially or wholly bored or eaten by weevils or other insects.
5. "Shrivelled and immature seeds" are those fruits which are not properly developed.

[No. F. 13-8/70-C&M.]

K. RAJAN, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 30 जून, 1971

का० आ० 2842.—यतः कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिह्न) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की अपेक्षा अनुसार धनिया श्रेणीकरण और चिह्न नियम, 1964 में आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रादुर्भाव भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (ii) तारीख 24 अक्तूबर 1970 के पृष्ठ 4883 और 4884 पर भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3468, तारीख 5 अक्तूबर, 1970 के साथ प्रकाशित किया गया था जिसमें 10 नवम्बर 1970 तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गये थे जिनका एतद् द्वारा प्रभावित संभाव्य होना था।

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 24 अक्तूबर 1970 को उपलब्ध करा दिया गया था।

और यतः जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम धनिया श्रेणीकरण और चिह्न (संशोधन) नियम, 1971 होगा।
2. धनिया श्रेणीकरण और चिह्न नियम, 1964 की अनुसूची 2 के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची
(नियम 3 और 4 देखिए)
घनिए के बीच (घनिया) का श्रेणी अभियान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा
विशेष लक्षण

श्रेणी अभियान	वाह्य पदार्थ (भार के आधार पर प्रतिशत, अधिकतम)	खंडित बीज (भार के आधार पर प्रतिशत, अधिकतम)	क्षतिग्रस्त काले पड़े और कीट द्वारा छेदे गये बीज (भार के आधार पर प्रति- शतत, अधिकतम)	सिकड़े हुए और अपरिपक्व बीज (भार के आधार पर प्रतिशत, अधिकतम)	नमी (भार के आधार पर प्रतिशत, अधिकतम)	साधारण लक्षण
1	2	3	4	5	6	7
विशेष						
अच्छी	1.5	10.0	1.0	1.0	10.0	
साधारण	3.0	15.0	2.0	2.0	10.0	
	7.0	30.0	4.0	3.0	10.0	
	7.0	फर्म के आर्डर से क्रेता और विक्रेता के बीच जैसा करार हुआ हो उसके अनुसार	4.0	3.0	10.0	घनिया-बीज—सेटीवाम एल के नाम (क) वनस्पति शास्त्र में कोरिन्डम से ज्ञात पौधे के मूल्लहुए, परिपक्व फल होंगे ; (ख) द्रश्यामान फफूंदी, जीवित कीट, किसी हानिकर विजातीय पदार्थ और दुर्गन्ध से मुक्त होंगे । (ग) साधारणतः किस्म 1 प्रकार के लक्षण सूचक आकार, भाप, स्वाद, रंग और सुवास के अनुरूप होंगे ।

परिभाषाएं :—

1. 'वाह्य पदार्थ' से धूल, कंकरी, पत्थर, मिट्टी, भूमी, वृक्ष, तने, तिनके या कोई अन्य विजातीय पदार्थ अभिप्रेत हैं।
2. 'खण्डित-बीज' वे फल होते हैं जो लम्बान में खण्डित हों।
3. "क्षतिग्रस्त और काले पड़े बीज" वे फल या खण्डित फल होते हैं जो ऐसे क्षतिग्रस्त या काले पड़े हुए हों कि उनकी क्वालिटी पर तात्त्विक प्रभाव पड़ता हो।
4. "कीट द्वारा छेदे गये बीज" वे फल या खण्डित फल होते हैं जो अंशतः या पूर्णतः वृक्ष या अन्य कीटों द्वारा छेदे या खाये गये हों।
5. "सिकुड़े हुए और अपरिपक्व बीज" वे फल होते हैं जो अच्छी तरह से विकसित न हुए हों।

[सं० फा० 13-8/70-सी०एम०]

के० राजन, अवर सचिव।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 6th July 1971

S.O. 2843.—In exercise of the powers conferred by section 68 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the posts mentioned in column 2 of the Table below as equivalent to the posts mentioned in the corresponding entry in column 1 of the said Table.

THE TABLE

Posts and ranks in the Police	Posts and ranks in the Border Security Force
1	2
1. Confirmed Deputy Superintendent of Police	Confirmed Assistant Commandant.
2. Assistant Superintendent of Police/Deputy Superin- tendent of Police	Assistant Commandant.

[No. 10/1/69-CLO/BSF/GPA.1.]

P. P. KHANNA, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1971

का० प्रा० 2843.—सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारिणी के स्तम्भ 2 में वर्णित पदों को उक्त सारिणी के स्तम्भ 1 की सत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित पदों के समतुल्य एवम् द्वारा घोषित करती है।

सारणी

पुलिस के पद और पंक्तियां	सीमा सुरक्षा बल के पद और पंक्तियां
(1)	(2)
1 पुष्ट पुलिस उपाधीक्षक	पुष्ट सहायक कमांडेन्ट
2 पुलिस सहायक अधीक्षक/ पुलिस उपाधीक्षक	सहायक कमांडेन्ट

[संख्या 10/1/69-सीएनओ/बीएसएफ/जीपीए-1]

पी० पी० खन्ना, उप-सचिव।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 3rd July 1971

S.O. 2844.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Terminal Tax on Railway Passengers Act, 1956 (69 of 1956) and of all the powers hereunto enabling and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) No. F (X)I-65/TX-19/8-B, dated the 11th April, 1968 the Central Government hereby—

(a) fixes the rates specified in column (2) of the Schedule annexed hereto as the rates at which terminal tax shall be levied in respect of every railway ticket on all passengers carried by railway to the notified place specified in column (1) of the said Schedule; and

(b) directs that the aforesaid terminal tax shall be leviable with effect from the 1st August, 1971.

2. This notification shall come into force on the 1st August, 1971.

THE SCHEDULE

Name of notified place	Rates of terminal tax per single ticket			
1	2		3	
	ADULT		Child between 3 & 12 years of age	
	For short distance passengers (Beyond 16 Kms and upto 240 Kms)	For long distance passengers (Beyond 240 Kms).	For short distance passengers (Beyond 16 Kms and upto 240 Kms)	For long distance passengers (Beyond 240 Kms).
	Paise	Paise	Paise	Paise
Rishikesh				
Air Cond. & Ist classes	40	70	20	35
Air Cond. chair Car	40	70	20	35
II Class	30	40	15	20
III Class	15	20	10	10

Explanation:—The terminal Tax on a return ticket shall be the same as fixed herein.

[No. F(X)I-71/TX-19/1.]

V. P. SAWHNEY, Secy., Rly. Board

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नयी दिल्ली, 3 जुलाई, 1971

का०प्रा० 2844.—रेल यात्रियों पर सीमाकर अधिनियम, 1956 (1956 का 69) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा अब तक समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की 11 अप्रैल, 1968 की धिसूचना सं० एफ (एक्स) 1-65/टी० एक्स०-19/8-बी का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा —

(क) इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (3) में निर्दिष्ट दरें निश्चित करती है । इन्हीं दरों के अनुसार उक्त अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचित स्थान सं/ तक रेलवे द्वारा ले जाये जाने वाले सभी यात्रियों के प्रत्येक रेलवे टिकट पर सीमाकर लगाया जायेगा ; और

(ख) यह निदेश देती है कि उपर्युक्त सीमाकर 1 अगस्त, 1971 से उद्ब्राह्म होगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1971 से लागू होगी ।

अनुसूची

अधिसूचित

प्रति एकहरे टिकट पर सीमाकर की दरें

जगह का नाम

1	2			
	वयस्क		3 और 12 वर्ष के बीच का बच्चा	
1. अधिक्षेप	थोड़ी दूरी के यात्रियों के लिए (16 किलोमीटर से आगे और 240 किलोमीटर तक)	लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए (240 किलोमीटर से आगे)	थोड़ी दूरी के यात्रियों के लिए (16 किलोमीटर से आगे और 240 किलोमीटर तक)	लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए (240 किलोमीटर से आगे)
	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे
वातानुकूल और प्रथम श्रेणिया	40	70	20	35
वातानुकूल कुर्सी यान	40	70	20	35
द्वितीय श्रेणी	30	40	15	20
तृतीय श्रेणी	15	20	10	10

टिप्पणी : वातानु टिकट पर सीमाकर उतना ही लगेगा, जितना इस अनुसूची में निर्धारित है ।

[सं० एफ (एक्स) 1-71/टी० एक्स०-19/1]

वेद प्रकाश साहनी, सचिव, रेलवे बोर्ड ।